सूर्योदय 05:24 AM सूर्यास्त 07:16 PM

हिन्दी दैनिक

दिल्ली वार्ता

दिल्ली से प्रकाशित एवं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, बिहार, बंगाल में प्रसारित।

facebook.com/delhivartanews x.com/delhivartanews instagram/vartanews

वर्ष 20 | अंक : 122 | नई दिल्ली, बुधवार, 03 जून 2026 | RNI No :- DELHIN/2008/23199 | पृष्ठ - 08, मूल्य ₹ 2, | www.delhivarta.com

एक नजर...

नेपाल सीमा विवाद में किसी तीसरे पक्ष की भूमिका नहीं: भारत

नई दिल्ली। नेपाल के साथ सीमा विवाद को सुलझाने में किसी भी तीसरे पक्ष की भागीदारी को भारत ने मंगलवार को खारिज कर दिया, जबकि कुछ ही दिन पहले ऐसी खबरें आई थीं कि नेपाली प्रधानमंत्री बलेंद्र शाह ने इस लंबे समय से चले आ रहे मुद्दे को सुलझाने के लिए चीन और यूनाइटेड किंगडम की भागीदारी मांगी थी। नेपाल के प्रधानमंत्री बलेंद्र शाह की 'भारत अतिक्रमण' वाली टिप्पणी के संबंध में मीडिया के एक प्रश्न का उत्तर देते हुए विदेश मंत्री के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सभी संबंधित पक्षों को यह स्पष्ट होना चाहिए कि भारत और नेपाल के बीच द्विपक्षीय मामलों का समाधान केवल दोनों देशों के बीच ही होना चाहिए और ऐसे मामलों में किसी तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है।

उन्होंने आगे कहा कि भारत-नेपाल सीमा का लगभग 98 प्रतिशत हिस्सा पहले ही सीमांकित हो चुका है, हालांकि कुछ हिस्सों में कुछ मुद्दे अभी भी अनसुलझे हैं। उन्होंने कहा कि भारत-नेपाल सीमा का लगभग 98 प्रतिशत हिस्सा पहले ही निर्धारित किया जा चुका है। हालांकि, कुछ हिस्सों में कुछ मुद्दे अनसुलझे रह गए हैं। गंडक नदी के मार्ग में परिवर्तन के कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई है। जायसवाल ने आगे कहा कि इसके अलावा, कुछ सीमांकित क्षेत्रों में सीमा पार अतिक्रमण और नो-मैन्स लैंड पर अतिक्रमण के मामले हैं, जिनका संयुक्त रूप से मानचित्रण किया जा रहा है।

जायसवाल की ये टिप्पणी रैपर से राजनेता बने शाह के रविवार के उस बयान के बाद आई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि लिपुलेख दर्रे के सीमा विवाद पर भारत के साथ चर्चा के अलावा नेपाल चीन और ब्रिटेन के भी संपर्क में है। उन्होंने कहा कि चूंकि यह समस्या उस समय से चली आ रही है जब ब्रिटिश भारत ने इस क्षेत्र को छोड़ा था, इसलिए हमारा मानना है कि इस मामले में इंग्लैंड को भी शामिल किया जाना चाहिए।

शाह ने संसद के मौजूदा सत्र में अपनी पहली उपस्थिति के दौरान कहा कि आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि मुझे यह तथ्य प्रधानमंत्री बनने के बाद ही पता चला। केवल भारत ने ही नेपाली क्षेत्र पर अतिक्रमण नहीं किया है, बल्कि नेपाल ने भी कई स्थानों पर भारतीय क्षेत्र पर अतिक्रमण किया है। नेपाल और भारत के बीच लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और कालापानी को लेकर पुराना सीमा विवाद है। भारत लगातार यह दावा करता रहा है कि ये क्षेत्र उत्तराखंड का हिस्सा हैं।

इबोला पर स्वास्थ्य मंत्रालय की एडवाइजरी

नई दिल्ली। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने मंगलवार को इबोला प्रभावित देशों से आने वाले यात्रियों के लिए एहतियाती सलाह जारी की है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि भारत में अब तक इबोला का कोई भी एक्टिव मामला सामने नहीं आया है, लेकिन अफ्रीका के कुछ हिस्सों में बीमारी के लगातार फैलने के मद्देनजर निगरानी और तैयारियां मजबूत कर दी गई हैं।

मंत्रालय ने उन सभी लोगों से अपील की है जिन्होंने पिछले 21 दिनों के भीतर किसी इबोला प्रभावित देश की यात्रा की है या वहां से गुजरे हैं। यदि बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, उल्टी, दस्त या बिना किसी वजह से खून बहने जैसे लक्षण दिखें तो तुरंत खुद को आइसोलेट कर लें और स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों को सूचित करें। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, 'जल्द रिपोर्ट करने से जान बचाई जा सकती हैं और बीमारी के फैलने को रोका जा सकता है।' विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, इबोला के लक्षण अचानक शुरू हो सकते हैं।

इनमें बुखार, थकान, बेचैनी, मांसपेशियों में दर्द, सिरदर्द और गले में खराश प्रमुख हैं। बाद में उल्टी, दस्त, पेट दर्द, चकत्ते और लीवर-किडनी संबंधी परेशानी हो सकती हैं। खून बहना आम लक्षण नहीं है और यह बीमारी के अंतिम चरण में दिख सकता है।

» शेष पेज 7 पर

मोदी सरकार का बड़ा एक्शन

ओएसएम विवाद के बाद सीबीएसई चेयरमैन और सेक्रेटरी को हटाया, जांच के लिए बनाई कमेटी

• नई दिल्ली, एजेंसी

केंद्र सरकार ने ओएसएम विवाद के मद्देनजर सीबीएसई के अध्यक्ष राहुल सिंह और सचिव हिमांशु गुप्ता का तबादला कर दिया है। सीबीएसई द्वारा ऑन-स्क्रीन मार्किंग (ओएसएम) सेवाओं की खरीद की जांच के लिए एक जांच समिति का गठन किया गया है। छात्रों के भविष्य और परीक्षा व्यवस्था की शुचिता को ध्यान में रखते हुए इसे सीबीएसई के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई माना जा रहा है।

इसी बीच, सीबीएसई ने मंगलवार को छात्रों के लिए ऑनलाइन री-इवैल्यूएशन और उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन प्रतियों में समस्याओं के सत्यापन का पोर्टल शुरू कर दिया है। यह सुविधा केवल उन छात्रों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी स्कैन की गई उत्तर पुस्तिकाएं प्राप्त कर ली हैं। पोर्टल 2 जून 2026 से 6 जून 2026 (मध्यरात्रि तक) चालू रहेगा। इसके बाद कोई भी ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। छात्रों को सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट पर आधार नंबर के माध्यम से लॉगिन करके ऑनलाइन आवेदन

करना होगा। पूरी प्रक्रिया, शुल्क भुगतान सहित, डिजिटल माध्यम से ही पूरी होगी।

सीबीएसई ने छात्रों से अपील की है कि वे अंतिम आवेदन सबमिट करने से पहले सभी विषयों से संबंधित अनुरोधों को शामिल कर लें। एक बार 'फ्रीज एंड प्रोसीड टू पेमेंट' बटन दबाने के बाद आवेदन लॉक हो जाएगा और उसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकेगा। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि छात्र एक विषय या एक साथ कई विषयों के लिए केवल एक आवेदन ही कर सकते हैं।

इससे पहले आज, सीबीएसई के पुनर्मूल्यांकन पोर्टल पर साइबर हमलों की झड़ी लग गई थी। सीबीएसई के अनुसार, पुनर्मूल्यांकन पोर्टल पर मात्र 2 मिनट में 15 लाख से अधिक हिट्स आए और अनधिकृत रूप से फ़ाइलों तक पहुँचने के 1 लाख से अधिक प्रयास किए गए, सीबीएसई के X पोस्ट में यह जानकारी दी गई है। आज दोपहर 3 बजे तक, 16,000 से अधिक छात्रों ने सफलतापूर्वक अपनी प्रविष्टियाँ जमा कर दी हैं, सीबीएसई ने X पोस्ट में यह जानकारी दी।

आज हजारों छात्रों ने सीबीएसई पुनर्मूल्यांकन पोर्टल का उपयोग किया, उसी दौरान दुर्भावनापूर्ण तत्वों ने साइबर हमलों की झड़ी लगाकर सेवाओं को बाधित करने का प्रयास किया। सबसे हालिया हमला 'डिनायल ऑफ सर्विस अटैक' था, जिसके कारण मात्र 2 मिनट में पोर्टल पर 15 लाख हिट्स आए और अनधिकृत रूप से फ़ाइलों तक पहुँचने के 1 लाख से अधिक प्रयास किए गए। सीबीएसई के X पोस्ट में यह जानकारी दी गई है। छात्रों की प्रतिक्रिया के बाद, बोर्ड ने प्रक्रिया को अधिक सुविधाजनक और सुचारू बनाने के लिए सत्र समय सीमा बढ़ाने सहित प्लेटफ़ॉर्म को और बेहतर बनाया है।

शिक्षा मंत्रालय ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) से बोर्ड की ऑन-स्क्रीन मार्किंग (ओएसएम) प्रणाली से जुड़े सेवा प्रदाता, सीओईएमपीटी को अनुबंध दिए जाने के संबंध में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। सूत्रों के अनुसार, मंत्रालय ने सीबीएसई से निविदा प्रक्रिया का पूरा विवरण प्रस्तुत करने को कहा है, जिसमें अनुबंध देने के दौरान अपनाई गई प्रक्रियाएं और निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल अधिकारियों के नाम शामिल हैं।

» शेष पेज 7 पर

चुनाव में धांधली का आरोप लगा बोली ममता-लड़ूंगी या मर जाऊंगी

• कोलकाता, एजेंसी

टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने मंगलवार को मध्य कोलकाता में भाजपा की हालिया विधानसभा चुनावों में जीत के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं पर कथित हमलों के विरोध में एक दिवसीय धरना शुरू किया। कोलकाता पुलिस द्वारा रानी रश्मोनी रोड पर विरोध प्रदर्शन करने की टीएमसी की अपील को ठुकराए जाने के बाद वह एस्प्लेनेड के वाई-चैनल स्थित धरना स्थल पर पहुंचीं। बनर्जी ने मेगाफोन से भीड़ को संबोधित करते हुए कहा कि हमें मंच लगाने या माइक्रोफोन इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दी गई।

पूर्व मुख्यमंत्री के भाषण के दौरान टीएमसी कार्यकर्ताओं द्वारा नारे लगाने से विरोध प्रदर्शन में अफरा-तफरी मच गई। ममता ने कोलकाता में कहा कि भाजपा ने बंगाल विधानसभा चुनाव जीतने के लिए 294 में से 177 सीटों पर मतगणना में धांधली की। उन्होंने दावा किया कि पुलिस टीएमसी कार्यकर्ताओं को प्रदर्शनों में भाग न लेने की धमकी दे रही है, मैं विरोध प्रदर्शन जारी रखूंगा। ममता ने कोलकाता में कहा कि पुनर्वास के बिना फेरीवालों को बेदखल करना टीएमसी सरकार की नीति नहीं थी,

हमने मानवीय दृष्टिकोण अपनाया। उन्होंने कहा कि मैं इन कठिन समय में टीएमसी कार्यकर्ताओं का साथ नहीं छोड़ूंगी।

ममता ने शुभेंदु अधिकारी की ओर इशारा करते हुए कहा कि मुझे इस बात का अफसोस है कि जिन लोगों को मैंने जीवन में सहारा दिया, वे अब गद्दार के साथ मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा विरोधी दल देशव्यापी कार्ययोजना पर निर्णय लेने के लिए दिल्ली में बैठक करेंगे। धरने वाली जगह पर उसने नारे लगाए, 'मैं लड़ूंगी या मर जाऊंगी।' हालांकि, पूर्व मुख्यमंत्री ने दावा किया कि निजी स्वार्थों के लिए पार्टी से नेताओं के अलग होने से संगठन के पुनर्निर्माण में मदद मिलेगी और टीएमसी इस संकट से और भी मजबूत होकर उभरेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि लोग क्यों डरे हुए हैं? लोग क्यों चिंतित हैं?

» शेष पेज 7 पर

एयरपोर्ट पर रील बनाना पड़ सकता है महंगा!

• नई दिल्ली, एजेंसी

अगर आप एयरपोर्ट पर ट्रैवल व्लॉग, रील या शॉर्ट बनाने के बारे में सोच रहे हैं, तो ऐसा करने से पहले आपको ये नियम जानने की जरूरत है। DGCA ने पूरे भारत में एयरपोर्ट के संवेदनशील इलाकों में बिना इजाजत फोटो और वीडियो बनाने के खिलाफ सख्त नियम लागू किए हैं।

यह कदम यात्रियों के बीच यात्रा के दौरान सोशल मीडिया कंटेंट बनाने के बढ़ते चलन को देखते हुए उठाया गया है। कई बार वे अनजाने में सुरक्षा से जुड़ी जानकारी भी रिकॉर्ड कर लेते हैं। नए दिशा-निर्देशों के तहत, नियम तोड़ने वाले यात्रियों पर जुर्माना लग सकता है, उनके डिवाइस जब्त किए जा सकते हैं और गंभीर मामलों में तो उन पर हवाई यात्रा करने पर भी रोक लगाई जा

सकती है।

DGCA ने क्या बदलाव किए?

उड्डयन नियामक ने यात्रियों और विजिटर्स के लिए एयरपोर्ट के कई प्रतिबंधित इलाकों में बिना पहले से इजाजत लिए फोटो या वीडियो बनाना मन कर दिया है। इनमें सुरक्षा जांच चौकियां, बोर्डिंग गेट, रवने बसें, विमान हैंडलिंग जोन, एयरपोर्ट एप्रन और अन्य संवेदनशील इलाके शामिल हैं। अधिकारियों का कहना है कि इसका मकसद सुरक्षा इंतजामों, निगरानी प्रणालियों

» शेष पेज 7 पर

मुलाकात

राष्ट्रपति भवन में मंगलवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करते दक्षिण अफ्रीका के उप राष्ट्रपति पॉल माशातिले।

फोटो साभार : पीआईबी

ट्विशा केसः पति समर्थ और रिटायर्ड सास 14 दिन की न्यायिक हिरासत में

• भोपाल, एजेंसी

भोपाल की एक अदालत ने पूर्व मॉडल ट्विशा शर्मा के पति समर्थ सिंह और उसकी सास गिरिबाला सिंह को दहेज उत्पीड़न के आरोप में सीबीआई (केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो) की हिरासत की अवधि पूरी होने के बाद मंगलवार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। त्विषा का शव 12 मई को भोपाल स्थित उसके ससुराल में फंदे से लटका मिला था।

ट्विशा के परिवार के वकील अंकुर पांडे ने बताया कि सीबीआई ने रिमांड अवधि पूरी होने के बाद समर्थ सिंह और उसकी मां एवं सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश गिरिबाला को शोभना भलावे की अदालत में पेश किया जिसने दोनों को 16 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इससे एक दिन पहले सोमवार को सीबीआई ने त्विषा शर्मा की मौत

की जांच के सिलसिले में डमी का इस्तेमाल करके उनके ससुराल स्थित घर में अपराध के दृश्य का नाट्य रूपांतरण (रीक्रिएशन) किया एवं कथित आत्महत्या की परिस्थितियों का अवलोकन किया था।

अधिकारियों ने कहा था कि फोरेंसिक और अपराध स्थल विशेषज्ञों के साथ सीबीआई समर्थ सिंह और गिरिबाला सिंह को घटनास्थल लेकर पहुंची और उनसे 12 मई की रात की घटना का विस्तृत ब्योरा देने को कहा है।

TMC से दागी नेताओं के लिए दरवाजे बंद, नहीं मिलेगी बीजेपी में एंट्री!

• कोलकाता, एजेंसी

पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य ने मंगलवार को कहा कि पार्टी तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के नेताओं को शामिल नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा ने अपना आधार जमीनी स्तर से बनाया है और वह दागी व्यक्तियों को शामिल नहीं करेगी।

उन्होंने जोर देकर कहा कि भाजपा का तृणमूलकरण कभी नहीं होगा। एएनआई से बात करते हुए भट्टाचार्य ने कहा कि टीएमसी के लिए हमारे दरवाजे बंद हैं। हमने बिना किसी बाहरी नेता को लाए 207 सीटें हासिल कीं। जनता ने टीएमसी के नेताओं के खिलाफ वोट दिया। इस बार हमारी राजनीतिक रणनीति निचले स्तर से शुरू हुई है। दागी लोगों को हम अपनी पार्टी में कैसे शामिल कर सकते हैं? भाजपा का तृणमूलकरण कभी नहीं होगा।

भट्टाचार्य ने पूर्व

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के कोलकाता में होने वाले विरोध प्रदर्शन की आलोचना करते हुए टीएमसी को खुद के खिलाफ बताया और कहा कि पश्चिम बंगाल की जनता ने पार्टी को नकार दिया है, जिसके चलते उनके लिए खेल खत्म हो गया है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल की जनता ममता बनर्जी को विरोध प्रदर्शन नहीं करने देगी। टीएमसी सड़कों पर उतरकर जनता का सामना करने की स्थिति में नहीं है।

भट्टाचार्य ने आगे कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री के अदालत जाने पर क्या हुआ, यह तो सभी जानते हैं। अब टीएमसी खुद टीएमसी के खिलाफ है। ममता बनर्जी दिल्ली की बात सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए कर रही हैं। वह दिल्ली आ सकती हैं, अंटार्कटिका जा सकती हैं या रेगिस्तान में जा सकती हैं। वह कुछ भी कर सकती हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल की जनता ने टीएमसी को नकार दिया है। खेल खत्म हो चुका है। ममता बनर्जी मंगलवार दोपहर को कोलकाता के रानी रश्मोनी रोड पर पार्टी नेताओं के खिलाफ कथित चुनावोत्तर हिंसा के विरोध में प्रदर्शन का नेतृत्व करेंगी। यह विरोध प्रदर्शन टीएमसी नेताओं अभिषेक बनर्जी और कल्याण बनर्जी पर दक्षिण 24 परगना और हुगली दौरे के दौरान हुए हमलों के बाद हो रहा है।

अभिषेक बनर्जी ने आरोप लगाया कि उन पर ईंटों, पत्थरों और अंडों से हमला किया गया, जिससे उनकी आंख में चोट आई, जबकि कल्याण बनर्जी ने दावा किया कि चांदीताला पुलिस स्टेशन के पास उन पर जानलेवा हमला हुआ, जिसमें वे बाल-बाल बचे।

घपलेबाजी

पीएम आवास योजना में कट मनी का खेल! TMC नेताओं ने बंगाल में लौटाए लाभार्थियों के पैसे

• कोलकाता, एजेंसी

पश्चिम बंगाल में भ्रष्टाचार से संबंधित जांच और गिरफ्तारियां लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं, ऐसे में जमीनी स्तर पर तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के नेताओं में चिंता के संकेत उभर रहे हैं।

दक्षिण 24 परगना से एक ताजा घटनाक्रम में, स्थानीय टीएमसी नेता को कथित तौर पर निवासियों को पैसे लौटाते हुए देखा गया है, क्योंकि आरोप सामने आए हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के लाभार्थियों से आवास लाभ दिलाने के बदले नकद भुगतान मांगा गया था। दक्षिण 24 परगना जिले के नामखाना से ताजा मामला सामने आया है। आरोपों के अनुसार, पीएम आवास योजना के तहत मकानों की मंजूरी में सुविधा के लिए लगभग 45 लाभार्थियों से 5,000 रुपये प्रति व्यक्ति मांगे गए थे। जनता की शिकायतों और भ्रष्टाचार के मामलों पर बढ़ते ध्यान के बाद, एक स्थानीय टीएमसी नेता को लाभार्थियों को पैसे लौटाते हुए देखा गया। पश्चिम बंगाल में, 'कट मनी' शब्द का प्रयोग आमतौर पर स्थानीय राजनीतिक कार्यकर्ताओं या मध्यस्थों द्वारा सरकारी कल्याणकारी योजनाओं और लाभों तक लोगों की पहुंच में मदद करने के बदले में कथित कमीशन या अनौपचारिक भुगतान का वर्णन करने के लिए किया जाता है।

कूच बिहार जिले में भी इसी तरह का विवाद चल रहा है, जहां ग्रामीणों ने धन

वापसी के वादे पूरे करवाने के लिए एक अनोखा तरीका अपनाया है।

गांववाले पूरे गांव में लाउडस्पीकर से घोषणाएं कर रहे हैं और स्थानीय टीएमसी नेता को पीएम आवास योजना के लाभार्थियों से कथित तौर पर वसूले गए 'कटौती' के पैसे वापस करने की प्रतिबद्धता की बार-बार याद दिला रहे हैं।

ये घोषणाएं घुघुमारी ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले सभी क्षेत्रों में की जा रही हैं और इसने प्रभावी रूप से गांव के सार्वजनिक संबोधन तंत्र को दैनिक जवाबदेही अभियान में बदल दिया है। विवाद तब शुरू हुआ जब ग्रामीणों ने टीएमसी पंचायत सदस्य ज्योत्सना बर्मन के आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया।

निवासियों का आरोप है कि लाभार्थियों को आवास लाभ प्राप्त करने या योजना के तहत भविष्य की किस्तों के भुगतान में देरी से बचने के लिए 5,000 रुपये से 25,000 रुपये तक का कमीशन देने के लिए मजबूर किया गया था। कई ग्रामीणों ने दावा किया कि उन्होंने यह पैसा इस डर से दिया कि अन्यथा उनके आवेदन या भुगतान में देरी हो सकती है।

स्थानीय सूत्रों के अनुसार, लाभार्थियों से एकत्र की गई पूरी धनराशि 4 जून तक वापस करने के आश्वासन के बाद विरोध प्रदर्शन अस्थायी रूप से रोक दिए गए थे। तब से, ग्रामीण स्थानीय नेताओं को समय सीमा याद दिलाने के लिए लगातार मार्च और लाउडस्पीकर अभियान चला रहे हैं।

निवासियों ने चेतावनी दी है कि यदि वादा की गई धनराशि समय पर वापस नहीं की गई, तो नए सिरे से विरोध प्रदर्शन शुरू किए जा सकते हैं। हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों के बाद यह मुद्दा और भी जोर पकड़ गया है, जिसमें भाजपा ने राज्य में टीएमसी के 15 साल के शासन को समाप्त कर दिया।

संक्षिप्त खबरें

अमर कालोनी हत्याकांड : छतरपुर लालबत्ती पर शव रख किया प्रदर्शन

नई दिल्ली। दक्षिण-पूर्वी जिला के अमर कॉलोनी में 26 मई को गोलिकांड में घायल साई कुमार की मौत के दूसरे दिन मंगलवार को शव पहुंचाया गया। परिवार आरोपितों के एनकाउंटर की मांग कर रहा है। क्राइम ब्रांच अब तक नाबालिग मुख्य आरोपित समेत तीन को पकड़ चुकी है। वहीं, एक नाबालिग अभी भी है फरार। वारदात से नाराज स्वजनों व स्थानीय लोगों ने छतरपुर लालबत्ती पर युवक का शव रखकर ने प्रदर्शन किया। वे आरोपियों को फांसी देने की मांग कर रहे हैं।

शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन कर रहे लोगों को पुलिस ने बहुत समझाने का प्रयास किया। हालांकि, वे अपनी मांग पर अड़े रहे। इस बीच सड़क पर काफी देर तक हंगामे की स्थिति बनी रही। बता दें कि दक्षिण-पूर्वी जिला के अमर कॉलोनी इलाके के एक रेस्तरां में युवती को घूरने का विरोध करने पर 17 साल किशोर के सिर में गोली मारने के मामले को पुलिस आयुक्त ने जिला पुलिस से हटाकर क्राइम ब्रांच को सौंप दी था। इसके साथ ही, पुलिस इस मामले में पकड़े गए मुख्य आरोपी 16 साल के किशोर के खिलाफ जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में एक याचिका दायर करने पर विचार कर रही है, ताकि अपराध की गंभीरता और उसके आपराधिक इतिहास को देखते हुए उस पर वयस्क के रूप में मुकदमा चलाया जा सके।

पुलिस अधिकारी के मुताबिक, वारदात में मुख्य आरोपी ओखला के श्याम नगर का रहने वाला 16 साल का किशोर है। पुलिस ने बताया कि मुख्य आरोपी समेत तीन अन्य उसके साथ थे। फिलहाल, इनमें से एक नाबालिग फरार चल रहा है। इस संबंध में किशोरी ने पुलिस को बताया था कि वह अपने दोस्त के साथ रेस्तरां में बैठी थी। तभी वहां मौजूद लड़कों में से एक ने उसकी बगल वाली कुर्सी के साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी और घूरना शुरू कर दिया। जब साई ने इस पर आपत्ति जताई, तो वह लड़का साई को घूरने लगा और उसके साथ गाली-गलौज करने लगा।

पत्रकारों को मिलनी चाहिए कैशलेस मेडिकल सुविधा : कपिल मिश्रा

नई दिल्ली। दिल्ली के कानून और न्याय, श्रम, रोजगार मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि पत्रकारों को कैशलेस मेडिकल सुविधा तो मिलनी ही चाहिए। उन्होंने यह बात 'मान्यता प्राप्त पत्रकार कल्याण समिति' के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के दौरान कही।

समिति का यह प्रतिनिधिमंडल पत्रकारों की मांगो का ज्ञापन लेकर मंत्री कपिल मिश्रा से आज दिल्ली सचिवालय में मिला। प्रतिनिधिमंडल में समिति के जनरल सेक्रेटरी रजनीकांत तिवारी, कोषाध्यक्ष अशोक कौशिक, गौरव शर्मा, श्याम सुंदर और अमित कुमार शामिल रहे। इस मौके पर कपिल मिश्रा को प्रतीक चिह्न, शॉल और पुष्प गुच्छ भेंट कर सम्मानित किया गया। यह ज्ञानकारी 'मान्यता प्राप्त पत्रकार कल्याण समिति' के जरिए विज्ञप्ति में दी गई।

विज्ञप्ति के मुताबिक, इस मौके पर कपिल मिश्रा ने पत्रकारों की मांगों पर चर्चा करते हुए कहा कि पत्रकारों को कैशलेस मेडिकल सुविधा तो मिलनी ही चाहिए। इसके साथ-साथ पत्रकारों को पेंशन, डीटीसी की अंतराजीय बसों में मुफ्त यात्रा समेत अन्य मांगों पर विचार करने का भरोसा दिया। समिति के प्रतिनिधियों ने कहा कि पत्रकार समाज और सरकार के बीच सेतु का कार्य करते हैं। कठिन परिस्थितियों, जोखिम और लगातार जिम्मेदारियों के बीच पत्रकार जनहित की आवाज को सामने लाते हैं। ऐसे में उनके स्वास्थ्य और भविष्य की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए।

सीबीएसई मूल्यांकन संबंधी मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल

नई दिल्ली। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) की नई ऑन-स्क्रीन मूल्यांकन प्रणाली को लेकर विवाद गहरा गया है। कांग्रेस पार्टी के भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन (एनएसयूआई) ने इस प्रणाली में कथित व्यापक अनियमितताओं व खामियों का आरोप लगाते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। याचिका में पूरे मामले की स्वतंत्र जांच कराने का निर्देश देने और प्रभावित छात्रों को राहत देने की मांग की गई है।

एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ की ओर से दायर याचिका में कहा गया कि यह मामला लाखों विद्यार्थियों के हितों से जुड़ा है, जिन्होंने कक्षा 12 की परीक्षा इस डिजिटल मूल्यांकन प्रणाली के तहत दी थी। याचिका के अनुसार सीबीएसई ने उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैनिंग व मूल्यांकन के लिए ऑन-स्क्रीन प्रणाली लागू की थी। हालांकि परिणाम घोषित होने के बाद देशभर से बड़ी संख्या में विद्यार्थियों, अभिभावकों व शिक्षकों ने गंभीर शिकायतें दर्ज कराईं। इनमें धुंधली स्कैन प्रतियां, उत्तर पुस्तिकाओं के पन्ने गायब होना अधूरी अपलोडिंग, उत्तर पुस्तिकाओं का आपस में मेल न खाना, अपेक्षा से बहुत कम अंक मिलना तथा शिकायतों के निस्तारण के प्रभावी तंत्र का अभाव जैसी समस्याएं शामिल हैं।

एनएसयूआई का कहना है कि वर्तमान शिकायत निवारण व्यवस्था पर्याप्त नहीं है। याचिका में उत्तर पुस्तिका सत्यापन पोर्टल को एक महीने के लिए दोबारा खोलने, विवादित मामलों में मैनुअल पुनः जांच व भौतिक सत्यापन की अनुमति देने की मांग की गई।

रोजाना 30 स्पेशल गाड़ियों का परिचालन कर रहा उत्तर रेलवे

नई दिल्ली। ग्रीष्मकालीन अवकाश के समय लोगों को उनके घरों तक पहुंचाने के लए उत्तर रेलवे द्वारा लगातार विशेष रेलगाड़ियां चलाई जा रही हैं। उत्तर रेलवे से प्रतिदिन लगभग 30 विशेष रेलगाड़ियों का परिचालन किया जा रहा है जिसके माध्यम से लगभग 60 हजार अतिरिक्त सीटें रोजाना उपलब्ध कराई जा रही हैं। आगामी 15 जुलाई तक विशेष रेलगाड़ियों का परिचालन जारी रहेगा।

जानकारी के अनुसार अधिकांश स्कूलों में बीते 15 मई से ग्रीष्मकालीन अवकाश हो चुका है। इसके साथ ही राजधानी में बढ़ रही गर्मी के दौरान प्रत्येक वर्ष बड़ी संख्या में लोग मई एवं जून माह में अपने गांव चले जाते हैं। ऐसे यात्रियों के लिए प्रत्येक वर्ष उत्तर रेलवे द्वारा विशेष रेलगाड़ियों का परिचालन किया जाता है। इस वर्ष भी बीते 1 मई से ही विशेष रेलगाड़ियों का परिचालन शुरु कर दिया गया था जो आगामी 15 जुलाई तक जारी रहेगा। सबसे अधिक विशेष रेलगाड़ियां मुज्जफरपुर, दरभंगा, लौकहा बाजार, बरौनी, हावड़ा, वैष्णों देवी कटड़ा, पटना, मुज्जफरपुर आदि जगहों के लिए चलाई गई है।

उत्तर रेलवे के मुख्य प्रवक्ता हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि बीते दो महीने में उत्तर रेलवे द्वारा लगभग 1750 विशेष रेलगाड़ियां चलाई गई हैं। औसतन रोजाना 30 विशेष रेलगाड़ियां चलाई जा रही हैं। इसके साथ ही 280 अतिरिक्त कोच भी लगाए गए हैं। उन्होंने बताया कि आगमी 15 जुलाई तक 84 विशेष रेलगाड़ियों के माध्यम से एक हजार से ज्यादा फेरे लगाए जाएंगे। इसके साथ ही आवश्यकता पड़ने पर विशेष गाड़ियों एवं फेरों की संख्या को बढ़ाया भी जा सकता है।

यूएपीए केस में चार साल नौ महीने बाद आरोपी को जमानत

नई दिल्ली। पटियाला हाउस स्थित विशेष एनआईए अदालत ने गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के एक मामले में करीब चार साल नौ महीने से न्यायिक हिरासत में बंद आरोपी मधेश शंकर को जमानत दे दी। अदालत ने माना कि मुकदमे के जल्द पूरा होने की संभावना नहीं है और बड़ी संख्या में गवाहों की जांच अभी बाकी है।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश पीतांबर दत्त की अदालत ने आरोपी को एक लाख रुपये के निजी मुचलके और समान राशि के दो जमानतदारों पर रिहा करने का आदेश दिया। साथ ही पासपोर्ट जमा कराने, किसी समान अपराध में शामिल न होने और कथित तौर पर आईएसआईएस से जुड़े व्यक्तियों से संपर्क न रखने जैसी शर्तें भी लगाई गई हैं। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि आरोपी अगस्त 2021 से जेल में है और अब तक लंबी अवधि हिरासत में बिता चुका है। अभियोजन पक्ष अब तक 61 गवाहों के बयान दर्ज करा पाया है, जबकि करीब 90 गवाहों की गवाही अभी शेष है। ऐसे में मुकदमे के शीघ्र समाप्त होने की संभावना नहीं दिखती। बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि लंबे समय से हिरासत में रहने और सह-आरोपियों को मिली राहत के आधार पर आरोपी को भी जमानत दी जानी चाहिए।

दिल्ली स्वास्थ्य विभाग में बड़ा फेरबदल, 40 से अधिक डॉक्टरों और स्वास्थ्य अधिकारियों का तबादला

• नई दिल्ली, एजेंसी

दिल्ली सरकार ने राजधानी की स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और प्रभावी बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के निर्देश पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत कार्यरत केंद्रीय खरीद एजेंसी (सीपीए) में व्यापक प्रशासनिक पुनर्गठन किया गया है। इस प्रक्रिया के तहत 40 से अधिक मेडिकल, पैरामेडिकल और प्रशासनिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों का स्थानांतरण किया गया है।

सरकार का कहना है कि दवाओं, चिकित्सा उपकरणों और अन्य स्वास्थ्य सामग्रियों की खरीद एवं आपूर्ति व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए यह कदम उठाया गया है, ताकि दिल्लीवासियों को बेहतर और समयबद्ध स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकें।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि दिल्लीवासियों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराना हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है और इसमें किसी प्रकार की लापरवाही या अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि सीपीए में एचओओ (हेड ऑफ ऑफिस) डॉ. विनोद कुमार रंगा समेत 10 डॉक्टरों का स्थानांतरण किया गया है। इसके अलावा पैरामेडिकल सेवाओं को मजबूत करने के लिए 20 कर्मचारियों का ट्रांसफर कर दिया गया है। इसमें फार्मासिस्ट, जूनियर मेडिकल लैब टेक्नीशियन, लैब अटेंडेंट और ड्राइवर आदि शामिल हैं।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के अनुसार, प्रशासनिक कार्यों में दक्षता बढ़ाने के लिए सेक्शन ऑफिसर, सीनियर असिस्टेंट और जूनियर असिस्टेंट स्तर के 10 कर्मचारियों का भी स्थानातंरण किया गया है। मानव संसाधनों की समीक्षा के दौरान सीपीए में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों की स्थिति का भी आकलन किया गया है।

साथ ही ऐसे कर्मचारियों की जानकारी भी संकलित की गई है जो सीपीए के वेतनमान पर हैं लेकिन अन्य कार्यालयों में कार्यरत हैं ताकि उपलब्ध संसाधनों का अधिक प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। इसके अलावा अन्य स्टाफ को भी सीपीए से हटाया गया है।

मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि सीपीए दिल्ली सरकार की स्वास्थ्य व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण केंद्र है, जहां से दवाओं, चिकित्सा उपकरणों और अन्य आवश्यक स्वास्थ्य सामग्रियों की खरीद एवं आपूर्ति का कार्य संचालित होता है। इस व्यवस्था को और अधिक सक्षम बनाने के लिए विभिन्न अस्पतालों और विभागों से अनुभवी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को जोड़ा जा रहा है। इस प्रक्रिया के तहत विभिन्न अस्पतालों और स्वास्थ्य संस्थानों से 12 चिकित्सा अधिकारियों को सीपीए में तैनात किया गया है। इनमें वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, चिकित्सा अधिकारी और सीएमओ स्तर के अधिकारी शामिल हैं। इनकी तैनाती से खरीद, भंडारण, आपूर्ति और प्रशासनिक कार्यों को और मजबूती मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विभागीय कार्यों को गति देने के लिए विभिन्न अधिकारियों को अतिरिक्त जिम्मेदारियां भी सौंपी गई हैं। प्रोजेक्ट ब्रांच, केयरटेकिंग ब्रांच, स्टोर एवं परचेज ब्रांच, कंप्यूटर सेल, मोबाइल हेल्थ स्कीम, पीजीएमएस, आरटीआई, चाइल्ड राइट्स, हेल्थ मेला, अस्पताल समन्वय और अन्य महत्वपूर्ण इकाइयों के संचालन की जिम्मेदारी संबंधित अधिकारियों को दी गई है। इसके अलावा स्टोर एवं परचेज ब्रांच और सीपीए से जुड़े कार्यों को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए भी आवश्यक प्रशासनिक व्यवस्थाएं की गई हैं।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली को आठ कमांड सेंटर में विभाजित कर जल प्रबंधन में सुधार का काम किया जा रहा है। इसके अंतर्गत वजीराबाद और चंद्रावल कमांड सेंटर की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अन्य का अध्ययन किया जा रहा है।

दिल्ली के हैदरपुर तक सीएलसी और डीएसबी से पानी। सीएलसी में पानी की बर्बादी मात्र पांच प्रतिशत, लेकिन डीएसबी में 45 प्रतिशत तक है। इस ओपन कैनाल की जगह पाइप लाइन से पानी लाने के लिए IIT रुड़की से अध्ययन कराया जा रहा है। इस परियोजना के लिए दिल्ली सरकार फंड देगी और हरियाणा सरकार यह काम करेगी। 2032 तक रेणुका डैम से पानी मिलेगा। इससे पहले ड्यूल पाइप लाइन पर काम शुरू किया गया है। डीपीआर तैयार किया जा रहा है।

नए एसटीपी प्लांट ऐसे होंगे जिसमें न दुर्गंध होगा और न प्रदूषण। स्कीम तैयार की जा रही है। सबसे पहले सरकारी भवनों में ड्यूल पाइप लाइन सिस्टम को लागू किया जाएगा। इसके बाद आवासीय सोसाइटी में। इसे लागू करने वाली सोसाइटी को बिल में छूट दी जाएगी। एक साल में नए एसटीपी प्लांट लगाने और उसके एक साल में ड्यूल पाइप लाइन सिस्टम लग जाए। पाइप लगने तक एसटीपी से टैंकर के माध्यम से उपचारित पानी सरकारी भवनों और सोसाइटी तक पहुंचाने की व्यवस्था की जाएगी।

CBSE के पोर्टल पर बड़ा साइबर अटैक, 2 मिनट में आए 15 लाख हिट्स

• नई दिल्ली, एजेंसी

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) के पुनर्मूल्यांकन पोर्टल पर आज भारी ट्रैफिक के बीच साइबर हमलावरों ने लगातार हमले किए, लेकिन पोर्टल मजबूती से सेवा दे रहा है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार, पोर्टल वर्तमान में 8,000 से अधिक समवर्ती (कॉन्करेंट) यूजर्स को सपोर्ट कर रहा है। दोपहर 3 बजे तक 16,000 से ज्यादा छात्र सफलतापूर्वक अपने पुनर्मूल्यांकन आवेदन जमा कर चुके हैं। हजारों छात्रों ने आज पोर्टल का उपयोग किया, लेकिन इसी दौरान दुर्भावनापूर्ण तत्वों ने सेवाओं को बाधित करने का प्रयास किया। सबसे ताजा घटना में दो मिनट के अंदर पोर्टल पर 15 लाख हिट्स (hits) दर्ज किए गए, जो एक स्पष्ट डिनायल ऑफ सर्विस (DoS) अटैक था।

इसके अलावा, 1 लाख से अधिक अनधिकृत फाइल एक्सेस के प्रयास भी सामने आए। CBSE की टीम ने इन हमलों का सामना करते हुए पोर्टल को पूरी तरह सुरक्षित और चालू रखा। छात्रों की फीडबैक के आधार पर प्लेटफॉर्म को और बेहतर बनाया गया है। अब सेशन टाइम लिमिट बढ़ा दी गई है, जिससे छात्रों को अपनी प्रक्रिया अधिक सुविधाजनक और निर्बाध तरीके से पूरी करने में मदद मिल रही है।

CBSE ने छात्रों के हित को सर्वोपरि रखते हुए अपनी टीमों को पूरी तरह अलर्ट रखा है। आधिकारिक बयान में कहा गया है कि छात्रों की सुविधा के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। पोर्टल पर भारी लोड और साइबर हमलों के बावजूद सेवा बिना रुके जारी है, जो बोर्ड की तकनीकी मजबूती को दर्शाता है। छात्रों से अपील की गई है कि वे आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ही आवेदन करें और किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्या होने पर हेल्पलाइन से संपर्क करें। CBSE का कहना है कि पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और छात्र-हितैषी रखी गई है। टीमों की सतर्कता और त्वरित प्रतिक्रिया के कारण हमलों के बावजूद हजारों छात्र अपना काम समय पर पूरा कर पा रहे हैं।

दिल्ली रिज की सुरक्षा के लिए रिज मैनेजमेंट बोर्ड का पुनर्गठन

• नई दिल्ली, एजेंसी

राजधानी की हरित विरासत और पर्यावरणीय संतुलन को मजबूत करने के उद्देश्य से उपराज्यपाल टीएस संधू ने दिल्ली रिज मैनेजमेंट बोर्ड (डीआरएमबी) के पुनर्गठन को मंजूरी दे दी है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप गठित इस नए बोर्ड का उद्देश्य दिल्ली रिज क्षेत्र की सुरक्षा, संरक्षण और प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करना है।

पुनर्गठित बोर्ड की अध्यक्षता मुख्य सचिव करेंगे, जबकि दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के उपाध्यक्ष सदस्य होंगे। इसके अलावा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, एमसीडी, एनडीएमसी, दिल्ली पुलिस, सीपीडब्ल्यूडी, राजस्व विभाग और पर्यावरण एवं वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी बोर्ड में शामिल किए गए हैं। बोर्ड में पर्यावरण विशेषज्ञों और गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों को भी जगह दी गई है। सेवानिवृत्त आईएफएस अधिकारी अरविंद माधव सिंह और संकला फाउंडेशन की निदेशक डॉ. मालविका कौल को गैर-सरकारी सदस्य के रूप में शामिल किया गया है।

DTC बस में बैठकर पहुंचे रोहतास नगर पहुंचे मंत्री प्रवेश वर्मा और सांसद मनोज तिवारी

• नई दिल्ली, एजेंसी

उत्तर-पूर्वी दिल्ली के रोहतास नगर विधानसभा क्षेत्र में लंबे समय से लंबित विकास कार्यों को गति देने की दिशा में सोमवार को अहम पहल की गई। सांसद मनोज तिवारी और दिल्ली सरकार के लोक निर्माण विभाग (PWD) मंत्री प्रवेश वर्मा ने अधिकारियों के साथ क्षेत्र का दौरा कर विभिन्न परियोजनाओं और स्थानीय समस्याओं का निरीक्षण किया। इस दौरान सड़क, जल निकासी, सौंदर्यीकरण और सार्वजनिक सुविधाओं से जुड़े मुद्दों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को विकास कार्यों में तेजी लाने और लंबित परियोजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने के निर्देश दिए गए।

उत्तर पूर्वी दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी ने अधिकारियों के साथ क्षेत्र की जमीनी स्थिति का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा कि रोहतास नगर क्षेत्र की वर्षों पुरानी समस्याओं के समाधान के लिए दिल्ली सरकार गंभीरता से काम कर रही है।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि क्षेत्र में लंबित परियोजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए ताकि लोगों को जल्द राहत मिल सके।प्रवेश वर्मा ने विशेष रूप से रोहतास नगर फ्लाईओवर के नीचे के क्षेत्र के सौंदर्यीकरण और बेहतर उपयोग को लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि स्थानीय निवासियों और व्यापारियों से सुझाव लेकर इस स्थान को जनहित के अनुरूप विकसित किया जाएगा। इसके लिए कई नई योजनाओं और सुविधाओं पर काम शुरू करने के आदेश भी दिए गए हैं।

सांसद मनोज तिवारी ने कहा

सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि केंद्र और दिल्ली सरकार मिलकर क्षेत्र के विकास के लिए लगातार प्रयास कर रही हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जनता की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा और विकास कार्यों में किसी प्रकार की बाधा नहीं आने दी जाएगी।

स्थानीय लोगों ने भी क्षेत्र में लंबे समय से लंबित समस्याओं के समाधान की दिशा में उठाए जा रहे कदमों का स्वागत किया और उम्मीद जताई कि निरीक्षण के बाद विकास कार्यों को नई गति मिलेगी।

सिलिंडर रिफिलिंग के समय ब्लास्ट से भरभराकर गिरा मकान, 11 घायल; एक की हालत गंभीर

• नई दिल्ली, एजेंसी

भलस्वा डेरी थाना क्षेत्र के मुकुंदपुर के ईशू विहार की गली नंबर-एक में मंगलवार सुबह साढ़े नौ बजे जोरदार धमाके के बाद एक इमारत ढह गई। धमाके की तीव्रता इतनी अधिक थी कि पूरा मकान मलबे में तब्दील हो गया। मकान में अवैध तरीके से गैस रिफिलिंग का काम किया जा रहा था। एनडीआरएफ की टीम ने मलबे में दबे लोगों को निकालने के लिए खोजी कुत्तों की भी मदद ली।

जानकारी के अनुसार, इस हादसे में 11 व्यक्ति घायल हो गए हैं। इनमें से एक की हाल गंभीर बनी हुई है। हादसे के तुरंत बाद दमकल की टीम के पहुंचने से पहले ही स्थानीय लोगों और पीसीआर की मदद से चार घायलों को नजदीकी अस्पताल पहुंचा दिया गया था। फिलहाल, सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है।

स्थानीय लोगों के अनुसार, 250 वर्ग गज के इस भूखंड में गैस सिलिंडर रीफिलिंग के अलावा पेंट और मोबाइल चार्जिंग वायर बनाने का काम भी होता था। लोगों का कहना है कि 5-6 साल से इस इमारत में व्यवसायिक गतिविधियां चल रही थीं।

पुलिस और दमकल विभाग के अनुसार, अभी तक तीन लोगों को मलबे से सकुशल निकाल लिया गया है, जबकि एक व्यक्ति अभी भी मलबे में दबा हुआ है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, घटना गैस सिलिंडर ब्लास्ट के कारण हुई है। इस हादसे में कुल 11 लोग घायल हुए हैं। वहीं, एक की हालत गंभीर होने के बाद उसे सफदरजंग अस्पताल में रेफर कर दिया गया है।

दमकल विभाग की पांच गाड़ियां मौके पर पहुंच गई हैं और पुलिस के साथ मिलकर रेस्क्यू अभियान तेजी से चलाया जा रहा है। दमकल विभाग का कहना है कि सुबह 9:37 बजे धमाके के बाद इमारत गिरने और कुछ लोगों के फंसे होने की सूचना मिली थी। सर्च अभियान अभी जारी रहा है।

आधिकारिक जानकारी के अनुसार, मंगलवार को सुबह 9 बजे सूचना मिली कि सिलिंडर में धमाका होने के बाद एक मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। सूचना मिलते ही घटनास्थल पर राहत कार्य शुरू करने के आदेश दे दिए। इस बीच स्थानीय लोगों ने राहत एवं बचाव कार्य करना शुरू कर दिया था। सूचना यह भी मिल रही है कि मलबे में से आधा दर्जन सिलिंडर मिले हैं।

बाहरी उत्तरी जिला पुलिस उपायुक्त हरेश्वर स्वामी ने बताया कि इस इमारत में अवैध रूप से गैस सिलिंडर की रीफिलिंग हो रही थी। बड़े सिलिंडर से छोटे सिलिंडर में गैस भरी जा रही थी। इसी दौरान धमाका हुआ।

सभी घायलों को निकाल कर अस्पताल पहुंचा दिया गया है, इनसे एक व्यक्ति की हालत गंभीर बताई जा रही है। चार घायलों का इलाज जहांगीरपुरी के बाबू जगजीवन राम अस्पताल में चल रहा है और छह रोहिणी स्थित बाबा साहेब अंबेडकर में उपचाराधीन हैं।

साले ने की जीजा की चाकू गोदकर हत्या

नई दिल्ली। दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में आपसी पारिवारिक विवाद ने एक युवक की जान ले ली। दरअसल पत्नी को वापस घर ले जाने के लिए पहुंचे युवक की कथित तौर पर उसके नाबालिग साले ने चाकू मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी नाबालिग को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है।

मृतक अभिषेक की शादी कुछ साल पहले आरती से हुई थी। बताया गया कि अभिषेक नशे का आदी था, जिसके चलते पति-पत्नी के बीच अक्सर विवाद होता रहता था। लगातार झगड़ों से परेशान होकर आरती अपने मायके में रहने लगी थी। परिजनों के मुताबिक अभिषेक इस बात से नाराज रहता था और अक्सर अपनी पत्नी को वापस साथ चलने के लिए दबाव बनाता था। आरोप है कि वह कई बार चाकू लेकर आरती के घर पहुंचता था और उसे धमकाने की कोशिश करता था।

दिल्ली में जल्द शुरू होगा ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन, समय पर होंगे काम

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने नागरिकों को बेहतर और पारदर्शी सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में एक और कदम उठाते हुए बुराड़ी स्थित परिवहन विभाग की विभिन्न इकाइयों का औचक निरीक्षण किया।

निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने डीटीओ (District Transport Office), व्हीकल इंस्पेक्शन यूनिट, व्हीकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन (ATS) का दौरा कर वहां उपलब्ध सुविधाओं और कार्यों की स्थिति का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान नागरिकों को मिलने वाली सुविधाओं, सेवा वितरण व्यवस्था और कार्यालयों में कार्यप्रणाली की समीक्षा की गई। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि आम लोगों को किसी प्रकार की असुविधा न हो और सेवाओं को अधिक सरल, पारदर्शी तथा समयबद्ध बनाया जाए।

इस दौरान ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन (ATS) के निर्माण कार्यों की भी विस्तृत समीक्षा की गई। संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि निर्माण कार्य निर्धारित समयसीमा के भीतर पूरा किया जाए, ताकि नागरिकों को आधुनिक और तकनीक आधारित वाहन परीक्षण सुविधाएं जल्द उपलब्ध कराई जा सकें।

अब दूध का प्लास्टिक पैक पर्यावरण को नहीं करेगा प्रदूषित, मदर डेयरी लाया मिट्टी में घुलने वाला मिल्क पाउच

• नई दिल्ली, एजेंसी

प्लास्टिक के पैक में दूध लेने से अधिकतर लोगों को अच्छा महसूस नहीं होता, क्योंकि यह ध्यान में रहता है कि दूध का तो इस्तेमाल हो जाएगा, लेकिन साथ ही प्लास्टिक का पाउच फेंकना पड़ेगा। जो पर्यावरण के साथ मिट्टी को भी प्रदूषित करेगा। लेकिन अब चिंता की बात नहीं है। क्योंकि प्रमुख दूग्ध उत्पाद कंपनी मदर डेयरी ने देश का ऐसा पहला प्लास्टिक के पैक प्रस्तुत किया है जो, मिट्टी में घुलने वाला है।

यह फर्स्ट-ऑफ-इट्स-काइंड मिल्क पैकेजिंग है, जो बायो अवेलेबल वैक्स में बदल जाती है, जिसे मिट्टी में मौजूद माइक्रोब्स नैचुरली ब्रेकडाउन करके प्राकृतिक तत्वों में बदल देते हैं।

मदर डेयरी इस पैकेजिंग इनोवेशन को अपने प्रसिद्ध गाय दूध वर्ग के माध्यम से दिल्ली-एनसीआर में विश्व पर्यावरण दिवस (पांच जून) से पेश करेगी, जिसमें एक नया पैक डिजाइन भी शामिल होगा।

मदर डेयरी, देश की लोकप्रिय दूध और दुग्ध उत्पादों की प्रमुख एवं राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। उसने आज मंगलवार को देश का पहला मिट्टी में नैचुरली डिग्रेडेबल मिल्क पाउच पेश किया।

कंपनी के अधिकारियों के अनुसार, यह पहल सस्टेनेबिलिटी और पर्यावरण संरक्षण के प्रति कंपनी की लंबे समय से चली आ रही प्रतिबद्धता को और मजबूत करती है। नई पैकेजिंग इनोवेशन का अनावरण करते हुए राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड एवं मदर डेयरी के अध्यक्ष डॉ. मीनेश शाह ने कहा, विश्व के सबसे बड़े दूध उत्पादक देश के रूप में, भारत का डेयरी क्षेत्र व्यापकता, समावेशिता और जिम्मेदारी का एक सच्चा उदाहरण है।

जल समस्या

पानी की समस्या से दिल्ली वालों को मिलेगा छुटकारा, मंत्री प्रवेश वर्मा ने बताया पूरा प्लान

• नई दिल्ली, एजेंसी

दिल्ली में पानी की कमी को दूर करने के लिए दिल्ली सरकार सीवेज उपचार संयंत्रों (एसटीपी) के उपचारित पानी के गैर पेयजल कार्य में करने की योजना तैयार की जा रही है। अगले दो वर्षों में इस योजना को जमीन पर लाने का लक्ष्य रखा गया है।

जल मंत्री प्रवेश वर्मा ने प्रेसवार्ता में कहा कि पिछले कुछ दिनों से दिल्ली पानी की कमी है। जनसंख्या के आधार पर दिल्ली में 1250 एमजीडी पानी की आवश्यकता। इसकी तुलना में एक हजार एमजीडी मिलता है। हरियाणा से बात करने से सीएलसी और डीएसबी से एक हजार क्यूसेक पानी मिल रहा है।

यमुना में पानी की कमी के वजीराबाद जलाशय का जलस्तर 674.15 की जगह 668 फीट रह गया है। वजीराबाद और चंद्रावल डब्ल्यूटीपी के लिए यमुना से पहले 209 क्यूसेक पानी लिया जाता था। जलाशय का जलस्तर कम होने से इसकी जगह इस समय मात्र 75 क्यूसेक पानी मिल रहा है।

पहले हरियाणा से सीएलसी डीएसबी नहरों के माध्यम से 920 क्यूसेक पानी मिलता था अब लगभग एक हजार क्यूसेक हो गया। इस पानी को वजीराबाद और चंद्रावल की तरफ मोड़ा गया है। इसके बाद भी इन दोनों संयंत्रों को लगभग 50 एमजीडी कम पानी मिल रहा है।

उन्होंने कहा कि दिल्ली में पानी की समस्या दूर करने के लिए कई परियोजनाओं पर काम किया जा रहा है इसके अंतर्गत पुरानी पाइप लाइनों को बदला जा रहा है। दिल्ली

पीएम मोदी और सीएम भजनलाल की ढाई घंटे की बैठक के क्या हैं मायने? राजस्थान कैबिनेट में जल्द हो सकता है फेरबदल

• जयपुर, एजेंसी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के बीच हुई करीब ढाई घंटे की महत्वपूर्ण बैठक के बाद राजस्थान की राजनीति में नई चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया है। राजनीतिक गलियारों में मंत्रिमंडल विस्तार और लंबित राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। माना जा रहा है कि आगामी निकाय और पंचायत चुनावों से पहले भाजपा सरकार और संगठन स्तर पर कुछ बड़े फैसले ले सकती है।

जल्द हो सकती हैं राजनीतिक नियुक्तियां

सूत्रों के अनुसार, बैठक के दौरान प्रदेश सरकार के कामकाज, संगठनात्मक गतिविधियों और आगामी चुनावी रणनीति पर विस्तार से चर्चा हुई। इसके साथ ही मंत्रिमंडल विस्तार और विभिन्न बोर्ड, निगम, आयोग तथा सरकारी संस्थानों में लंबे समय से लंबित राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर भी मंथन किए जाने की चर्चा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि चुनावी वर्ष को देखते हुए भाजपा सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन साधने की दिशा में कदम उठा सकती है। मंत्रिमंडल विस्तार के जरिए विभिन्न वर्गों और क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व देने पर विचार किया जा सकता है। वहीं, राजनीतिक नियुक्तियों के माध्यम से संगठन से जुड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं को नई जिम्मेदारियां सौंपे जाने की संभावना भी जताई जा रही है।

संगठन को मजबूती मिलेगी

प्रदेश भाजपा के कई नेता और कार्यकर्ता लंबे समय से बोर्ड, निगम और आयोगों में नियुक्तियों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ऐसे में यदि सरकार इन नियुक्तियों पर फैसला करती है तो इससे संगठन को मजबूती मिलने के साथ-साथ कार्यकर्ताओं में भी सकारात्मक संदेश जाएगा। हालांकि, मुख्यमंत्री के नेतृत्व को लेकर किसी प्रकार के बदलाव की संभावना फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है।

भाजपा नेतृत्व पहले भी स्पष्ट कर चुका है कि राजस्थान में सरकार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में ही कार्य करती रहेगी। पार्टी का फोकस विकास कार्यों, सुशासन और आगामी चुनावी तैयारियों पर बना हुआ है।

अब राजनीतिक हलकों की नजर भाजपा नेतृत्व के अगले कदम पर टिकी हुई है। यदि आने वाले दिनों में मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर कोई घोषणा होती है, तो इसे आगामी निकाय और पंचायत चुनावों की रणनीतिक तैयारी के रूप में देखा जाएगा।

'मैंने बेनीवाल जैसे बहुत देखे हैं': मदन राठौड़ का पलटवार, कहा- उनके लिए अकेला ही काफी हूं

जयपुर, एजेंसी। राजस्थान की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (आरएलपी) के बीच बयानबाजी का दौर लगातार तेज होता जा रहा है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल के बीच चल रही जुबानी जंग अब और तीखी हो गई है। बेनीवाल के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए मदन राठौड़ ने कहा कि उन्होंने राजनीति में ऐसे कई नेताओं को देखा है और हनुमान बेनीवाल का सामना करने के लिए वे अकेले ही काफी हैं। दरअसल, हनुमान बेनीवाल ने हाल ही में आरोप लगाया था कि मदन राठौड़ उनका नाम लेकर राजनीतिक लोकप्रियता हासिल करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा था कि एक समय मदन राठौड़ उनके साथ लंबे समय तक बैठकर भाजपा की आलोचना किया करते थे। बेनीवाल ने उन पर राजनीतिक रुख बदलने का आरोप लगाते हुए कहा कि वे पहले एक खेमे में थे और अब दूसरे खेमे के साथ खड़े नजर आते हैं। इन आरोपों का जवाब देते हुए मदन राठौड़ ने कहा कि राजस्थान की राजनीति में शुद्धता और मर्यादा की आवश्यकता है।

जयपुर के ट्रैफिक पर 'कंट्रोल रूम की नजर': जीब्रा लाइन लांघी तो स्पीकर से तुरंत मिलेगी चेतावनी

• जयपुरी, एजेंसी।

राजधानी जयपुर में बेतरतीब ट्रैफिक, रोजाना लगने वाले जाम और नियमों की अनदेखी पर लगाम लगाने के लिए पुलिस ने तकनीक का सहारा लिया है। शहर में एक नई सार्वजनिक उद्घोषणा (पब्लिक एड्रेस) प्रणाली शुरू की जा रही है, जिसके तहत ट्रैफिक सिग्नलों को सीधे पुलिस कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से जोड़ा जा रहा है।

इस व्यवस्था का पायलट प्रोजेक्ट फिलहाल रामबाग चौराहे पर शुरू किया गया है। नई प्रणाली के तहत ट्रैफिक सिग्नल पर लगे हाई-रिजॉल्यूशन कैमरे और लाउड-स्पीकर वाहन चालकों की गतिविधियों पर नजर रखेंगे। यदि कोई चालक जीब्रा लाइन पार कर आगे खड़ा होता है या ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करता है, तो कंट्रोल सेंटर में मौजूद पुलिसकर्मी तुरंत उसे नाम, वाहन नंबर या पहचान के आधार पर सार्वजनिक रूप से चेतावनी दे सकेंगे।

रामबाग चौराहे पर शुरू हुई इस व्यवस्था के शुरुआती दिनों में कई वाहन चालक उस समय चौंक गए, जब अचानक लाउडस्पीकर से उन्हें पीछे हटने या नियमों का पालन करने की हिदायत दी गई। कई लोगों को यह एहसास ही नहीं था कि उनकी हर गतिविधि पर कंट्रोल सेंटर से नजर रखी जा रही है। पुलिस अधिकारियों का मानना है कि केवल चालान और दंड से ट्रैफिक व्यवस्था में अपेक्षित सुधार नहीं हो पा रहा था।

कांग्रेस चिंतन शिविर के समापन में पहुंचे राहुल गांधी, जिलाध्यक्षों के परिवार से मिले, खड़गे का दौरा टला

• जयपुर, एजेंसी।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी सोमवार को अजमेर जिले के पुष्कर पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस के 10 दिवसीय राष्ट्रीय चिंतन एवं संगठन सृजन प्रशिक्षण शिविर के समापन कार्यक्रम में भाग लिया। वाइल्ड रोज रिसॉर्ट में आयोजित इस शिविर में देशभर से आए कांग्रेस पदाधिकारियों और जिला अध्यक्षों को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने और कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद बढ़ाने पर जोर दिया।

संगठन को मजबूत बनाने का दिया संदेश

शिविर में राजस्थान के 50 और दिल्ली के 15 जिला अध्यक्षों सहित प्रदेश पदाधिकारी मौजूद रहे। राहुल गांधी ने प्रशिक्षण शिविर के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि संगठन की मजबूती ही कांग्रेस की सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने जिला अध्यक्षों को संगठन विस्तार, जनसंपर्क और पार्टी की विचारधारा को आमजन तक पहुंचाने के संबंध में मार्गदर्शन दिया। इस दौरान शिविर में शामिल जिला अध्यक्षों के परिवारजन भी कार्यक्रम का हिस्सा बने। राहुल गांधी ने परिवार के सदस्यों से आत्मीय मुलाकात की और उनके साथ तस्वीरें भी खिंचवाईं।

एयरपोर्ट से पुष्कर तक जोरदार स्वागत

इससे पहले राहुल गांधी सुबह 10:05 बजे किशनगढ़ एयरपोर्ट पहुंचे, जहां पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट सहित कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं ने उनका स्वागत किया। किशनगढ़ विधायक विकास चौधरी ने राहुल गांधी को पारंपरिक हल भेंट कर उनका अभिनंदन किया। इसके बाद राहुल गांधी सड़क मार्ग से पुष्कर के लिए रवाना हुए।

खड़गे का दौरा रद्द

गौरतलब है कि चिंतन शिविर में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के भी शामिल होने का कार्यक्रम था, लेकिन किसी कारणवश उनका दौरा अंतिम समय में रद्द हो गया। शिविर के समापन के साथ संगठनात्मक मजबूती और आगामी राजनीतिक रणनीति को लेकर कांग्रेस नेताओं के बीच महत्वपूर्ण चर्चा हुई।

युवा जैसा सोचता है, वैसा ही बन जाता है : अर्जुनराम मेघवाल

• अजमेर, एजेंसी।

केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने कहा कि युवा जैसा सोचता है, अंततः वैसा ही बन जाता है। सकारात्मक विचार, अनुशासन और श्रेष्ठ संगति ही सफलता की वास्तविक कुंजी हैं। उन्होंने विद्यार्थियों का आह्वान किया कि वे बड़े सपने देखें, उन्हें साकार करने के लिए कठिन परिश्रम करें तथा स्वामी विवेकानंद और डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम जैसे महापुरुषों के जीवन से प्रेरणा ग्रहण करें। मेघवाल अजमेर के जवाहर रंगमंच में आयोजित 'विलक्षण प्रतिभा सम्मान समारोह' को संबोधित कर रहे थे।

अजमेर दक्षिण विधायक अनिता भदेल एवं पहल जन सेवा संस्थान के तत्वावधान में आयोजित समारोह में राज्य एवं केंद्रीय शिक्षा बोर्डों की 12वीं कक्षा में 90 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले 520 विद्यार्थियों का सम्मान किया गया। समारोह में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी भी विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। मेघवाल ने कहा कि मानसिक स्वास्थ्य शारीरिक स्वास्थ्य जितना ही महत्वपूर्ण है। सकारात्मक सोच व्यक्ति को श्रेष्ठता की ओर ले जाती है, जबकि नकारात्मकता निराशा को जन्म देती है। उन्होंने विद्यार्थियों से अपनी क्षमता पर विश्वास रखने, अच्छे लोगों की संगति अपनाने तथा भारतीय जीवन मूल्यों को आत्मसात करने का आह्वान किया। पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए उन्होंने स्वयं नियमित रूप से साइकिल चलाने की बात कही तथा प्रकृति के निकट रहने को तनावमुक्त जीवन का आधार बताया। केंद्रीय राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने कहा कि शिक्षा के साथ संस्कार, अनुशासन और मितव्ययता भी आवश्यक हैं। प्रतिभाओं का सम्मान केवल उनकी उपलब्धियों का अभिनंदन नहीं, बल्कि अन्य विद्यार्थियों को प्रेरित करने का माध्यम भी है। उन्होंने युवाओं से मोबाइल एवं डिजिटल संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करने, स्वदेशी उत्पादों को अपनाने तथा विकसित भारत के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया।

विधायक अनिता भदेल ने बताया कि वर्ष 2022 में प्रारंभ किए गए इस सम्मान समारोह के माध्यम से अब तक 2,000 से अधिक प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को सम्मानित किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि समाज में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, आवश्यकता केवल उन्हें पहचानने और प्रोत्साहित करने की है। इस वर्ष 135 विद्यालयों से संपर्क कर प्राप्त सूचनाओं के आधार पर 67 विद्यालयों के 520 विद्यार्थियों का चयन किया गया, जिन्हें मेडल, प्रमाण-पत्र एवं स्वामी विवेकानंद स्मृति-चिह्न प्रदान कर सम्मानित किया गया।

डबल इंजन नहीं, डबल इंतज़ारशास्त्र चल रहा है : अशोक गहलोत

• जयपुर, एजेंसी।

राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र और राज्य सरकार पर विकास परियोजनाओं में देरी को लेकर तीखा हमला बोला है। सोशल मीडिया मंच एक्स पर की गई अपनी पोस्ट में गहलोत ने "डबल इंजन सरकार" पर कटाक्ष करते हुए इसे "डबल इंतज़ारशास्त्र" करार दिया। गहलोत ने कहा कि योजनाओं और परियोजनाओं में लगातार हो रही देरी का सीधा असर आम जनता और सरकारी खजाने पर पड़ रहा है। उन्होंने लिखा कि "इंतज़ारशास्त्र" के जरिए राज्य सरकार को जगाने का प्रयास किया गया है ताकि यह समझाया जा सके कि परियोजनाओं में देरी केवल प्रशासनिक समस्या नहीं, बल्कि जनता की जेब पर भारी पड़ने वाला मुद्दा है।

पूर्व मुख्यमंत्री ने दावा किया कि यह समस्या केवल राजस्थान तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे देश में बड़े पैमाने पर देखने को मिल रही है। उन्होंने केंद्र सरकार की परियोजनाओं का हवाला देते हुए कहा कि देशभर में चल रहे 1981 प्रोजेक्ट्स में से अधिकांश देरी का शिकार हैं, जिसके कारण उनकी लागत करीब 5.65 लाख करोड़ रुपये तक बढ़ चुकी है। गहलोत ने कहा कि राजस्थान में वर्तमान में 81 बड़े प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जिनमें से 53 परियोजनाएं निर्धारित समय से पीछे चल रही हैं, जबकि 10 परियोजनाओं का बजट बढ़ चुका है। उन्होंने विशेष रूप से एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड की राजस्थान रिफाइनरी परियोजना का उल्लेख करते हुए कहा कि यह प्रोजेक्ट वर्ष 2022 तक पूरा होना था, लेकिन अब इसकी समयसीमा 2026 तक पहुंच गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि परियोजना की लागत भी 84.23 प्रतिशत बढ़कर 79,459 करोड़ रुपए हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि इन परियोजनाओं को समय पर शुरू और पूरा किया जाता तो बढ़ी हुई लागत के रूप में खर्च हो रही है।

महंगाई का झटका

राजस्थान में कॉमर्शियल सिलिंडर फिर हुआ महंगा, छह महीने में दाम दोगुने के करीब

• जयपुर, एजेंसी।

अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों और ऊर्जा बाजार में लगातार बढ़ रही कीमतों का असर अब देश के एलपीजी उपभोक्ताओं पर भी दिखाई देने लगा है। पेट्रोलियम कंपनियों ने रविवार रात एलपीजी गैस की कीमतों की समीक्षा करने के बाद एक बार फिर 19 किलोग्राम वाले कॉमर्शियल गैस सिलिंडर के दाम बढ़ा दिए हैं। नई दरें 1 जून से लागू हो गई हैं।

राजस्थान में 42 रुपये बढ़े कॉमर्शियल गैस सिलिंडर के दाम

राजस्थान एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष दीपक गहलोत के अनुसार, कंपनियों ने कॉमर्शियल गैस सिलिंडर की कीमत में 42 रुपये प्रति सिलिंडर की बढ़ोतरी की है। इसके बाद राजस्थान में 19 किलोग्राम वाला कॉमर्शियल एलपीजी सिलिंडर, जो अब तक 3099 रुपये में मिल रहा था, उसकी कीमत बढ़कर 3141 रुपये हो गई है।

घरेलू उपभोक्ताओं को राहत, रसोई गैस के दाम स्थिर

हालांकि आम उपभोक्ताओं को राहत देते हुए कंपनियों ने घरेलू गैस सिलिंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है। 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू एलपीजी सिलिंडर की कीमत राजस्थान में 916.50 रुपये पर स्थिर रखी गई है। इसके अलावा अन्य घरेलू श्रेणी के सिलिंडरों की दरों में भी कोई संशोधन नहीं किया गया है।

होटल-रेस्टोरेंट और कारोबारियों पर बढ़ेगा बोझ

कॉमर्शियल सिलिंडर की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी का सीधा असर होटल, रेस्टोरेंट, ढाबों, मिठाई दुकानों और छोटे व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर पड़ रहा है। व्यवसायियों का कहना है कि गैस की लागत बढ़ने से परिचालन खर्च में वृद्धि हो रही है, जिसका प्रभाव वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों पर भी पड़ सकता है।

छह महीने में कहां से कहां पहुंच गई कीमत

आंकड़ों पर नजर डालें तो वर्ष 2026 में कॉमर्शियल गैस सिलिंडर की कीमतों में कई बार बढ़ोतरी की जा चुकी है। 31 दिसंबर तक 19 किलोग्राम का कॉमर्शियल सिलिंडर 1608 रुपये में उपलब्ध था, जो अब बढ़कर 3141 रुपये तक पहुंच गया है। जनवरी में 111 रुपये, फरवरी में 49.50 रुपये, मार्च में 141.50 रुपये, अप्रैल में 195 रुपये, मई में 993 रुपये और जून में 42 रुपये प्रति सिलिंडर की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

आने वाले महीनों में और बढ़ सकती हैं कीमतें

लगातार बढ़ती कीमतों ने व्यापारिक उपभोक्ताओं की चिंता बढ़ा दी है। उद्योग और व्यापार से जुड़े संगठनों का कहना है कि यदि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल और गैस की कीमतों में तेजी का दौर जारी रहा, तो आने वाले महीनों में कॉमर्शियल एलपीजी और महंगी हो सकती है।

संक्षिप्त खबरें

बहरोड़ में लूट-मारपीट के बाद महिलाओं को उठा ले दबंग, तीन घंटे बाद पुलिस ने कराया रेस्क्यू

कोटपूतली-बहरोड़, एजेंसी। कोटपूतली-बहरोड़ जिले के बहरोड़ सदर थाना क्षेत्र में महिलाओं के कथित अपहरण, घर में घुसकर मारपीट, तोड़फोड़ और लाखों रुपये की नकदी व जेवरात लूटने का गंभीर मामला सामने आया है। घटना के बाद क्षेत्र में तनावपूर्ण हालात बन गए, जिसके चलते कई थानों की पुलिस और राजस्थान सशस्त्र बल (आरएसी) का भारी जाब्ता तैनात करना पड़ा। पुलिस ने पीड़ित पक्ष की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। नीमराना के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुरेश खिंची ने बताया कि मौसमपुर-कांकरा गांव निवासी एक व्यक्ति ने बहरोड़ सदर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि गांव पहाड़ी के कई लोग हथियारों और लाठियों से लैस होकर उसके घर पहुंचे। आरोपियों ने घर का मुख्य गेट तोड़ दिया और परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट की। पीड़ित ने शिकायत में आरोप लगाया है कि हमलावर उसकी पत्नी और पुत्रवधू के साथ भी मारपीट करते हुए उन्हें जबरन अपने साथ ले गए। इसके अलावा घर में रखी करीब 4 लाख 70 हजार रुपये की नकदी तथा सोने-चांदी के आभूषण भी लूट लिए गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आई और महिलाओं की तलाश के लिए विशेष टीमें गठित की गईं। पुलिस जांच में सामने आया है कि 28 मई को गांव पहाड़ी की एक युवती अपने ससुराल, झुंझुनूं जिले से मौसमपुर-कांकरा के एक युवक के साथ चली गई थी। इस संबंध में झुंझुनूं जिले में गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करवाई गई है। युवती की तलाश में झुंझुनूं पुलिस भी बहरोड़ पहुंची थी।

राजस्थान के 20 जिलों में आंधी-बारिश का यलो अलर्ट

जयपुर, एजेंसी। राजस्थान में मौसम ने अचानक करवट ले ली है। लगातार दो दिन तक रेत के बवंडर और धूलभरी आंधी के बाद सोमवार को भी प्रदेश के कई हिस्सों में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से सोमवार सुबह सवाई माधोपुर और आसपास के क्षेत्रों में बारिश हुई, जबकि जयपुर और दौसा सहित कई जिलों में बादल छाए रहे। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के 20 जिलों में यलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम में यह बदलाव 4 जून तक जारी रहने की संभावना है। सोमवार सुबह सवाई माधोपुर शहर में करीब छह बजे मौसम बदला और लगभग 15 मिनट तक तेज बारिश हुई। वहीं रविवार को जैसलमेर के सीमावर्ती क्षेत्रों में तेज रेत का बवंडर उठने से कई इलाके धूल-मिट्टी से ढक गए। बाद में बारिश और ओलावृष्टि होने से तापमान में गिरावट आ गई। प्रदेश में पिछले 24 घंटे के दौरान बीकानेर, हनुमानगढ़, चूरू, जैसलमेर, जोधपुर, उदयपुर, बाड़मेर और जालोर जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हुई। जैसलमेर में रविवार दोपहर तक तेज गर्मी रही और तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया। दोपहर बाद पाकिस्तान सीमा क्षेत्र की ओर से रेत का बवंडर उठा, जिसने सुल्ताना, मोहनगढ़ और सुथार मंडी सहित कई इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया। तेज हवाओं के कारण आसमान धूल से भर गया और दृश्यता प्रभावित हुई। रविवार को प्रदेश में सबसे अधिक तापमान बाड़मेर में 42 डिग्री सेल्सियस मापा गया। इसके अलावा जैसलमेर में 41.5, जालोर में 39.1, जोधपुर में 38.9, उदयपुर और वनस्थली (टोंक) में 38.2, चित्तौड़गढ़ में 38, कोटा में 37.4, श्रीगंगानगर में 37.3 और अलवर में 37 डिग्री सेल्सियस तापमान मापा गया।

कार—ट्रक भिड़ंत में हीरा व्यापारी समेत दो की मौत

प्रतापगढ़, एजेंसी। चित्तौड़गढ़-बांसवाड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच-56) पर सोमवार तड़के हुए भीषण सड़क हादसे में मुंबई के एक हीरा व्यापारी समेत दो लोगों की मौत हो गई, जबकि एक अन्य व्यापारी गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसा प्रतापगढ़ जिले के सुहागपुरा थाना क्षेत्र में पाडलिया जीएसएस के समीप अलसुबह करीब पांच बजे हुआ।पुलिस के अनुसार निर्माण कार्यों में प्रयुक्त एक मिक्सर ट्रक प्रतापगढ़ से बांसवाड़ा की ओर जा रहा था, जबकि मुंबई से आ रही कार बांसवाड़ा की दिशा में बढ़ रही थी। इसी दौरान दोनों वाहनों की आमने-सामने जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि ट्रक कार को घसीटते हुए सड़क किनारे लगभग 150 फीट गहरी खाई में जा गिरा। हादसे में कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। कार में चालक भावेश (35), मुंबई निवासी हीरा व्यापारी राजकुमार मूणत (42) तथा उनके मित्र घनश्याम पटेल (50) सवार थे। दुर्घटना में घनश्याम पटेल की मौके पर ही मृत्यु हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल चालक भावेश और राजकुमार मूणत को ग्रामीणों की सहायता से बाहर निकालकर जिला अस्पताल पहुंचाया गया। उपचार के दौरान चालक भावेश ने भी दम तोड़ दिया। राजकुमार मूणत का अस्पताल में उपचार जारी है।हादसे के बाद खाई में गिरी कार में सवार लोग बुरी तरह फंस गए थे। चीख-पुकार सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद घायलों को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया। घायल राजकुमार मूणत ने बताया कि वे और उनके मित्र घनश्याम पटेल मुंबई में हीरों का कारोबार करते हैं। प्रतापगढ़ जिले के निनौर गांव स्थित पुश्तैनी जमीन से जुड़े पारिवारिक विवाद के सिलसिले में वे मुंबई से अपने गांव आ रहे थे, लेकिन घर पहुंचने से पहले ही यह दुर्घटना हो गई।सुहागपुरा थानाधिकारी मनीष कुमार वैष्णव के अनुसार फरार ट्रक चालक की तलाश के लिए पुलिस टीमों को लगाया गया है। दोनों शवों को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है।

अजय कुमार बने राजस्थान भाजपा के प्रदेश महामंत्री (संगठन), 29 माह बाद भरा गया पद

नई दिल्ली/जयपुर, एजेंसी। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने राजस्थान संगठन में लंबे समय से रिक्त चल रहे प्रदेश महामंत्री (संगठन) पद पर नियुक्ति कर दी है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एवं मुख्यालय प्रभारी अरुण सिंह द्वारा जारी संगठनात्मक नियुक्ति पत्र के अनुसार भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने अजय कुमार को राजस्थान प्रदेश भाजपा का प्रदेश महामंत्री (संगठन) नियुक्त किया है। यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू होगी। सोमवार को जारी आदेश में कहा गया है कि अजय कुमार राजस्थान भाजपा में संगठनात्मक गतिविधियों के संचालन, समन्वय और विस्तार से जुड़े दायित्वों का निर्वहन करेंगे। नियुक्ति पत्र की प्रतिलिपि सभी राष्ट्रीय पदाधिकारियों, प्रदेश प्रभारियों, प्रदेश अध्यक्षों तथा राजस्थान के मुख्यमंत्री को भी प्रेषित की गई है। उल्लेखनीय है कि राजस्थान भाजपा में प्रदेश महामंत्री (संगठन) का पद 15 जनवरी 2024 से चंद्रशेखर के तेलंगाना जाने के बाद से रिक्त चल रहा था। करीब 29 माह से खाली इस पद को लेकर पार्टी संगठन और कार्यकर्ताओं के बीच लगातार चर्चाएं चल रही थीं।

घर में काम कर रही महिला पर पड़ोसी का खौफनाक हमला, ब्लेड से गला और पैर काटे

बांसवाड़ा, एजेंसी। बांसवाड़ा जिले के सदर थाना क्षेत्र के तेजपुर गांव में रविवार दोपहर एक महिला पर उसके पड़ोस में किराए से रहने वाले युवक ने ब्लेड से हमला कर दिया। हमले में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे परिजन तत्काल महात्मा गांधी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसका उपचार जारी है। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। पुलिस के अनुसार, तेजपुर निवासी रेखा (30) अपने घर में घरेलू कामकाज कर रही थी। इसी दौरान पड़ोस में किराए पर रहने वाला सूरज वहां पहुंचा। दोनों के बीच किसी पुराने विवाद को लेकर कहासुनी हो गई, जिसके बाद आरोपी ने अपने पास मौजूद ब्लेड से महिला के गले और पैरों पर ताबड़तोड़ वार कर दिए। हमले के बाद घायल महिला की चीख-पुकार सुनकर परिजन और आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। लहूलुहान हालत में महिला को तुरंत महात्मा गांधी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका उपचार जारी है।

संपादकीय

ईरान की सैन्य शक्ति और अमेरिकी दबाव के बीच बदलता पश्चिम एशिया का शक्ति संतुलन

पश्चिम एशिया एक बार फिर वैश्विक राजनीति के केंद्र में है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जारी तनाव ने पूरे क्षेत्र को अस्थिर बना दिया है। हाल के दिनों में ईरान द्वारा अमेरिकी MQ-1 ड्रोन को मार गिराने का दावा, होर्मुज स्ट्रेट के आसपास बढ़ती सैन्य गतिविधियां, लेबनान में संघर्ष और परमाणु समझौते को लेकर चल रही कूटनीतिक खींचतान ने यह स्पष्ट कर दिया है कि यह केवल दो देशों के बीच का विवाद नहीं बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन का मामला बन चुका है। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प का यह दावा कि ईरान परमाणु हथियार न बनाने और न खरीदने पर सहमत हो गया है, अंतरराष्ट्रीय राजनीति में एक नई बहस को जन्म देता है।

पहली नजर में ऐसा लग सकता है कि अमेरिका का दबाव काम कर रहा है और ईरान पीछे हट रहा है, लेकिन वास्तविकता इससे कहीं अधिक जटिल है। ईरान ने यदि परमाणु हथियारों के निर्माण से दूरी बनाने की बात स्वीकार भी की है तो इसका अर्थ यह नहीं है कि उसकी सामरिक या सैन्य शक्ति कमजोर हो गई है। पिछले दो दशकों में ईरान ने अपनी रक्षा नीति को इस प्रकार विकसित किया है कि वह बिना परमाणु हथियारों के भी क्षेत्रीय स्तर पर एक प्रभावशाली शक्ति बना रहे।

ईरान की सबसे बड़ी ताकत उसकी मिसाइल क्षमता है। उसके पास हजारों किलोमीटर तक मार करने वाली बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें हैं, जो पश्चिम एशिया में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों और इजराइल जैसे देशों के लिए लगातार चुनौती बनी हुई हैं। इसके अलावा ड्रोन तकनीक के क्षेत्र में भी ईरान ने उल्लेखनीय प्रगति की है। रूस-यूक्रेन युद्ध के दौरान ईरानी ड्रोन की चर्चा पूरी दुनिया में हुई थी। आज ईरान कम लागत में बड़ी संख्या में ऐसे ड्रोन तैयार करने में सक्षम है जो युद्ध के मैदान में प्रभावी भूमिका निभा सकते हैं।

ईरान की एक और बड़ी ताकत उसके क्षेत्रीय सहयोगी समूह हैं। लेबनान में हिजबुल्लाह, यमन में हूती संगठन, इराक और सीरिया में सक्रिय कई सशस्त्र समूह ईरान के प्रभाव क्षेत्र का हिस्सा माने जाते हैं। यही कारण है कि अमेरिका और इजराइल के लिए ईरान के साथ किसी भी संभावित संघर्ष का अर्थ केवल एक देश से युद्ध नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र में कई मोर्चों पर संघर्ष हो सकता है। यही वजह है कि अमेरिका की सैन्य शक्ति अत्यधिक मजबूत होने के बावजूद वह प्रत्यक्ष युद्ध को लेकर सावधानी बरतता दिखाई देता है।

अमेरिका ने लंबे समय से ईरान पर आर्थिक प्रतिबंधों, राजनीतिक दबाव और सैन्य चेतावनियों की नीति अपनाई है। उसका उद्देश्य ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकना और क्षेत्र में उसके प्रभाव को सीमित करना रहा है। लेकिन बीते वर्षों के अनुभव बताते हैं कि केवल दबाव की नीति से अमेरिका अपने सभी लक्ष्य हासिल नहीं कर पाया है। प्रतिबंधों के बावजूद ईरान ने अपनी सैन्य क्षमताओं को विकसित किया और क्षेत्रीय राजनीति में अपनी मौजूदगी बनाए रखी।

डोनाल्ड ट्रम्प के हालिया बयान भी इसी द्वंद्व को दर्शाते हैं। एक तरफ वे कहते हैं कि अमेरिका अपनी शर्तें मनवा रहा है और दूसरी तरफ यह भी कहते हैं कि उन्हें समझौते की कोई जल्दी नहीं है। यह बयान बताता है कि वाशिंगटन अभी भी दबाव और कूटनीति दोनों रास्तों को साथ लेकर चलना चाहता है। यदि अमेरिका पूरी तरह आश्वस्त होता कि वह सैन्य कार्रवाई के जरिए अपने लक्ष्य हासिल कर सकता है, तो शायद वह समझौते की भाषा पर इतना जोर नहीं देता।

कई विश्लेषकों का मानना है कि वर्तमान परिस्थितियों में अमेरिका भी कुछ हद तक बैकफुट पर दिखाई दे रहा है। इसका कारण केवल ईरान की सैन्य शक्ति नहीं बल्कि वैश्विक परिस्थितियां भी हैं। रूस-यूक्रेन युद्ध, चीन के साथ बढ़ती प्रतिस्पर्धा, वैश्विक आर्थिक चुनौतियां और ऊर्जा बाजार की अनिश्चितता अमेरिका को एक और बड़े युद्ध से बचने के लिए प्रेरित करती हैं। पश्चिम एशिया में किसी व्यापक संघर्ष का सीधा असर तेल की कीमतों, वैश्विक व्यापार और विश्व अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा।

होर्मुज स्ट्रेट इस पूरे विवाद का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। दुनिया के कुल समुद्री तेल व्यापार का बड़ा हिस्सा इसी जलमार्ग से होकर गुजरता है। यदि यहां किसी कारणवश आवाजाही प्रभावित होती है तो वैश्विक ऊर्जा बाजार में भारी उथल-पुथल मच सकती है। यही कारण है कि अमेरिका और उसके सहयोगी देश इस क्षेत्र को खुला और सुरक्षित रखना चाहते हैं, जबकि ईरान इसे अपने सामरिक प्रभाव के एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में देखता है।

हाल के घटनाक्रम यह भी दिखाते हैं कि ईरान केवल सैन्य शक्ति के भरोसे नहीं चल रहा बल्कि वह कूटनीतिक स्तर पर भी सक्रिय है। ईरानी नेतृत्व लगातार यह संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि वह अपने राष्ट्रीय हितों से समझौता नहीं करेगा। संसद के स्पीकर और अन्य वरिष्ठ नेताओं के बयान इसी रणनीति का हिस्सा माने जा रहे हैं। वे स्पष्ट कर रहे हैं कि किसी भी समझौते को तभी स्वीकार किया जाएगा जब उसमें ईरानी जनता के अधिकारों और देश की संप्रभुता का सम्मान किया जाए।

दूसरी ओर इजराइल की चिंता मुख्य रूप से सुरक्षा से जुड़ी है। इजराइल लंबे समय से ईरान के परमाणु कार्यक्रम और उसके क्षेत्रीय प्रभाव को अपने लिए खतरा मानता रहा है। इसलिए वह अमेरिका पर लगातार दबाव बनाता है कि ईरान के खिलाफ सख्त रुख अपनाया जाए। लेबनान और अन्य क्षेत्रों में जारी सैन्य गतिविधियां इसी व्यापक रणनीतिक संघर्ष का हिस्सा हैं।

वर्तमान स्थिति में यह कहना कठिन है कि अमेरिका और ईरान के बीच अंतिम समझौता कब और किस रूप में होगा। हालांकि इतना स्पष्ट है कि दोनों पक्ष प्रत्यक्ष युद्ध की कीमत को समझते हैं। यही कारण है कि कड़ी बयानबाजी और सैन्य तैयारियों के बावजूद बातचीत के रास्ते पूरी तरह बंद नहीं हुए हैं। ट्रम्प का यह कहना कि समझौता होने पर कई लोगों की जान बच सकती है, इस बात का संकेत है कि कूटनीति अभी भी सबसे महत्वपूर्ण विकल्प बनी हुई है।

कुल मिलाकर ईरान का परमाणु हथियार न बनाने पर सहमत होना एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम जरूर है, लेकिन इसे उसकी कमजोरी के रूप में नहीं देखा जा सकता। ईरान आज भी पश्चिम एशिया की सबसे प्रभावशाली सैन्य और राजनीतिक शक्तियों में से एक है। उसकी मिसाइल क्षमता, ड्रोन तकनीक, क्षेत्रीय नेटवर्क और भौगोलिक स्थिति उसे विशेष सामरिक महत्व प्रदान करती है। वहीं अमेरिका अपनी वैश्विक शक्ति और सैन्य क्षमता के बावजूद इस तथ्य को समझता है कि ईरान के साथ किसी बड़े संघर्ष के परिणाम केवल युद्धक्षेत्र तक सीमित नहीं रहेंगे बल्कि पूरी दुनिया पर उनका प्रभाव पड़ेगा। इसीलिए वर्तमान परिस्थितियां यह संकेत देती हैं कि शक्ति प्रदर्शन और कूटनीति दोनों साथ-साथ चलेंगे। अमेरिका दबाव बनाए रखेगा, ईरान अपनी ताकत का प्रदर्शन करता रहेगा और दोनों पक्ष अपने-अपने हितों को सुरक्षित रखते हुए बेहतर सौदे की तलाश करेंगे। पश्चिम एशिया का भविष्य इसी संतुलन पर निर्भर करेगा कि टकराव कितना बढ़ता है और संवाद के रास्ते कितने खुले रहते हैं।

- कांतिलाल मांडोत

महज कोरी बयानबाजी नही बनना चाहिए सुप्रीम कोर्ट का निर्देश

- **मनोज कुमार अग्रवाल**

अगली पेशी अगले साल यह देश की अदालतों में होता रहा है लेकिन हाल ही मे सुप्रीम कोर्ट ने न्याय में देरी को रोकने और पारदर्शिता लाने के लिए सभी हाईकोर्ट्स को सख्त निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत, सुनवाई के बाद सुरक्षित रखे गए सभी फैसले अधिकतम तीन महीने (90 दिन) के भीतर सुनाने अनिवार्य हैं। वहीं, जमानत से जुड़े मामलों में 24 घंटे के भीतर आदेश जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। ऐसा पहली बार नहीं है पूर्व में भी पूर्व सीजेआई सरकार और सत्तारूढ़ पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र और सत्तारूढ़ नेता समय समय पर देश की न्याय व्यवस्था में देरी की समस्या का समाधान खोजने का वायदा दावा और बयान करते रहे हैं लेकिन हर बार ढाक के वहीं तीन पात। न्याय मे देरी का सिलसिला नया नहीं है, लेकिन जब अदालतें बहस पूरी होने के बाद भी वर्षों तक फैसले सुरक्षित रखती हैं, तो यह केवल प्रशासनिक लापरवाही नहीं रह जाती, बल्कि न्याय के मूल सिद्धांत पर सवाल खड़ा करती है।

यह वह कड़वी सच्चाई है कि अदालतों में करोड़ों मामले लंबित हैं और न्याय की उम्मीद लिए लोग तारीख पर तारीख काटते रहते हैं। कई मामलों में फैसला तब आता है, जब पीड़ित की उम्र, आर्थिक शक्ति और मानसिक ऊर्जा लगभग खत्म चुकी होती है। ऐसे में यह सवाल स्वाभाविक है कि देर से मिला न्याय क्या सचमुच न्याय कहलाया जा सकता है? इस मामले में सुप्रीम कोर्ट कई बार निचली अदालतों को सचेत कर चुका है। एक बार फिर से हाईकोर्टों में फैसलों में हो रही देरी पर सुप्रीम कोर्ट गंभीर चिंता जताते हुए स्पष्ट कहा है कि किसी भी मामले में फैसला सुरक्षित रखने के बाद उसे तीन महीने के भीतर सुनाया जाना चाहिए। यदि तीन महीने तक फैसला नहीं आता है, तो हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को वह मामला चीफ जस्टिस के सामने रखना होगा। यह निर्देश केवल प्रशासनिक सुधार नहीं, बल्कि न्यायिक जवाबदेही की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सुप्रीम कोर्ट इसी गंभीर स्थिति पर सख्त रुख अपनाते हुए जो दिशा-निर्देश जारी किए हैं, वे न्याय व्यवस्था में पारदर्शिता, जवाबदेही और समयबद्धता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हैं। अदालत ने साफ कहा है कि फैसला सुरक्षित रखने के बाद उसे अनिश्चितकाल तक लंबित नहीं रखा जा सकता। न्याय केवल होना ही नहीं चाहिए, बल्कि समय पर दिखना भी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का यह निर्देश कि कोई भी फैसला रिजर्व होने के तीन महीने के भीतर सुनाया जाना चाहिए, न्यायिक प्रक्रिया को अनुशासित करने वाला कदम है। यदि तीन महीने के भीतर फैसला नहीं सुनाया जाता, तो संबंधित हाईकोर्ट का रजिस्ट्रार जनरल मामला मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखेगा। मुख्य न्यायाधीश अधिकतम दो सप्ताह का अतिरिक्त समय दे सकते हैं। इसके बाद भी फैसला न आए तो मामला दूसरी बेंच को स्थानांतरित किया जा सकेगा। यह व्यवस्था इसलिए आवश्यक है, है, क्योंकि किसी भी मुकदमे में फैसला सुरक्षित होने का अर्थ यह नहीं कि पक्षकारों की प्रतीक्षा अनंत हो जाए। सबसे गंभीर पहलू उन मामलों का है, जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़े हैं।

जमानत, अग्रिम जमानत, सजा पर रोक या जेल में बंद विचाराधीन कैदियों से जुड़े मामलों में देरी का अर्थ सीधे-सीधे व्यक्ति की स्वतंत्रता पर चोट है। संविधान का अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करता है। यदि किसी व्यक्ति की जमानत याचिका पर बहस पूरी हो चुकी हो और आदेश महीनों तक सुरक्षित रखा जाए, जाए, तो यह केवल तकनीकी देरी नहीं, बल्कि संवैधानिक अधिकारों का हनन है। सुप्रीम कोर्ट ने इसी कारण कहा है कि जमानत से जुड़े मामलों में आदेश उसी दिन सुनाया जाना चाहिए और यदि सुरक्षित रखा जाए तो अगले दिन अवश्य जारी किया जाए। जमानत आदेशों को जेल प्रशासन तक तुरंत पहुंचाने का निर्देश भी बेहद महत्वपूर्ण है। कई बार अदालत से राहत मिलने के बाद भी कागजी प्रक्रिया में देरी के कारण आरोपी या दोषी जेल में ही रह जाता है। यह स्थिति न्याय की आत्मा के विरुद्ध है। यदि अदालत ने रिहाई का आदेश दिया है, तो जेल प्रशासन तक सूचना तुरंत पहुंचनी चाहिए और संबंधित व्यक्ति को उसी दिन या अधिकतम अगले दिन रिहा किया जाना चाहिए, बशर्ते वह किसी अन्य मामले में वांछित न हो या जमानत की शर्तें पूरी करता हो। यह व्यवस्था न्याय को कागज से जमीन तक पहुंचाने की दिशा में जरूरी सुधार है।

सुप्रीम कोर्ट ने केवल फैसला सुनाने की समय सीमा तय नहीं की, बल्कि विस्तृत आदेश अपलोड करने को भी अनिवार्य किया है। अदालत ने कहा है कि ऑपरेटिव पार्ट यानी मुख्य आदेश सुनाने के 15 दिनों के भीतर पूरा फैसला, कारणों सहित, वेबसाइट पर अपलोड होना चाहिए। यदि 15 दिन में विस्तृत फैसला अपलोड नहीं होता, तो पक्षकार आवेदन दे सकते हैं। यदि 30 दिन तक भी आदेश अपलोड न हो, तो पक्षकार मामले को वापस लेने या दूसरी बेंच में सुनवाई के लिए आवेदन कर सकेंगे। इससे न्यायिक आदेशों में पारदर्शिता बढ़ेगी और पक्षकारों को यह समझने का अवसर मिलेगा कि अदालत ने किस आधार पर फैसला दिया। एक अन्य महत्वपूर्ण निर्देश यह है कि बहस पूरी होने और फैसला सुरक्षित रखे जाने की तारीख हाईकोर्ट की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाए। यह छोटी सी व्यवस्था दिखने में तकनीकी लग सकती है, लेकिन इसका प्रभाव बड़ा होगा। इससे पक्षकारों, वकीलों और आम जनता को पता रहेगा कि किस मामले में फैसला कब से सुरक्षित है। जब यह जानकारी सार्वजनिक होगी, तो अनावश्यक देरी पर स्वाभाविक निगरानी बनेगी। झारखंड हाईकोर्ट से जुड़े मामले ने इस समस्या की गंभीरता को उजागर किया। याचिकाकर्ताओं का आरोप था कि उनकी आपराधिक अपीलों पर अंतिम बहस सुनने के बाद दो-तीन वर्षों तक फैसला सुरक्षित रखा गया, लेकिन सुनाया नहीं गया। यह स्थिति किसी भी लोकतांत्रिक न्याय व्यवस्था के लिए चिंताजनक है। अगर किसी दोषी या आरोपी की अपील पर बहस पूरी हो चुकी है और फैसला वर्षों तक सुरक्षित है, तो वह व्यक्ति कानूनी अनिश्चितता में जीने को मजबूर होता है। न्याय की प्रतीक्षा स्वयं एक सजा बन जाती है। देश में करोड़ों मामले लंबित हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी हजारों मामले पेंडिंग हैं और हाईकोर्टों तथा निचली अदालतों में लंबित मामलों की संख्या करोड़ों में है। ऐसे में यह आवश्यक है कि जहां सुनवाई पूरी हो चुकी है, वहां फैसला समय पर आए। न्यायिक विलंब से केवल पक्षकार परेशान नहीं होता, बल्कि समाज में कानून के प्रति भरोसा भी कमजोर होता है।

क्या पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बन पायेगा ?

- **सौरभ वार्ष्णेय**

आज की पत्रकारिताः संघर्ष, जिम्मेदारी और विश्वास की परीक्षा बन कर रह गई है। लोकतंत्र के चार प्रमुख स्तंभों में पत्रकारिता को केवल कहने भर को विशेष स्थान प्राप्त है। पत्रकारिता केवल समाचारों का संकलन और प्रसारण भर नहीं है, बल्कि यह समाज को जागरूक करने, सत्ता से प्रश्न पूछने और जनभावनाओं को अभिव्यक्ति देने का सशक्त माध्यम भी है। किंतु वर्तमान समय में पत्रकारिता अनेक चुनौतियों, दबावों और संघर्षों के दौर से गुजर रही है। ऐसे समय में पत्रकारिता की भूमिका, जिम्मेदारी और विश्वसनीयता पर गंभीर चिंतन आवश्यक हो गया है। अभी ३० मई पत्रकारिता दिवस बीता है लेकिन सत्ता की तरफ से सिर्फ रस्म अदायगी? क्या वाकई पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ संविधान के तहत बन पायेगा या हम पत्रकार बिरादरी सिर्फ गाहे गवाये ढोल पीटते रह जायेंगे? पत्रकारिता सिर्फ और सिर्फ कहने भर का चौथा स्तंभ रह जायेगा। यह एक ज्वलंत विषय है।

आज सूचना क्रांति का युग है। इंटरनेट, सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म ने समाचारों के प्रसार को अत्यंत तेज बना दिया है। जहां पहले एक समाचार को पाठकों तक पहुंचने में घंटों या दिनों का समय लगता था, वहीं अब कुछ ही सेकंड में खबरें दुनिया भर में पहुंच जाती हैं। लेकिन इस तेजी के साथ एक बड़ी चुनौती भी सामने आई है—सत्य और असत्य के बीच अंतर करने की चुनौती। फर्जी खबरें, आधी-अधूरी जानकारी और भ्रामक प्रचार पत्रकारिता की विश्वसनीयता को प्रभावित कर रहे हैं। पत्रकारिता का मूल उद्देश्य निष्पक्षता, सत्यता और जनहित की रक्षा करना है। लेकिन आज कई बार व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा, टीआरपी की दौड़ और राजनीतिक प्रभाव के कारण पत्रकारिता अपने मूल सिद्धांतों से भटकती दिखाई देती है। समाचारों की प्रस्तुति में सनसनीखेजता बढ़ रही है, जबकि तथ्यों की गहराई और निष्पक्ष विश्लेषण को अपेक्षित महत्व नहीं मिल पा रहा है। यह स्थिति लोकतंत्र और समाज दोनों के लिए चिंता का विषय है।

दूसरी ओर, जमीनी स्तर पर कार्य करने वाले पत्रकारों का संघर्ष भी कम नहीं है। अनेक पत्रकार सीमित संसाधनों में काम करते हुए जनसमस्याओं को उजागर करने का प्रयास करते हैं। कई बार उन्हें सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक दबावों का सामना करना पड़ता है। दूर-दराज के क्षेत्रों में कार्यरत संवाददाता जनता और प्रशासन के बीच सेतु का कार्य करते हैं, लेकिन उनके योगदान को हमेशा उचित सम्मान और सुरक्षा नहीं मिल पाती। डिजिटल युग ने पत्रकारिता को नए अवसर भी प्रदान किए हैं। स्वतंत्र पत्रकारिता, वैकल्पिक मीडिया और ऑनलाइन समाचार मंचों ने आम लोगों की आवाज को व्यापक मंच दिया है। अब कोई भी महत्वपूर्ण मुद्दा सोशल मीडिया के माध्यम से राष्ट्रीय बहस का विषय बन सकता है। हालांकि, इस स्वतंत्रता के साथ जिम्मेदारी भी जुड़ी हुई है। बिना सत्यापन के सूचना साझा करना समाज में भ्रम और अविश्वास पैदा कर सकता है।

आज पत्रकारिता के सामने सबसे बड़ी परीक्षा जनता के विश्वास को बनाए रखने की है। पाठक और दर्शक केवल खबर नहीं, बल्कि विश्वसनीय खबर चाहते हैं। पत्रकारों और मीडिया संस्थानों को यह समझना होगा कि उनका सबसे बड़ा पूंजीगत निवेश जनता का विश्वास है। यदि यह विश्वास कमजोर होता है, तो पत्रकारिता का प्रभाव और महत्व दोनों प्रभावित होंगे। आवश्यकता इस बात की है कि पत्रकारिता अपने मूल मूल्यों—सत्य, निष्पक्षता, पारदर्शिता और जनहित—को पुनः केंद्र में स्थापित करे।

खेल के आंगन से हिमालय की ऊंचाइयों तक 8 वर्षीय निक्षा बारोट ने रचा साहस का स्वर्णिम इतिहास

- **कांतिलाल मांडोत**

बचपन को जीवन का सबसे सुंदर और निष्कलुष समय माना जाता है। यह वह आयु होती है जब बच्चे खिलौनों से खेलते हैं। आंगन में दौड़ते हैं। मित्रों के साथ क्रीड़ा करते हैं। हंसते हैं। सीखते हैं और सपनों की रंगीन दुनिया में खोए रहते हैं। आठ वर्ष की आयु तो विशेष रूप से मासूमियत और खेलकूद की उम्र मानी जाती है। इस आयु में किसी बच्चे से यह अपेक्षा नहीं की जाती कि वह जीवन की कठिन चुनौतियों का सामना करेगा या कोई ऐसा कार्य करेगा जिसे बड़े बड़े लोग भी करने से पहले कई बार सोचते हैं। लेकिन पालनपुर की नन्ही बालिका निक्षा बारोट ने अपनी असाधारण इच्छाशक्ति और अद्भुत साहस से इस धारणा को बदल दिया है।

सिर्फ आठ वर्ष की आयु में निक्षा बारोट ने माउंट एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचकर ऐसा कीर्तिमान स्थापित किया है जिस पर पूरे देश को गर्व है। यह उपलब्धि केवल एक ट्रैकिंग यात्रा नहीं है बल्कि यह दृढ़ संकल्प आत्मविश्वास साहस और अनुशासन की ऐसी कहानी है जो हर आयु वर्ग के लोगों को प्रेरित करती है। जिस उम्र में बच्चे अपने घर के आंगन और विद्यालय के खेल मैदान तक सीमित रहते हैं उस उम्र में निक्षा ने हिमालय की कठिन व दुर्गम राहों पर चलकर दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला के चरणों तक पहुंचने का गौरव प्राप्त किया है। निक्षा ने सात दिनों की कठिन यात्रा में लगभग एक सौ तीस किलोमीटर का सफर तय किया। यह दूरी किसी भी व्यक्ति के लिए चुनौतीपूर्ण मानी जाती है। उस पर हिमालय का कठिन भूभाग बर्फीली हवाएं ऊंचाई पर कम होती ऑक्सीजन और लगातार बदलता मौसम यात्रा को और भी कठिन बना देते हैं। लेकिन इस नन्ही बालिका ने किसी भी चुनौती के सामने हार नहीं मानी। उसने अपने छोटे छोटे कदमों से उन रास्तों को पार किया जहां पहुंचना अनेक वयस्कों के लिए भी कठिन माना जाता है।

काठमांडू से लुकला तक की यात्रा के बाद शुरू हुआ यह अभियान नामचे बाजार तेंगबोचे डिंगबोचे लोबुचे और गोरक्षेप जैसे कठिन पड़ावों से होकर गुजरा। हर पड़ाव अपने भीतर नई चुनौतियां समेटे हुए था। कहीं तीखी चढ़ाई थी तो कहीं बर्फ से ढके रास्ते। कहीं तेज ठंडी हवाएं थीं तो कहीं सांस लेने में कठिनाई पैदा करने वाली ऊंचाई। लेकिन निक्षा ने अद्भुत धैर्य और आत्मविश्वास का परिचय देते हुए हर बाधा को पार किया और आखिरकार सत्रह हजार पांच सौ अट्ठानवे फीट की ऊंचाई पर स्थित एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंच गई। निक्षा की यह उपलब्धि इसलिए भी विशेष है क्योंकि इसमें केवल शारीरिक क्षमता ही नहीं बल्कि मानसिक दृढ़ता की भी आवश्यकता होती है।

न्याय में देरी न्याय की हत्या के समतुल्य है मीलार्ड!

- **मनोज कुमार अग्रवाल**

अगली पेशी अगले साल यह देश की अदालतों में होता रहा है लेकिन हाल ही मे सुप्रीम कोर्ट ने न्याय में देरी को रोकने और पारदर्शिता लाने के लिए सभी हाईकोर्ट्स को सख्त निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत, सुनवाई के बाद सुरक्षित रखे गए सभी फैसले अधिकतम तीन महीने के भीतर सुनाने अनिवार्य हैं। वहीं, जमानत से जुड़े मामलों में 24 घंटे के भीतर आदेश जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। ऐसा पहली बार नहीं है पूर्व में भी पूर्व सीजेआई सरकार और सत्तारूढ़ पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र और सत्तारूढ़ नेता समय समय पर देश की न्याय व्यवस्था में देरी की समस्या का समाधान खोजने का वायदा दावा और बयान करते रहे हैं लेकिन हर बार ढाक के वहीं तीन पात।

न्याय मे देरी का सिलसिला नया नहीं है, लेकिन जब अदालतें बहस पूरी होने के बाद भी वर्षों तक फैसले सुरक्षित रखती हैं, तो यह केवल प्रशासनिक लापरवाही नहीं रह जाती, बल्कि न्याय के मूल सिद्धांत पर सवाल खड़ा करती है। यह वह कड़वी सच्चाई है कि अदालतों में करोड़ों मामले लंबित हैं और न्याय की उम्मीद लिए लोग तारीख पर तारीख काटते रहते हैं। कई मामलों में फैसला तब आता है, जब पीड़ित की उम्र, आर्थिक शक्ति और मानसिक ऊर्जा लगभग खत्म चुकी होती है। ऐसे में यह सवाल स्वाभाविक है कि देर से मिला न्याय क्या सचमुच न्याय कहलाया जा सकता है? इस मामले में सुप्रीम कोर्ट कई बार निचली अदालतों को सचेत कर चुका है। एक बार फिर से हाईकोर्टों में फैसलों में हो रही देरी पर सुप्रीम कोर्ट गंभीर चिंता जताते हुए स्पष्ट कहा है कि किसी भी मामले में फैसला सुरक्षित रखने के बाद उसे तीन महीने के भीतर सुनाया जाना चाहिए।

यदि तीन महीने तक फैसला नहीं आता है, तो हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को वह मामला चीफ जस्टिस के सामने रखना होगा। यह निर्देश केवल प्रशासनिक सुधार नहीं, बल्कि न्यायिक जवाबदेही की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सुप्रीम कोर्ट इसी गंभीर स्थिति पर सख्त रुख अपनाते हुए जो दिशा-निर्देश जारी किए हैं, वे न्याय व्यवस्था में पारदर्शिता, जवाबदेही और समयबद्धता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हैं। अदालत ने साफ कहा है कि फैसला सुरक्षित रखने के बाद उसे अनिश्चितकाल तक लंबित नहीं रखा जा सकता। न्याय केवल होना ही नहीं चाहिए, बल्कि समय पर दिखना भी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का यह निर्देश कि कोई भी फैसला रिजर्व होने के तीन महीने के भीतर सुनाया जाना चाहिए, न्यायिक प्रक्रिया को अनुशासित करने वाला कदम है। यदि तीन महीने के भीतर फैसला नहीं सुनाया जाता, तो संबंधित हाईकोर्ट का रजिस्ट्रार जनरल मामला मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखेगा। मुख्य न्यायाधीश अधिकतम दो सप्ताह का अतिरिक्त समय दे सकते हैं। इसके बाद भी फैसला न आए तो मामला दूसरी बेंच को स्थानांतरित किया जा सकेगा। यह व्यवस्था इसलिए आवश्यक है, है, क्योंकि किसी भी मुकदमे में फैसला सुरक्षित होने का अर्थ यह नहीं कि पक्षकारों की प्रतीक्षा अनंत हो जाए। सबसे गंभीर पहलू उन मामलों का है, जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़े हैं। जमानत, अग्रिम जमानत, सजा पर रोक या जेल में बंद विचाराधीन कैदियों से जुड़े मामलों में देरी का अर्थ सीधे-सीधे व्यक्ति की स्वतंत्रता पर चोट है। संविधान का अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करता है। यदि किसी व्यक्ति की जमानत याचिका पर बहस पूरी हो चुकी हो और आदेश महीनों तक सुरक्षित रखा जाए, जाए, तो यह केवल तकनीकी देरी नहीं, बल्कि संवैधानिक अधिकारों का हनन है।

सुप्रीम कोर्ट ने इसी कारण कहा है कि जमानत से जुड़े मामलों में आदेश उसी दिन सुनाया जाना चाहिए और यदि सुरक्षित रखा जाए तो अगले दिन अवश्य जारी किया जाए। जमानत आदेशों को जेल प्रशासन तक तुरंत पहुंचाने का निर्देश भी बेहद महत्वपूर्ण है। कई बार अदालत से राहत मिलने के बाद भी कागजी प्रक्रिया में देरी के कारण आरोपी या दोषी जेल में ही रह जाता है। यह स्थिति न्याय की आत्मा के विरुद्ध है। यदि अदालत ने रिहाई का आदेश दिया है, तो जेल प्रशासन तक सूचना तुरंत पहुंचनी चाहिए और संबंधित व्यक्ति को उसी दिन या अधिकतम अगले दिन रिहा किया जाना चाहिए, बशर्ते वह किसी अन्य मामले में वांछित न हो या जमानत की शर्तें पूरी करता हो। यह व्यवस्था न्याय को कागज से जमीन तक पहुंचाने की दिशा में जरूरी सुधार है।

स्वामी दिल्ली वार्ता मीडिया प्राइवेट लिमिटेड, प्रकाशक एवं मुद्रक शमीम अहमद द्वारा आला प्रिंटिंग प्रेस 3636, कटरा दीना बेग लाल कुंआ, दिल्ली-110006 या अखबार प्रिंटर 1534 कासिम जान स्ट्रीट, बल्लीमारान, दिल्ली-110006 से मुद्रित व 12/596 वेस्ट गुरू अंगद नगर ईस्ट, दिल्ली-1100092 से प्रकाशित। संपादक - सलीम अहमद

कार पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर पूर्व प्रधान की हत्या

• आगरा, एजेंसी।

उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में प्रधानी चुनाव को लेकर चल रही रंजिश में पूर्व प्रधान की कार को घेर कर ताबड़तोड़ फायरिंग में पूर्व प्रधान की हत्या कर दी गई। वही प्रधान का भाई गंभीर रूप से घायल है और उपचाराधीन है, परिजनों द्वारा घटना के लिए वर्तमान प्रधान पर आरोप लगाया है।

उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में सोमवार की रात करीब 9:30 बजे ग्राम शाहपुर गुर्जर थाना चित्राहट निवासी दो सगे भाई अवनीश यादव (50),उपेंद्र यादव उर्फ मलिक यादव (45) वर्ष पुत्रगण किताब सिंह आगरा से कार द्वारा कस्बा जैतपुर जा रहे थे। रास्ते मे ग्राम प्यामपुरा थाना क्षेत्र जैतपुर के समीप एक कार एवं मोटरसाइकिल द्वारा पूर्व प्रधान अवनीश की कार का पीछा कर उसे घेर लिया गया कार असंतुलित होकर रुक गई। गाड़ी रुकते ही इन लोगों द्वारा पूर्व प्रधान की कार पर फायरिंग शुरू कर दी, जिससे अवनीश और उसके भाई उपेंद्र गोलियां लगने से गंभीर रूप से घायल हो गए। फायरिंग की सूचना पर पहुंची पुलिस द्वारा घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जैतपुर पर भर्ती कराया गया जहां चिकित्सकों द्वारा अवनीश यादव को मृत घोषित कर दिया गया। घायल उपेंद्र यादव का इलाज एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा में चल रहा है। मृतक अवनीश के शव को पोस्टमार्टम हेतु एस.एन मेडिकल कॉलेज आगरा भेज दिया गया है। मृतक अवनीश गांव शाहपुर गुर्जर में 2016 में प्रधान रह चुके हैं। इस घटना में इंद्रराज सिंह यादव पुत्र राजवीर सिंह, छोटे पुत्र इंद्रराज सिंह, निवासी ग्राम शाहपुर गुर्जर आदि द्वारा फायरिंग किए जाने का आरोप लगाया जिसमें फायरिंग में पूर्व प्रधान अवनीश की मौत हो गई और उसके भाई भाई उपेंद्र गंभीर रूप से घायल है। मृतक अवनीश यादव वर्ष 2016 में शाहपुर गुर्जर के प्रधान थे, वर्तमान में इंद्रराज यादव की पत्नी सुनीता देवी ग्राम शाहपुर गुर्जर की प्रधान है।

मृतक उपेंद्र यादव के भतीजे टिंकू ने बताया कि उनके चाचा की गांव के दूसरे पक्ष इन्द्रराज यादव से रंजिश चल रही है, इसी रंजिश की वजह से चाचा और उनका परिवार गांव में नहीं रहता है। जैतपुर वाले मकान में रहता है। सोमवार को शाम चाचा अवनीश और उपेंद्र आगरा से तारीख कर गांव शाहपुर लौटे थे। गांव में खेती-बाड़ी का काम देखकर रात में जैतपुर के लिए कार से वापस लौट गए। इसी दौरान विपक्षी गण इंद्रराज पक्ष द्वारा उनकी कार पर फायरिंग कर चाचा की हत्या कर दी गई।

पोस्टमार्टम हाउस पर पहुंचे ग्रामीणों ने बताया कि पिछले वर्ष 2025 में 24 जनवरी को प्रधानी चुनावी रंजिश को लेकर उपेंद्र उर्फ मलिक के साथ आरोपी इंद्रराज सिंह पक्ष द्वारा रास्ते में रोककर मारपीट की एवं पेट के नीचे गोली मार दी थी। घटना के सम्बन्ध में थाना बाह पर इंद्र राज सिंह व उसके सहयोगियों के खिलाफ मु.अ.सं. 06/25 पंजीकृत किया गया था जिसमे एक आरोपी विजय प्रताप उर्फ रोली को जेल भेज दिया गया था।

इसी मुकदमे के संबंध में मृतक अवनीश और भाई उपेंद्र तारीख करने सोमवार को आगरा गए हुए थे। दोनों पक्षों के मध्य प्रधानी को लेकर रंजीत चली आ रही थी । मंगलवार को घटना के संबंध में जानकारी देते हुए अभिषेक अग्रवाल डीसीपी पूर्वी जोन ने बताया कि घटना में प्रधानी को लेकर उपजी रंजिश में हत्या की बात सामने आई है। हमलावरों की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर दी गई है। जल्दी ही गिरफ्तारी की जाएगी। प्राथमिकी प्राप्त कर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है।पुलिस द्वारा विधिक कार्रवाई की जा रही है

अछल्दा में राजधानी एक्सप्रेस की चपेट में आने से युवक की मौत, 15 मिनट रुकी ट्रेन

• औरैया, एजेंसी।

दिल्ली-हावड़ा रेल मार्ग पर उत्तर प्रदेश के औरैया जनपद में स्थित अछल्दा स्टेशन के पास सोमवार रात एक दर्दनाक हादसे में अज्ञात युवक की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। घटना के बाद ट्रैक पर शव पड़े होने के कारण राजधानी एक्सप्रेस को करीब 15 मिनट तक रोकना पड़ा।

जानकारी के अनुसार, सोमवार रात करीब 9:07 बजे 12310 राजेंद्र नगर तेजस राजधानी एक्सप्रेस के लोको पायलट ने अछल्दा स्टेशन मास्टर को सूचना दी कि डाउन लाइन पर खंभा संख्या 1117/16 के पास एक व्यक्ति ट्रेन की चपेट में आ गया है। सूचना मिलते ही रेलवे प्रशासन में हड़कंप मच गया।

ट्रैक पर शव पड़े होने के कारण कानपुर की ओर जा रही राजधानी एक्सप्रेस को आउटर के होम सिग्नल पर रोकना पड़ा। स्टेशन मास्टर की सूचना पर मौके पर पहुंचे पॉइंट मैन ने ट्रैक से शव को हटाया, जिसके बाद लगभग 15 मिनट बाद ट्रेन को आगे के लिए रवाना किया गया। मृतक की उम्र लगभग 35 वर्ष बताई जा रही है। उसके शरीर पर केवल नीले रंग का जांघिया था, जबकि घटनास्थल पर नारंगी रंग की शर्ट, नीले रंग का लोवर और एक लाल बेल्ट भी पड़ी मिली। युवक की पहचान समाचार लिखे जाने तक नहीं हो सकी थी। घटना की सूचना स्टेशन मास्टर द्वारा जीआरपी फफूंद को दी गई। जीआरपी प्रभारी विक्रम सिंह ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई।

सरकार पूर्व सैनिकों के लिए नई शस्त्र लाइसेंस नीति पर कर रही मंथन

• देहरादून, एजेंसी।

राज्य सरकार पूर्व सैनिकों के नई शस्त्र लाइसेंस नीति पर विचार कर रही है। इसके लिए गृह विभाग में विचार-विमर्श चल रहा है। पूर्व सैनिकों के बढ़ते जमीनी विवादों को सुलझाने, उन्हें निशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराने पर भी प्रदेश की धामी सरकार में विमर्श का दौर चल रहा है। उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण सलाहकार परिषद के अध्यक्ष कर्नल (रि.) अजय कोठियाल का कहना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ पूर्व सैनिक कल्याण विषय पर कई दौर का विमर्श हुआ है। शासन स्तर पर भी मुख्यमंत्री धामी के निर्देश पर बहुत से विषयों पर संवाद हुआ है। उन्हें उम्मीद है कि सरकार इस पर निर्णय लेने जा रही है।

कोठियाल कहते हैं कि समान नागरिक पेंशन योजना से लाखों पूर्व सैनिकों को फायदा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्र को एक मजबूत सुरक्षा कवच तो दिया ही है, साथ ही पूर्व सैनिकों के लिए भी बहुत सी ऐसी योजनाएं दी हैं जिसकी मांग हम सर्विस में रहते हुए कई साल से कर रहे थे।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि सरकार पूर्व सैनिकों, पूर्व अर्ध सैनिकों के लिए एक सेवक के रूप में काम कर रही है। सरकार इनके बेहतर भविष्य के लिए नए प्रस्तावों पर विचार कर रही है। देवभूमि उत्तराखंड में भव्य सैन्यधाम की स्थापना का कार्य अंतिम चरण में है। पूर्व सैनिकों में रिटायरमेंट के बाद ये भावना रहती है कि उनके पास आत्म रक्षा के लिए शस्त्र हो, सैनिक की सेवा अवधि में उनके कंधे पर लटकी बंदूक से उनका एक अलग तरह से रिश्ता रहता जो उन्हें देश की सुरक्षा के लिए हर समय तैयार रहने को प्रेरित करता है। पूर्व सैनिकों की ये मांग रही है कि उन्हें शस्त्र लाइसेंस प्राथमिकता से दिए जाए। उनकी इस मांग पर धामी सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। धामी सरकार ने अग्निवीर योजना से रिटायर हो कर आ रहे सैनिकों के लिए 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण पुलिस, जेल प्रहरी, वन सुरक्षा में दिए जाने की घोषणा की हुई है। सरकार ने इन सभी विभागों को कह दिया है कि वे आने वाले दिसंबर माह से पहले नौकरियां के लिए रिक्तियां निकालें। सरकार का ये भी मानना ह कि आंतरिक सुरक्षा एजेंसियों को सेना द्वारा प्रशिक्षित और अनुशासित युवा मिलने से उनका एक बड़ा खर्चा कम हो जाएगा। धामी सरकार ने प्राइवेट सेक्टर में भी ये संदेश दिया है कि वे राष्ट्रहित में अग्निवीर पूर्व सैनिकों के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करें। इसके साथ इनके लिए स्व रोजगार के लिए भी सरकार योजना बना रही है।

खेल मंत्री ने समतलीकरण कार्यों का निरीक्षण कर अधिकारियों को दिए निर्देश

• हल्द्वानी, एजेंसी।

खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि गौलापार स्थित प्रस्तावित खेल विश्वविद्यालय परिसर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने समतलीकरण कार्यों का निरीक्षण कर अधिकारियों को दिए निर्देश। वन विभाग से भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद खेल मंत्री रेखा आर्या पहली बार गौलापार स्थित प्रस्तावित खेल विश्वविद्यालय परिसर पहुंचीं। इस दौरान वह भावुक नजर आईं और उन्होंने भूमि की पावन मिट्टी को माथे से लगाकर नमन किया।

निरीक्षण के दौरान खेल मंत्री ने विश्वविद्यालय परिसर में चल रहे भूमि समतलीकरण कार्यों का जायजा लिया और अधिकारियों को गुणवत्ता के साथ निर्धारित समयसीमा के भीतर कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। वर्तमान में परिसर में भूमि समतलीकरण, झाड़ियों की सफाई और अन्य प्रारंभिक कार्य तेजी से किए जा रहे हैं। इस अवसर पर रेखा आर्या ने कहा कि यह भूमि केवल जमीन का एक टुकड़ा नहीं, बल्कि उत्तराखंड के लाखों खिलाड़ियों के सपनों का आधार है। उन्होंने कहा, 'एक खेल मंत्री के रूप में मेरे लिए यह स्थान किसी तीर्थस्थल से कम नहीं है। यहीं से प्रदेश के खिलाड़ियों के सपनों को नई उड़ान मिलेगी और भविष्य के राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी तैयार होंगे।' उन्होंने कहा कि मिट्टी को माथे से लगाते समय उनके मन में उन खिलाड़ियों का संघर्ष, समर्पण और उम्मीदें उभर आईं, जो वर्षों से बेहतर खेल सुविधाओं और अवसरों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यह विश्वविद्यालय प्रदेश के खेल भविष्य की मजबूत नींव साबित होगा। खेल मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व और दृढ़ संकल्प के चलते यह महत्वाकांक्षी परियोजना अब धरातल पर उतर रही है। उन्होंने विश्वास जताया कि खेल विश्वविद्यालय उत्तराखंड को देश के अग्रणी खेल राज्यों की श्रेणी में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। निरीक्षण के दौरान खेल उपनिदेशक राशिका सिद्दकी, जिला खेल अधिकारी निर्मला पंत, वरुण बेनीवाल, सतीश कुमार सहित विभागीय अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे।

दलित युवक की हत्या के दोषी दो भाइयों को आजीवन कारावास

• गाजियाबाद, एजेंसी।

उत्तर प्रदेश के जनपद गाजियाबाद के विशेष न्यायाधीश (एससी-एसटी एक्ट) जितेंद्र मिश्रा की अदालत ने सोमवार को 10 वर्ष बाद दलित युवक की हत्या के आरोपित दो भाई उमेश शर्मा और अंकुर शर्मा को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। दोनों भाईयों पर 11-11 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा नहीं करने पर आरोपितों को ढाई-ढाई माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

वरिष्ठ विशेष लोक अभियोजक अखिलेश कुमार ने बताया कि जटवाड़ा कालोनी निवासी नरेंद्र कुमार की गैस बिल्डिंग क्षेत्र में दुकान थी। कारोबारी संबंधों के चलते उसने उमेश शर्मा से तीन हजार रुपये उधार लिए थे। व्यापार में घाटा होने के कारण वह समय पर रकम वापस नहीं कर सका। 31 जुलाई 2016 को दोपहर करीब डेढ़ बजे उमेश का नरेंद्र के पास फोन आया और उसने लोहिया नगर स्थित आटो स्टैंड के पास बीयर की दुकान के निकट पहुंचकर पैसों का हिसाब करने के लिए कहा। नरेंद्र अपने छोटे भाई राजकुमार के साथ मौके पर पहुंचा तो वहां उमेश, उसका भाई अंकुर और एक अन्य व्यक्ति मौजूद थे। इस दौरान पैसों की मांग को लेकर कहासुनी हुई।

नरेंद्र ने 10 दिन का समय मांगा, जिससे आरोपित नाराज हो गए। इसके बाद उमेश और अंकुर ने लोहे की राड और बीयर की बोतल से हमला कर दिया। नरेंद्र किसी तरह बच गया, लेकिन उसका भाई राजकुमार गंभीर रूप से घायल हो गया। वह मौके पर ही बेहोश होकर गिर गया। घटना के बाद नरेंद्र घायल भाई को लेकर सिहानी गेट थाने लेकर पहुंचा, जहां उसकी तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया।

पुलिस ने शुरू में भारतीय दंड संहिता की धारा 307 यानी हत्या के प्रयास के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की।उपचार के दौरान राजकुमार की मौत हो जाने पर मामले में हत्या की धाराएं जोड़ दी गईं। विवेचना के दौरान पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने मृतक की खून से सनी शर्ट बरामद की।

विकास की सौगात

सीएम योगी आदित्यनाथ ने फाजिल नगर का नाम पावागढ़ करने का किया ऐलान

• कुशीनगर, एजेंसी।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को कुशीनगर पहुंचे। उन्होंने यहां 424 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली 278 परियोजनाओं का लोकार्पण/शिलान्यास किया। तमकुही राज कुशीनगर में आयोजित इस कार्यक्रम में उन्होंने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र, स्वीकृति पत्र, चेक वितरण करते हुए उनसे सरकारी योजनाओं से जुड़ कर लाभान्वित होने का आह्वान किया। उन्होंने फाजिल नगर का नाम पावागढ़ करने का ऐलान करते हुए कहा नामकरण का प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है।

तमकुही राज में आयोजित समारोह में उन्होंने कहा कि यह भगवान बुद्ध और भगवान महावीर की भूमि है। पहली बार आया हूं और इस भूमि को नमन करता हूं। उन्होंने पूर्ववर्ती सरकारों में बनाए जंगल राज का विस्तार से जिक्र किया। कहा कि यहां का किसान परेशान था, क्योंकि वह मेहनत तो करता था लेकिन उसे उपज का दाम नहीं मिलता था। इतना ही नहीं सड़क, सुरक्षा, बिजली और अस्पताल नहीं थे। उन्होंने अपनी सरकार की आवास, राशन, आयुष्मान कार्ड, शौचालय समेत कई कल्याणकारी योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि फाजिल नगर का नाम पावागढ़ करने का प्रस्ताव बन गया है। हम लोग फाजिल नगर क्यों कहेंगे। यह पावन भूमि है और इसका महत्व बनाए रखना जरूरी है।

इस कार्यक्रम में जिले के प्रभारी मंत्री दिनेश प्रताप सिंह, सांसद रवि किशन, सांसद शंशाक मणि त्रिपाठी, विधायक सुरेंद्र कुशवाहा, सावित्री जायसवाल, दुर्गेश राय, विवेकानंद पांडेय, विनय प्रकाश गौड, यूपी एग्रो के उपाध्यक्ष जगदीश मिश्र सहित बडी संख्या में जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी को सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग आए थे और इनमें महिलाओं व युवाओं की संख्या अधिक रही।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जन्मोत्सव पर काशी में सेवा का महा-अभियान, 500 यूनिट रक्तदान का लक्ष्य : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ महाराज के 54वें जन्मदिवस (5 जून) को लेकर काशी में सेवा और समर्पण का माहौल देखने को मिल रहा है। इस अवसर पर त्रिशक्ति सेवा फाउंडेशन और हिन्दू युवा वाहिनी, वाराणसी की ओर से एक विशाल स्वैच्छिक रक्तदान शिविर आयोजित करने की तैयारी है। आयोजन में इस बार 500 यूनिट से अधिक रक्तदान करने का लक्ष्य रखा गया है।

रक्तदान महाअभियान की तैयारियों को लेकर मंगलवार को अंतिम रूप देने के लिए संगठन के पदाधिकारी कबीरचौरा स्थित राजकीय महिला अस्पताल के एमसीएच विंग पहुंचे, जहां उन्होंने अस्पताल प्रशासन और चिकित्सकों के साथ बैठक कर रक्तदान शिविर में आने वाले लोगों की सुविधा, स्वास्थ्य जांच और अन्य व्यवस्थाओं को लेकर विस्तृत चर्चा की। वाहिनी के मंडल प्रभारी अंबरीश सिंह 'भोला' ने बताया कि मुख्यमंत्री के जन्मदिन और 500 यूनिट रक्तदान के संकल्प को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ युवाओं में उत्साह है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन हर वर्ष सेवा कार्यों के माध्यम से मनाया जाता है और इस बार भी उसी परंपरा को आगे बढ़ाया जा रहा है। पिछले वर्षों में भी जनता और युवाओं का सहयोग मिला है।

संक्षिप्त खबरें

देवप्रयाग में गंगा नदी में गिरी कार, दो लोगों की मौत, रेस्क्यू अभियान जारी

देवप्रयाग, एजेंसी। उत्तराखंड के टिहरी जिले के देवप्रयाग में मंगलवार को ऋषिकेश-बदरीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक कार अनियंत्रित होकर खाई में गिरते हुए गंगा नदी में समा गई। रेस्क्यू टीमों ने मौके से दो लोगों के शव बरामद किए हैं, जबकि गंभीर रूप से घायल एक व्यक्ति को सुरक्षित रेस्क्यू कर अस्पताल भेजा गया है। अन्य संभावित लापता लोगों की तलाश के लिए राज्य आपदा प्रतिवादन बल (एसडीआरएफ), पुलिस और जल पुलिस की टीमें सर्च एवं रेस्क्यू अभियान चला रही हैं। पुलिस के अनुसार देवप्रयाग में सैनिक होटल और पंत गांव के बीच डंपिंग जोन के समीप तेज रफ्तार इनोवा कार सड़क किनारे लगे मजबूत सुरक्षा पैराफिट को तोड़ते हुए खाई में नीचे गंगा नदी में जा गिरा। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक हादसा इतना भीषण था कि कार सीधे नदी की तेज धाराओं में समा गई। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस, जल पुलिस और राज्य आपदा प्रतिवादन बल की टीमें तत्काल मौके पर पहुंची। रेस्क्यू अभियान के दौरान दो लोगों के शव बरामद किए गए, जबकि गंभीर रूप से घायल एक व्यक्ति को सुरक्षित बाहर निकालकर अस्पताल भेजा गया है। गंगा नदी का तेज बहाव राहत एवं बचाव कार्य में चुनौती बना हुआ है। जल पुलिस के गोताखोर और एसडीआरएफ की टीमें लगातार खोजबीन में जुटी हुई हैं। पुलिस प्रशासन के अनुसार वाहन में सवार लोगों की वास्तविक संख्या और दुर्घटना से जुड़े अन्य कारणों की जानकारी जुटाई जा रही है।

दुकान में लगी आग,पाया काबू

हल्द्वानी, एजेंसी। शहर के तिकोनिया क्षेत्र स्थित अंग्रेजी एवं देशी शराब की दुकान में सोमवार देर रात आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। आग की लपटें उठती देख राहगीरों ने तत्काल दमकल विभाग को सूचना दी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। मिली जानकारी के अनुसार देखते ही देखते पूरी दुकान को आग अपनी चपेट में ले लिया। आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड के तीन वाहनों को लगाया गया। काफी मशक्कत के बाद आग को नियंत्रित किया जा सका।घटना के दौरान दुकान के भीतर एक भरा हुआ गैस सिलेंडर भी मौजूद था, जिससे बड़ा हादसा होने की आशंका बनी हुई थी। दमकल कर्मियों ने साहस का परिचय देते हुए सिलेंडर को सुरक्षित बाहर निकाल लिया, जिससे संभावित विस्फोट और बड़े नुकसान को टाल दिया गया।प्रारंभिक जानकारी के अनुसार आग से दुकान में रखा शराब का स्टॉक और अन्य सामान जलकर राख हो गया। आग लगने का संभावित कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है, हालांकि वास्तविक कारणों का पता लगाने के लिए जांच की जा रही है।

उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदलेगा, आंधी-तूफान और बिजली गिरने का अलर्ट

देहरादून, एजेंसी। उत्तराखंड में मौसम एक बार फिर करवट लेने जा रहा है। राज्य के अधिकांश जिलों में मंगलवार को गरज-चमक के साथ बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुसार पर्वतीय जिलों के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। वहीं 4200 मीटर और उससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात की भी संभावना है। दूसरी ओर मैदानी जिलों में कहीं-कहीं बहुत हल्की से हल्की बारिश और गर्जन के साथ वर्षा हो सकती है।विभाग ने राज्यभर के लिए 'वॉच' श्रेणी की चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि कई स्थानों पर आकाशीय बिजली चमकने और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से झोंकेदार हवाएं चलने की आशंका है। लोगों को खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों में अधिकतम तापमान सामान्य से काफी कम जबकि पर्वतीय क्षेत्रों में सामान्य से अत्यंत कम दर्ज किया गया। हालांकि अगले दो से तीन दिनों में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी होने की संभावना है। देहरादून में मंगलवार को आसमान मुख्यतः साफ से लेकर आंशिक रूप से बादलों से घिरा रह सकता है। शाम के समय गरज वाले बादल विकसित होने तथा हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। शहर का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है।

भतीजी को बदनाम करने के लिए एआई से अश्लील तस्वीरें बनाकर वायरल करने का आरोप

कानपुर, एजेंसी। चकेरी थाना क्षेत्र में एक महिला ने अपने देवर पर 13 वर्षीय भतीजी की छवि धूमिल करने के उद्देश्य से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) की मदद से आपत्तिजनक तस्वीरें तैयार कर उन्हें वायरल करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने सोमवार को तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़िता के अनुसार, परिवार में बीते दिनों विवाद हुआ था, जिसके बाद आरोपी ने उन्हें और उनकी बेटी को बदनाम करने की धमकी दी थी। आरोप है कि इसी रंजिश के चलते आरोपित ने किशोरी की तस्वीर का दुरुपयोग करते हुए उसे पड़ोस के एक युवक के साथ आपत्तिजनक रूप में प्रदर्शित करने वाली तस्वीरें तैयार कीं और उन्हें विभिन्न माध्यमों से प्रसारित कर दिया। तस्वीरें प्रसारित होने की जानकारी मिलने पर परिवार के लोगों ने पड़ताल की तो संदेह देवर पर गया। पीड़ित पक्ष का कहना है कि घटना के बाद किशोरी मानसिक रूप से परेशान है और परिवार को सामाजिक स्तर पर भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। महिला ने पुलिस को बताया कि आरोपित पूर्व में भी परिवार के साथ विवाद करता रहा है। उनका आरोप है कि पुरानी रंजिश निकालने के लिए उसने यह साजिश रची। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। चकेरी थाना प्रभारी अजय प्रकाश मिश्र ने बताया कि वायरल तस्वीरों, मोबाइल फोन और सोशल मीडिया खातों की तकनीकी जांच कराई जा रही है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी।

जनगणना ड्यूटी में जा रहे प्रधानाध्यापक की सड़क हादसे में मौत

नोएडा, एजेंसी। थाना दनकौर क्षेत्र के सरकपुर गांव निवासी एक स्कूल के प्रधानाध्यापक की सोमवार को जनगणना ड्यूटी पर जाते समय सड़क हादसे में मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। परिजनों ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ पुलिस को शिकायत दी है। थाना दनकौर के प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार सिंह ने बताया कि सरकपुर गांव निवासी बालकिशन बुलंदशहर जिले के खुर्जा क्षेत्र के हसनपुर लडुकी गांव स्थित कंपोजिट विद्यालय में प्रधानाध्यापक के पद पर तैनात थे। सोमवार सुबह वह अपनी बाइक से जनगणना ड्यूटी के लिए घर से निकले थे। जब वह दनकौर कोतवाली क्षेत्र के चांगोली मोड़ के पास पहुंचे, तभी किसी अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही वह सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद वाहन चालक मौके से फरार हो गया। राहगीरों द्वारा सूचना दिए जाने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल शिक्षक को तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया। चिकित्सकों ने उनकी गंभीर हालत को देखते हुए उपचार शुरू किया, लेकिन अधिक चोट लगने के कारण उन्हें बचाया नहीं जा सका। कोतवाली प्रभारी ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। उन्होंने बताया कि पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाल रही है ताकि दुर्घटना करने वाले वाहन और उसके चालक की पहचान की जा सके।

संक्षिप्त खबरें

होटल संचालक पर फायरिंग, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात; जमीनी विवाद का मामला

रेवाड़ी, एजेंसी। रेवाड़ी जिले में एक होटल संचालक की कार पर फायरिंग कर जान से मारने की कोशिश किए जाने का मामला सामने आया है। पूरी घटना होटल में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। होटल के संचालक दीपक यादव ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि रविवार रात करीब 10 बजे उनकी बलेनो कार होटल के बाहर खड़ी थी। इसी दौरान अज्ञात व्यक्ति ने उनकी कार पर गोली चला दी। फायरिंग की आवाज सुनकर दीपक यादव और होटल का स्टाफ बाहर पहुंचा। जांच के दौरान घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद होने की बात सामने आई, जिसके आधार पर पुलिस आरोपियों की पहचान में जुटी है। पीड़ित ने आरोप लगाया कि जमीनी विवाद के चलते कुछ लोग उन्हें लगातार धमकियां दे रहे हैं। उन्होंने अमन धामलावास समेत कुछ अन्य लोगों पर संदेह जताते हुए कहा कि पहले भी होटल गिराने और जान से मारने की धमकियां मिल चुकी हैं। होटल संचालक ने बताया कि इससे पहले भी होटल में तोड़फोड़ और कर्मचारियों के साथ मारपीट की शिकायत थाना रामपुरा में दर्ज कराई गई थी। करीब चार-पांच माह पहले भी उन पर जानलेवा हमला हुआ था। शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी की तलाश की जा रही है।

रोहतक में इनेलो का जोरदार प्रदर्शन: विधायक अर्जुन चौटाला की एसपी से हुई झड़प

रोहतक, एजेंसी। महंगाई को लेकर सोमवार को इंडियन नेशनल लोकदल कार्यकर्ताओं ने रोहतक शहर में जोरदार प्रदर्शन किया। रानिया से विधायक अर्जुन सिंह चौटाला की अगुवाई में यह प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन करते हुए इनेलो कार्यकर्ता लघु सचिवालय पहुंचे और डीसी को ज्ञापन देने की मांग करते रहे लेकिन डीसी रोहतक ज्ञापन लेने नहीं पहुंचे जिसके बाद पार्टी कार्यकर्ताओं ने लघु सचिवालय में ही धरना दिया। इस दौरान पुलिस ने लघु सचिवालय के गेट बंद कर दिए और मामला और भी गरमा गया। इस दौरान करीब 15 मिनट तक पुलिस और विधायक अर्जुन चौटाला के बीच बहस हुई। हंगामा बढ़ता देख डीसी सचिन गुप्ता एसपी गौरव राजपुरोहित को लेकर मौके पर पहुंचे। एसपी ने विधायक को समझाने का प्रयास किया।आरोप है कि विधायक ने एसपी को अपशब्द बोले। इस पूरी घटना का वीडियो भी सामने आया है।

स्कूटी पर जा रहे अध्यापक की गला काटकर हत्या, बेटी को ट्यूशन छोड़कर लौट रहे थे जगदीप

अमृतसर (पंजाब), एजेंसी। अमृतसर के नारायणगढ़ इलाके में अपनी बेटी को ट्यूशन छोड़कर लौट रहे एक अध्यापक की अज्ञात हमलावरों ने हत्या कर दी। मृतक की पहचान गांव तलवंडी निवासी जगदीप सिंह के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार जगदीप सिंह सोमवार दोपहर करीब 2 बजे अपनी बेटी को एक्टिवा पर ट्यूशन छोड़ने गए थे। वापस लौटते समय नारायणगढ़ के नजदीक कुछ अज्ञात लोगों ने उन्हें घेर लिया। हमलावरों ने तेजधार हथियारों से उन पर हमला किया और उनका गला काट दिया। गंभीर चोटों और अधिक खून बहने के कारण उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू की। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया तथा आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी है। हमलावरों की पहचान और वारदात के कारणों का पता लगाने के लिए जांच जारी है। इलाके में दिनदहाड़े हुई इस घटना से लोगों में दहशत का माहौल है। पुलिस का कहना है कि सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की जांच की जा रही है।

युवक की हत्या कर शव को एक्टिवा पर लेकर घूमे, सुनसान जगह पर फेंका; दो गिरफ्तार

अमृतसर (पंजाब), एजेंसी। दोस्तों ने अपने एक अन्य साथी की गला घोटकर हत्या कर दी और इसके बाद शव को एक्टिवा पर लाद कर एक सुनसान जगह पर फेंक दिया। एक्टिवा पर ले जाते समय का पूरा घटनाक्रम इलाके में लगे सीसीटीवी में कैद हो गया। मृतक युवक का नाम सौरभ है और वह गुरु नानकपुरा इलाके का रहने वाला था। वह 27 मई से गायब था। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि दो युवक एक अन्य युवक को अपने बीच बैठाकर दोपहिया वाहन पर ले जा रहे हैं। परिजनों के अनुसार सौरभ घर से निकलने के बाद वापस नहीं लौटा। काफी तलाश के बावजूद उसका कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस में भी शिकायत दर्ज करवाई थी। बाद में उसका शव बरामद हुआ। मृतक की मां परमजीत ने आरोप लगाया कि उनके बेटे की गला घोंटकर हत्या की गई। उनका कहना है कि वायरल वीडियो में दिखाई दे रहे कपड़े वही हैं, जिन्हें पहनकर सौरभ घर से निकला था।

कोर्ट कॉम्प्लेक्स को बम से उड़ाने की धमकी से मचा हड़कंप, पुलिस-प्रशासन जांच में जुटा

जालंधर (पंजाब), एजेंसी। पंजाब में स्कूलों और सरकारी इमारतों को लगातार मिल रही बम धमकियों के बीच अब जालंधर के जिला प्रशासनिक एवं न्यायिक परिसर (कोर्ट कॉम्प्लेक्स) को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। इसके बाद हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस, डॉग स्क्वाड और एंटी-सबोटाज टीमों ने मौके पर पहुंचकर पूरे परिसर की जांच शुरू कर दी। सुरक्षा एजेंसियां हर पहलू को ध्यान में रखते हुए तलाशी अभियान चला रही हैं। धमकी के बाद कोर्ट परिसर और आसपास के इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। फिलहाल पुलिस धमकी के स्रोत का पता लगाने और मामले की गहन जांच में जुटी हुई है। प्रशासन ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना पुलिस को देने की अपील की है।

पहलवान सागर का एशियन गेम्स में चयन, 74 किलोग्राम भार वर्ग में खेलेंगे, परिजनों में खुशी

पानीपत, एजेंसी। पानीपत के नौल्था से पहलवान सागर जगलान ने 74 किलोग्राम भार वर्ग में एशियन गेम्स में क्वालीफाई किया है। उनकी इस उपलब्धि पर परिजनों में खुशी है। सागर के पिता भी कुश्ती से जुड़े रहे हैं। बचपन में शारीरिक रूप से कमजोर रहने के बावजूद उन्होंने कड़ी मेहनत से खुद को सीनियर स्तर तक पहुंचाया। पहलवान खेलो इंडिया और हरियाणा की कुश्ती अकादमियों से निकला है। बता दें कि पानीपत के नौल्था से पहलवानों के लिए जाना जाता है।

सेल टैक्स विभाग का चपड़ासी और चालक गिरफ्तार, मांग रहे थे रिश्वत

• फतेहाबाद, एजेंसी।

एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने मंगलवार दोपहर को सेल टैक्स विभाग के चपड़ासी और चालक को 50 हजार रुपये रिश्वत लेते हुए पकड़ा है। बैटरियों के स्क्रैप कारोबारी से आरोपी 50 हजार रुपये ले रहे थे। दोनों को रंगे हाथों पकड़ने के बाद टीम एसीबी कार्यालय में लेकर पहुंचे और प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले में अब सेल टैक्स विभाग के अधिकारी संदेह के घेरे में है। मामले में विभाग के चालक धोलूराम और चपड़ासी सुशील की गिरफ्तारी हुई है। एसीबी के अधिकारियों के मुताबिक आरोपी धोलूराम ईटीओ का चालक है। एसीबी के इंस्पेक्टर मनमोहन सिंह ने बताया कि जींद जिले के धमतान साहिब निवासी स्क्रैप कारोबारी बिशनदत्त ने एसीबी टीम को शिकायत दी थी कि उससे सेल्ज टैक्स विभाग के अधिकारी रिश्वत मांग रहे हैं। शिकायत मिलने के बाद एसीबी की टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया। बिशनदत्त ने विभाग में कार्यरत ड्राइवर धोलूराम और चपरासी सुशील कुमार को हिसार रोड स्थित पेट्रोल पंप के पास बुला लिया। यहां जैसे ही 50 हजार रुपये थमाए तो टीम ने उन्हें काबू कर लिया गया।

एसीबी के अधिकारियों के अनुसार शिकायकर्ता बिशनदास ने शिकायत दी थी कि वह पुरानी बैटरियां खरीदने का भी काम करता है। वह फतेहाबाद से पुरानी बैटरियां एकत्रित करके जींद में बेचता है। स्क्रैप की बैटरियों के बिल नहीं होते हैं लेकिन सेल टैक्स के अधिकारी बिल के नाम पर तंग करते हैं और चालान करने का डराकर रिश्वत की मांग करते हैं। अब भी उससे 50 हजार रुपये की डिमांड की गई। ।

50 एमबीबीएस सीटों को केंद्र की मंजूरी, इसी साल शुरू होगी पढ़ाई

• चण्डीगढ़, एजेंसी।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 50 एमबीबीएस सीटों को मंजूरी दे दी है, जिससे इसी वर्ष संस्थान में शैक्षणिक सत्र शुरू किया जा सकेगा। इसी साल जुलाई माह तक एम्स में बाह्य रोगी विभाग (ओपीडी) सेवाएं शुरू होने की संभावना है। स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने कहा कि रेवाड़ी में बन रहा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं और मेडिकल शिक्षा के लिए बड़ी उपलब्धि साबित होगा।

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि रेवाड़ी एम्स शुरू होने से दक्षिण हरियाणा और आसपास के क्षेत्रों के लोगों को उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी, जबकि युवाओं को मेडिकल शिक्षा के नए अवसर प्राप्त होंगे। स्वास्थ्य सेवाओं के साथ-साथ ग्रीन एनर्जी को भी बढ़ावा देने की दिशा में सभी सिविल अस्पतालों में सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की योजना पर काम किया जा रहा है। इससे अस्पताल अपनी बिजली स्वयं पैदा कर सकेंगे, बिजली खर्च कम होगा और पर्यावरण संरक्षण को भी बल मिलेगा। मंत्री

ने कहा कि जींद मेडिकल कॉलेज लगभग तैयार हो चुका है और इसका हैंडओवर इसी वर्ष मिलने की संभावना है।

करनाल जिले के कुटेल में बन रहा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल भी अंतिम चरण में है। यमुनानगर, कैथल और सिरसा में भी मेडिकल कॉलेजों का निर्माण कार्य तेजी से जारी है। जींद और कुटेल मेडिकल कॉलेजों का हैंडओवर होने के बाद राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की मंजूरियां लेकर प्रवेश प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

मक्खू में दुकानदार की हत्याः दो बदमाशों ने दुकान पर बैठे युवक पर दागी गोलियां

• मक्खू, एजेंसी।

ब्लाक मक्खू में सोमवार दोपहर बारह बजे दो बदमाशों ने एक दुकानदार की गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि कुछ माह पूर्व उसे वाट्सएप पर किसी अज्ञात व्यक्ति ने धमकी दी थी। सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी वारदात स्थल पर पहुंच गए और अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। उधर, नाराज दुकानदार मक्खू थाना के समक्ष धरने पर बैठ गए। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि गुरचरण सिंह काला गाबा अपनी दुकान पर बैठा था। उसकी दुकान पर दो व्यक्ति आए और पिस्तौल से गोलियां दागनी शुरू कर दी। गाबा के सीने में गोली लगी और वह जख्मी हो गया। उसे अस्पताल में दाखिल कराया गया। डाक्टरों ने उसकी चिंताजनक हालत देख मोगा रेफर कर दिया, लेकिन रास्ते में उसकी मौत हो गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे जीरा के पूर्व कांग्रेसी विधायक कुलबीर सिंह जीरा ने कहा कि इस वारदात के बाद दुकानदारों व व्यापारियों में दहशत का माहौल है। उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार ने फैसला लिया है किजब तक आरोपियों को काबू नहीं कर लिया जाता, तब तक वे न तो पोस्टमार्टम करवाएंगे और न ही अंतिम संस्कार करेंगे।

दो दिन में जिले में लगभग गोलियां चलने की पांच वारदात हो गई हैं। जीरा ने कहा कि पुलिस खुद की सुरक्षा नहीं कर पा रही है। दो दिन पूर्व हरिके हैड चौकी पर ड्यूटी पर तैनात होमगार्ड पर जानलेवा हमला कर बदमाश उसकी राइफल व दस राउंड मैगजीन छीनकर भाग गए। पुलिस अभी तक आरोपी नहीं पकड़ सकी है। दूसरी तरफ, गाबा के एक दोस्त ने बताया कि गाबा को वाट्सएप पर किसी व्यक्ति की कुछ माह पहले धमकी आई थी। गाबा ने अपना वाट्सएप ग्रुप बंद कर लिया था। आज आरोपी उसे दुकान पर आकर मार गए हैं।

लुधियाना में सीवर से निकली जहरीली गैसः सफाई करने आए पिता-पुत्र समेत तीन की मौत, लापरवाही का आरोप

• लुधियाना, एजेंसी।

लुधियाना के आरके रोड स्थित एक फैक्टरी में सोमवार को पाना-चाबी (टूल) निर्माता फैक्टरी में सीवरेज से जहरीली गैस का रिसाव हो गया। इसमें सीवर की सफाई करने आए पिता-पुत्र समेत तीन लोगों की जान चली गई। गैस रिसाव के बाद फैक्टरी परिसर में भगदड़ मच गई। गैस की चपेट में आने से कई अन्य मजदूर बेहोश हो गए। दो की हालत गंभीर बताई जा रही है। सूचना मिलने के बाद थाना मोती नगर की पुलिस सहित विभिन्न टीमें वहां पहुंच गई और राहत कार्य शुरु करवाया।

संभलने का मौका तक नहीं मिला

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, फैक्टरी में रोजाना की तरह उत्पादन का काम सामान्य रूप से चल रहा था। सीवरेज की गाद निकालने के लिए लोगों को बाहर से बुलाया गया था। बताया जा रहा है कि सीवर का ढक्कन खोलते ही गैस निकली और मौके पर ही पिता-पुत्र समेत तीन लोगों की मौत हो गई। जहरीली गैस पूरे परिसर में फैल गई। गैस का असर इतना तीखा और घातक था कि काम कर रहे मजदूरों को संभलने या बाहर भागने का मौका तक नहीं मिला। आंखों में असहनीय जलन और सांस लेने में तकलीफ के कारण कई कर्मचारी मौके पर ही निढाल होकर गिर पड़े।

इस दर्दनाक हादसे में जान गंवाने वाले मृतकों की शिनाख्त माना और उनके बेटे अमित के रूप में हुई है। जबकि तीसरे मृतक की पहचान करने में पुलिस जुटी है। अमित अपने पीछे एक साल की मासूम बेटी, पत्नी, दो बहनें और एक छोटे भाई को रोता-बिलखता छोड़ गया है। घर के दो मुख्य कमाने वाले सदस्यों की मौत से पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है।

गांव में जुटा प्रशासन, कारणों की तलाश

हादसे की खबर मिलते ही स्थानीय प्रशासन, पुलिस और संबंधित विभागों की टीमें एम्बुलेंस के साथ मौके पर पहुंचीं। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। थाना मोती नगर के एसएचओ इंस्पेक्टर भूपिंदर सिंह ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। जल्द ही पूरी जानकारी दी जाएगी।

अज्ञात चोरों ने सूने मकान को बनाया निशाना, 40 तोला सोना किया चोरी, नकदी पर किया हाथ साफ

• अंबाला, एजेंसी।

गांव शहजादपुर माजरा में अज्ञात चोरों ने एक सूने मकान को निशाना बनाकर करीब 40 लाख रुपये के सोने-चांदी के जेवरात और भारी नकदी पर हाथ साफ कर दिया। घटना उस समय हुई जब मकान मालिक अपने परिवार सहित धार्मिक स्थल ब्यास गए हुए थे। चोरों ने मकान का ताला और सुरक्षा जाल उखाड़कर इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया है।

गांव शहजादपुर माजरा के निवासी डॉ. विवेक बराड़ ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह अपने परिवार के साथ 30 मई की रात को ताला बंद कर धार्मिक स्थल ब्यास गए हुए थे। इसी दौरान अज्ञात चोरों ने उनके सूने मकान का ताला तोड़कर और लोहे का जाल उखाड़कर घर के अंदर प्रवेश किया। चोरों ने अलमारी में रखे शादी व अन्य आयोजनों के लिए संजोकर रखे गए सोने के आभूषण, जिनका वजन लगभग 40 तोला था, और करीब 5 किलोग्राम चांदी के जेवरात चोरी कर लिए। इसके साथ ही चोरों ने लॉकर में रखी 11 लाख रुपये की भारी नकदी भी समेट ली। घटना का खुलासा तब हुआ जब डॉ. विवेक बराड़ अगले दिन यानी 31 मई 2026 की रात लगभग 9:45 बजे वापस अपने घर लौटे। घर का मुख्य दरवाजा खोलने पर अंदर का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए। घर के अंदर का सारा कीमती सामान बिखरा पड़ा था और लोहे का सुरक्षा जाल उखड़ा हुआ था। अलमारी और तिजोरी के ताले टूटे थे, जिसमें से सोना, चांदी और नकदी गायब थी। पीड़ित ने तुरंत इस मामले की सूचना आस-पास के लोगों और स्थानीय पुलिस को दी।

सूचना मिलते ही शहजादपुर थाना पुलिस की टीम मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। पुलिस ने आस-पास के लोगों से पूछताछ की लेकिन शुरुआती जांच में चोरों का कोई सुराग नहीं लग पाया। शहजादपुर थाना प्रभारी ओमचंद ने बताया कि अज्ञात चोरों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। मामले की जांच का जिम्मा सहायक उप-निरीक्षक संदीप कुमार को सौंपा गया है। पुलिस का कहना है कि इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर चोरी का माल बरामद कर लिया जाएगा। इस बड़ी चोरी के बाद से ग्रामीण इलाकों में सुरक्षा को लेकर चिंता का माहौल है।

सोशल मीडिया पर लड़की से की दोस्ती, तकरार होने पर मार दी गोली; आरोपी गिरफ्तार

• सोनीपत, एजेंसी।

एक साल पहले फेसबुक पर शुरू हुई दोस्ती नाबालिग लड़की की जिंदगी पर भारी पड़ गई। आरोपी नवनीत ने झगड़े के बाद लड़की को गाड़ी में गर्दन और पेट में दो गोली मार दी। लड़की को मरा हुआ समझकर आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बीती 10 मई को गांव कमासपुर के पास यह वारदात हुई। आरोपी नवनीत किराए की गाड़ी लेकर नाबालिग लड़की को हाइवे पर ले गया। वहां दोनों के बीच किसी बात को लेकर तकरार हो गई। गुस्से में नवनीत ने लड़की को गर्दन और पेट में गोली मार दी। वारदात के बाद नवनीत लड़की को मरा हुआ मानकर वहां से भाग निकला। सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची और घायल लड़की को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। पुलिस ने आरोपी नवनीत को सोनीपत सेक्टर-7 से गिरफ्तार किया। आरोपी ने पूछताछ में खुलासा किया कि एक साल पहले फेसबुक पर लड़की से उसकी दोस्ती हुई थी। आरोपी हरियाणवी एल्बम में काम करती थी। पुलिस ने आरोपी पर पांच हजार रुपये का इनाम घोषित किया था। पुलिस अब आरोपी को कोर्ट में पेश कर रिमांड हासिल करने वाली है।

मौसम का यू-टर्न

तपती गर्मी पर लगा ब्रेक, 7 जून तक सुहाना रहेगा हरियाणा

• हिसार, एजेंसी।

जून महीने की शुरुआत कूल मौसम के साथ हुई। पिछले तीन दिन में हुई बारिश के चलते सोमवार को प्रदेशभर में तापमान सामान्य से कम बना रहा। मौसम विभाग के अनुसार जून के पहले पखवाड़े में एक के बाद एक चार पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से लोगों को गर्मी से राहत रहेगी। जून के दूसरे पखवाड़े में गर्मी सहनी पड़ेगी। महीने के दूसरे सप्ताह में प्री मानसून की बारिश होने की संभावना है।

तीन जुलाई को मानसून सक्रिय होने की उम्मीद है। 2 जून को रात्रि उसके बाद 4 जून को एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से हरियाणा-एनसीआर दिल्ली में 3-7 जून तक लगातार मौसम में बदलाव रहेगा। मौसम विशेषज्ञ डॉ. चंद्रमोहन ने बताया कि जून महीने में भी मौसम में उलटफेर देखने को मिलेगा। मौसम वैज्ञानिक के अनुसार जून महीने में भी 7-8 पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होंगे ,साथ ही साथ बंगाल की खाड़ी और अरब सागर पर भी 2 -4 लो प्रेशर एरिया व डिप डिप्रेशन बनने की संभावना बन रही है जिसकी वजह से हरियाणा ,एनसीआर, दिल्ली में बार बार मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। दूसरे पखवाड़े के पहले सप्ताह लगातार दक्षिणी पश्चिमी हवाओं के चलने से उमसभरी गर्मी पड़ेगी। 19 जून को एक और नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से और अरब सागर पर बने लो प्रेशर एरिया का असर राजस्थान तक पहुंचने से हरियाणा एनसीआर दिल्ली में मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा।

सिरसा में दिन का सबसे अधिक तापमान 40 डिग्री रहा। महेंद्रगढ़ में तापमान सामान्य से 6.8 डिग्री सेल्सियस कम 35.5 डिग्री दर्ज किया गया। करनाल में भी सामान्य से 6.8 डिग्री म 32.8 डिग्री तापमान रिकॉर्ड हुआ।

हिसार में दिन का तापमान 38.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है जो कि सामान्य से 3.7 डिग्री सेल्सियस कम बना हुआ है।हिसार में रात्रि तापमान सामान्य से 4.1 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया। मई महीने में मौसम का मिजाज तीन बार बदला। मई महीने के पहले 14 दिन बारिश, आंधी के कारण तापमान सामान्य या इससे कम बना रहा। 15 मई से तापमान में बढ़ोतरी होने लगी। 15 से 25 मई तक भीषण गर्मी ने लोगों को झुलसाया। मई महीने के आखिरी चार दिन में बारिश व धूल भरी आंधी के बाद फिर से मौसम ठंडा हो गया। इस साल मार्च, अप्रैल, मई तीनों महीनों में बारिश दर्ज की गई है।

भारत को दिल्ली में होस्ट करेगा अफगानिस्तान BCCI की दरियादिली से संभव हुआ यह T20 मुकाबला

• नई दिल्ली, एजेंसी

अफगानिस्तान इस साल के अंत में दिल्ली में भारत की मेजबानी करने के लिए तैयार है, क्योंकि खबरों के मुताबिक अफगानिस्तान टी20 मैचों की श्रृंखला के लिए भारत को अपने घरेलू मैदान पर मेहमान के तौर पर खेलने जा रहा है। अगर ऐसा होता है, तो अफगानिस्तान पहली बार किसी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला में भारत की मेजबानी करेगा। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार, अफगानिस्तान द्वारा अरुण जेटली स्टेडियम में भारत की मेजबानी करने के लिए तीन मैचों की टी20 श्रृंखला की योजना बनाई जा रही है।

अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड (एसीबी) ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) से इस महीने भारत द्वारा अफगानिस्तान के खिलाफ एक टेस्ट और तीन मैचों की वनडे श्रृंखला की मेजबानी के बाद वापसी दौरे के लिए संपर्क किया है। रिपोर्ट के अनुसार, आधिकारिक घोषणा की उम्मीद है; हालांकि, तीनों टी20 मैचों की तारीखें 13, 16 और 19 सितंबर तय की गई हैं। बीसीसीआई के एक सूत्र ने अंग्रेजी दैनिक को बताया कि बीसीसीआई और एसीबी के बीच अच्छे संबंध हैं। बीसीसीआई आयरलैंड, श्रीलंका और जिम्बाब्वे जैसे अन्य बोर्डों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए वहां भारतीय टीमें भेजकर उनकी मदद करता रहा है। इस संबंध में बीसीसीआई और एसीबी के बीच एक समझौता हो गया है। कुछ औपचारिकताओं के पूरा होने के बाद आधिकारिक घोषणा की जाएगी।

सूत्र ने आगे कहा कि बीसीसीआई ने एसीबी और दिल्ली जिला क्रिकेट संघ (डीडीसीए) के बीच इस बात पर समझौता कराया कि अफगानिस्तान को श्रृंखला के लिए घरेलू मैदान के रूप में उपलब्ध कराया जाए। डीडीसीए अपनी दिल्ली प्रीमियर लीग टी20 की तारीख भी इसी के अनुसार तय कर रहा है। भारत के क्रिकेट बाज़ार से भारी राजस्व प्राप्त होने के कारण, अफ़गानिस्तान द्वारा भारत की मेज़बानी करना एसीबी के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी। कई बोर्डों ने भारत के खिलाफ़ श्रृंखला आयोजित करने का प्रयास किया है। वहीं, अफ़गानिस्तान भारत में कई टीमों की मेज़बानी कर चुका है।

उन्होंने 2017 में ग्रेटर नोएडा में आयरलैंड के खिलाफ़ तीन टी20 और पांच वनडे मैचों की श्रृंखला की मेज़बानी की थी। उन्होंने 2028 में देहरादून में बांग्लादेश के खिलाफ़ टी20 श्रृंखला की मेज़बानी भी की थी। हाल ही में, उन्होंने 2024 में ग्रेटर नोएडा में न्यूज़ीलैंड के खिलाफ़ एक टेस्ट मैच का आयोजन किया था, जो बारिश और मैदान की खराब स्थिति के कारण बिना एक भी गेंद फेंके रद्द हो गया था। अफ़गानिस्तान द्वारा भारत की मेज़बानी करना एसीबी को बीसीसीआई के निरंतर समर्थन को दर्शाता है, जो ऐसे समय में मेज़बानी उपलब्ध करा रहा है जब अफ़गानिस्तान बोर्ड अपने घरेलू मैदान पर कोई मैच आयोजित नहीं कर रहा है।

इंडोनेशिया ओपन में पीवी सिंधु का शंखनाद, किदंबी श्रीकांत पहले दौर में ही बाहर

• मलेशिया, एजेंसी

दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने कुछ विषम पलों से गुजरने के बावजूद मंगलवार को यहां सीधे गेम में जीत हासिल करके इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के दूसरे दौर में प्रवेश किया, लेकिन किदांबी श्रीकांत पहले दौर की बाधा पार करने में नाकाम रहे। सिंधु ने इस सुपर 1000 बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला एकल के मैच में थाईलैंड की बुसानन ओंगबामरुंगफान को 51 मिनट में 25-23, 21-16 से पराजित किया।

पूर्व विश्व चैंपियन सिंधु ने शुरू से ही आक्रामक खेल दिखाया। उन्हें पहले गेम में कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा लेकिन उन्होंने शुरू से लेकर आखिर तक अपनी लय बरकरार रखी और सीधे गेम में जीत दर्ज की। गैर-वरीयता प्राप्त भारतीय खिलाड़ी सिंधु का सामना दूसरे दौर में मौजूदा ओलंपिक चैंपियन और विश्व की नंबर एक खिलाड़ी आन से-यंग से हो सकता है जिन्होंने उन्हें पिछले सप्ताह सिंगापुर ओपन के क्वार्टर फाइनल में हराया था। आन के खिलाफ भारतीय खिलाड़ी का रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच अभी तक जो नौ मैच खेले गए हैं उन सभी में सिंधु को हार का सामना करना पड़ा।

श्रीकांत पुरुष एकल के पहले दौर में जापान के युशी तनाका से 19-21, 15-21 से हारने के बाद टूर्नामेंट से बाहर हो गए। महिला वर्ग में मालविका बंसोड भी पहले दौर में ही टूर्नामेंट से बाहर हो गईं। उन्हें थाईलैंड की सातवीं वरीयता प्राप्त पोर्नपावी चोचुवोंग ने आसानी से 21-12, 21-10 से हराया। पुरुष युगल में हरिहरन आमसकारुनन और एमआर अर्जुन ने शानदार खेल का नमूना पेश किया तथा अपने से अधिक रैंकिंग वाली मलेशियाई जोड़ी नूर मोहम्मद अजरीन अयूब और टैन वी किओंग पर 21-18, 21-10 की जीत के साथ दूसरे दौर में प्रवेश किया।

अंपायर से भिड़ना टिम डेविड को पड़ा महंगा, मैच फी कटी और अगले IPL सीजन पर लगा बैन

• बेंगलुरू, एजेंसी

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के बल्लेबाज टिम डेविड पर इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के फाइनल में गुजरात टाइटंस के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन के कारण अगले सत्र में एक मैच का प्रतिबंध लगाया गया है। इसके अलावा उन पर मैच फीस का 50 प्रतिशत जुर्माना भी लगाया गया है। आईपीएल की ओर से सोमवार को जारी बयान के अनुसार, ऑस्ट्रेलिया के 30 वर्षीय खिलाड़ी को इस उल्लंघन के लिए दो डिमेरिट अंक दिए गए हैं। इसके साथ ही उनके कुल डिमेरिट अंक बढ़कर पांच हो गए हैं, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें एक मैच के लिए निलंबित किया गया है।

यह इस सत्र में तीसरी बार है, जब डेविड आईपीएल आचार संहिता के उल्लंघन के दोषी पाए गए हैं। रविवार को समाप्त हुए टूर्नामेंट में आरसीबी ने फाइनल में गुजरात टाइटंस को पांच विकेट से हराकर लगातार दूसरी बार खिताब अपने नाम किया था। आईपीएल की ओर से जारी बयान में कहा गया, ''रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बल्लेबाज टिम डेविड पर खिलाड़ियों और टीम अधिकारियों के लिए निर्धारित आईपीएल आचार संहिता के 'लेवल-एक' उल्लंघन के लिए मैच फीस का 50 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया है। साथ ही उन्हें दो डिमेरिट अंक भी दिए गए हैं।''

बयान में कहा गया, ''डेविड को आचार संहिता के अनुच्छेद 2.9 के उल्लंघन का दोषी पाया गया, जो मैच के दौरान किसी खिलाड़ी, टीम अधिकारी, अंपायर, मैच रेफरी या अन्य व्यक्ति की ओर अनुचित अथवा खतरनाक तरीके से गेंद या क्रिकेट उपकरण (जैसे पानी की बोतल आदि) फेंकने से संबंधित है।''

डेविड ने उल्लघंन स्वीकार कर लिया और मैच रेफरी जवागल श्रीनाथ द्वारा निर्धारित सजा को भी मान लिया। डेविड को मैदान पर मौजूद अंपायर नितिन मेनन की दिशा में आक्रामक तरीके से आइस बैग फेंकने का दोषी पाया गया था। यह घटना पहली पारी के 10वें ओवर में विकेट गिरने के बाद हुई थी। इससे पहले 11 मई को मुंबई इंडियंस के खिलाफ मैच के बाद डेविड को अनुच्छेद 2.6 के उल्लंघन का दोषी पाया गया था। यह अनुच्छेद अशोभनीय, अपमानजनक अथवा आपत्तिजनक इशारों के इस्तेमाल से संबंधित है।

उस मामले में उन पर मैच फीस का 30 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया था और दो डिमेरिट अंक दिए गए थे। वहीं, 13 अप्रैल को मुंबई इंडियंस के खिलाफ एक अन्य मैच में अंपायर के निर्देशों की अवहेलना करने के कारण उन्हें अनुच्छेद 2.4 के तहत दोषी पाया गया था। उस समय उन पर मैच फीस का 25 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया था और एक डिमेरिट अंक दिया गया था।

डे टेस्ट में 'पिंक बॉल' ट्रायल को मंज़ूरी, व्हाइट-बॉल क्रिकेट में लागू होगा IPL जैसा 'कोच रूल'

• कुआलालंपुर, एजेंसी

इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने टेस्ट क्रिकेट को अधिक रोमांचक बनाने और व्हाइट-बॉल प्रारूपों को आधुनिक रूप देने के लिए कई ऐतिहासिक फैसलों को मंजूरी दी है। रविवार को अहमदाबाद में आयोजित आईसीसी बोर्ड की बैठक में कई महत्वपूर्ण सिफारिशें स्वीकार की गईं। विशेष बात यह है कि यह बैठक उसी दिन हुई, जिस दिन आईपीएल 2026 (IPL 2026) का फाइनल मुकाबला खेला गया था। इन फैसलों में डे टेस्ट मैचों में 'पिंक बॉल' का ट्रायल और वनडे व टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में आईपीएल की तर्ज पर कोचों को मैदान पर जाने की अनुमति देना शामिल है।

पिंक बॉल का इस्तेमाल खास तौर पर डे-नाइट टेस्ट मैचों में किया जाता रहा है, जिनमें से पहला मैच नवंबर 2015 में खेला गया था। पिंक-बॉल टेस्ट इसलिए शुरू किए गए थे ताकि काम के घंटों के बाद ज्यादा दर्शक मैच देखने आ सकें, जिससे टेस्ट क्रिकेट का रोमांच भी बढ़ता है।

इस बीच, पिंक बॉल के इस्तेमाल का ट्रायल टीमों को तब खेलने की अनुमति देने के लिए है, जब लाल गेंद से खेलने के लिए रोशनी सही न हो, ताकि टेस्ट क्रिकेट में बर्बाद होने वाले समय को बचाया जा सके। कई बार ऐसा हुआ है कि शाम को रोशनी कम होने की वजह से एक दिन के पूरे 90 ओवर नहीं फेंके जा सके हैं। यह नियम इंग्लैंड और न्यूज़ीलैंड के बीच होने वाली आगामी टेस्ट सीरीज़ पर लागू नहीं होगा, जो 4 जून से शुरू हो रही है।

ICC ने IPL जैसा नियम लागू कियाः हेड कोच को ड्रिंक्स ब्रेक के दौरान मैदान पर जाने की अनुमति

इस बीच, ICC ने IPL जैसा, या मोटे तौर पर कहें तो T20 जैसा एक नियम लागू करने का भी फ़ैसला किया है। इस नियम के तहत, हेड कोच या तय किए गए स्टाफ़ को ड्रिंक्स ब्रेक के दौरान मैदान पर जाने और खिलाड़ियों से बातचीत करने की अनुमति होगी। यह नियम ODI और T20I मैचों में लागू होगा।

यह नियम T20 क्रिकेट में, खासकर IPL में काफ़ी इस्तेमाल होता रहा है, जहाँ कोच ड्रिंक्स ब्रेक के दौरान डगआउट से बाहर आकर खिलाड़ियों को निर्देश देते हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट में पहले यह नियम नहीं था, लेकिन अब यह व्हाइट-बॉल फ़ॉर्मेट का हिस्सा बन जाएगा।

इसके अलावा, ICC ने लेग-साइड वाइड के नियम को स्थायी बना दिया है। पिछले साल, इंटरनेशनल संस्था ने लेग-साइड वाइड के नियम में थोड़ा बदलाव किया था, जिसमें कहा गया था कि बल्लेबाज़ के पैरों के पीछे से और 'प्रोटेक्टिंग एरिया' के बीच से गुज़रने वाली गेंदों को वाइड नहीं माना जाएगा। 'इस ट्रायल में, अगर कोई गेंद लेग स्टंप और प्रोटेक्टेड एरिया मार्कर के बीच से पॉपिंग क्रीज़ को पार करती है, तो उसे 'वाइड' नहीं माना जाएगा। इसमें मदद के लिए, प्रोटेक्टेड एरिया मार्कर लाइन को पॉपिंग क्रीज़ तक बढ़ाया जाएगा और यह अंपायरों के लिए एक गाइड का काम करेगी,' ट्रायल के नियम में यह बात कही गई थी, जिसे अब परमानेंट कर दिया गया है।

महिला चैंपियंस ट्रॉफी का समय बदला

एक और अहम कदम उठाते हुए, ICC ने महिला चैंपियंस ट्रॉफी का समय जून-जुलाई 2027 से बदलकर फरवरी 2027 कर दिया है। संस्था ने इस बदलाव का कोई कारण नहीं बताया है। यह टूर्नामेंट 2022 में पहली बार घोषित होने के बाद, पहली महिला चैंपियंस ट्रॉफी होगी। इस टूर्नामेंट में आठ टीमें हिस्सा लेंगी, जो श्रीलंका में खेला जाएगा; यह 14 फरवरी से शुरू होकर दो हफ़्ते तक चलेगा और 28 फरवरी को खत्म होगा।

चार दिन की गिरावट के बाद शेयर बाजार में तेजी, सेंसेक्स 382 अंक उछला

• मुंबई, एजेंसी

घरेलू शेयर बाजार में लगातार चार सत्र से चली आ रही गिरावट का सिलसिला आज थम गया।पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ने के कारण आज शुरुआती कारोबार में बीएसई सेंसेक्स में 400 अंक से ज्यादा आई जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी50 इंडेक्स भी 23,250 अंक से नीचे चला गया था। लेकिन दोपहर बाद शेयर बाजार में तेजी लौटी। अंत में सेंसेक्स 382.50 अंक यानी 0.52% की तेजी के साथ 74,649.84 अंक पर बंद हुआ। निफ्टी 100.95 अंक यानी 0.43% की तेजी के साथ 23,483.55 अंक पर पहुंच गया। भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले 0.3% गिरावट के साथ 95.27 पर बंद हुआ।

सेंसेक्स के 30 में से 20 शेयर तेजी के साथ बंद हुए। आईटी शेयरों में सबसे ज्यादा तेजी रही। टीसीएस का शेयर 6.53 फीसदी उछलकर बंद हुआ। इन्फोसिस, एचसीएल टेक, अडानी पोर्ट्स, टेक महिंद्रा, टाइटन, आईटीसी, एशियन पेंट्स और ट्रेंट में उल्लेखनीय तेजी रही। दूसरी ओर एनटीपीसी, एक्सिस बैंक, पावरग्रिड, बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व में गिरावट रही।

निफ्टी पर टीसीएस, इन्फोसिस और एचसीएल टेक्नोलॉजीज में सबसे ज्यादा तेजी रही। ब्रॉडर मार्केट में निफ्टी मिडकैप में 01.8 फीसदी और निफ्टी स्मॉलकैप में 0.40 फीसदी तेजी आई। सेक्टरवाइज देखें तो निफ्टी आईटी में सबसे ज्यादा तेजी रही। निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल, निफ्टी ऑटो और निफ्टी एमएमसीजी में भी तेजी रही। लेकिन निफ्टी फार्मा और निफ्टी हेल्थकेयर में गिरावट रही।

ईरान ने धमकी दी है कि अगर इजरायल और लेबनॉन के बीच शांति कायम नहीं हुई तो वह अमेरिका के साथ चल रही बातचीत बंद कर देगा और होर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह ब्लॉक कर देगा। उसका कहना है कि जब तक इजरायल लेबनॉन से पूरी तरह अपने सैनिकों को नहीं निकाल देता, तब तक कोई बातचीत नहीं होगी। इससे दुनियाभर के शेयर बाजारों में गिरावट आई थी। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी एक इंटरव्यू में कहा कि अगर ईरान के साथ बातचीत खत्म हो गई है तो उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। उन्होंने कहा कि यह बातचीत बोरिंग होने लगी थी। इस बीच कच्चे तेल की कीमत में मामूली गिरावट आई है।

आपकी रसोई का बजट बिगाड़ेगा पेट्रोल डीजल, फल-सब्जियों पर भी महंगाई की मार

• नई दिल्ली, एजेंसी

पेट्रोल एवं डीजल की कीमतों में वृद्धि से अर्थव्यवस्था पर मुद्रास्फीति-जनित दबाव बढ़ने की आशंका है, जिससे आने वाले महीनों में परिवहन एवं विनिर्माण लागत बढ़ सकती है और आम उपभोग की वस्तुएं महंगी हो सकती हैं। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने मंगलवार को जारी रिपोर्ट में यह अनुमान जताया। रिपोर्ट कहती है कि 15 मई के बाद से पेट्रोल एवं डीजल की कीमतों में करीब 7.5 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी हो चुकी है और अगर कच्चे तेल के दाम ऊंचे स्तर पर बने रहते हैं तो यह बढ़ोतरी निकट भविष्य में 10 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच सकती है।

क्रिसिल ने कहा, "इसका असर पूरी अर्थव्यवस्था में ढुलाई लागत में बढ़ोतरी के जरिये दिखेगा, जिससे खाने-पीने की चीजों और अन्य वस्तुओं की महंगाई दोनों बढ़ेंगी।" रिपोर्ट के मुताबिक, ईंधन कीमतों में वृद्धि का सीधा असर महंगाई पर पड़ेगा। ईंधन कीमतों में 7.5 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी से खुदरा मुद्रास्फीति करीब 0.36 प्रतिशत बढ़ सकती है। अगर ईंधन कीमतें 10 रुपये प्रति लीटर तक बढ़ जाती हैं तो खुदरा महंगाई में करीब 0.48 प्रतिशत की वृद्धि हो सकती है। रिपोर्ट में कहा गया कि ईंधन के दाम बढ़ने का सर्वाधिक प्रभाव सड़क परिवहन पर पड़ेगा क्योंकि इसकी लागत का लगभग 42 प्रतिशत हिस्सा ईंधन पर निर्भर है।

इससे माल ढुलाई महंगी हो जाएगी और इसका असर रोजमर्रा की वस्तुओं की कीमतों पर पड़ेगा। देश में करीब 71 प्रतिशत माल ढुलाई सड़क मार्ग के जरिये ही होती है। क्रिसिल के मुताबिक, ढुलाई लागत बढ़ने से दूध, फल, दालें, चाय-कॉफी, मसाले, अंडे, मांस और मछली जैसे खाद्य उत्पादों की कीमतों में तेजी आ सकती है क्योंकि ये बड़े पैमाने पर परिवहन नेटवर्क पर निर्भर हैं। रिपोर्ट कहती है कि कपड़ा, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, लकड़ी उत्पाद, सीमेंट और सिरेमिक जैसे क्षेत्रों में भी लागत बढ़ेगी। रसायन, कोयला और धातु क्षेत्र भी महंगाई की चपेट में आएंगे। ऐसी स्थिति में कंपनियां लागत का बोझ उपभोक्ताओं पर डाल सकती हैं या उत्पाद की मात्रा में कटौती कर सकती हैं।

सितंबर, 2025 में जीएसटी दरों में की गई कटौती से कुछ राहत मिल सकती है लेकिन ऊंची ऊर्जा लागत के असर को यह पूरी तरह संतुलित नहीं कर पाएगी। रिपोर्ट के अनुसार, चालू वित्त वर्ष के पहले दो महीनों में कच्चे तेल की औसत कीमत 112 डॉलर प्रति बैरल रही है, जो पूरे वर्ष के अनुमान 95 डॉलर प्रति बैरल से अधिक है। हालांकि, सकल मुद्रास्फीति अभी भारतीय रिजर्व बैंक के चार प्रतिशत लक्ष्य से नीचे है, लेकिन आगे चलकर इसके बढ़ने का अनुमान है। फिर भी यह रिजर्व बैंक के दो से छह प्रतिशत के दायरे में रह सकती है।

मजबूत अर्थव्यवस्था

भारत-ओमान व्यापार समझौता लागू, निर्यात के लिए मिडिल ईस्ट का दरवाजा खुला

• नई दिल्ली, एजेंसी

भारत और ओमान के बीच मुक्त व्यापार समझौता खाड़ी क्षेत्र की अस्थिरता के बीच भारत की ऊर्जा एवं आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करेगा। विशेषज्ञों ने यहराय जताई है। दोनों देशों के बीच यह व्यापार समझौता एक जून से लागू हो गया है। शोध संस्थान सीआरएफ के अध्यक्ष शिशिर प्रियदर्शी ने कहा, '' पहला, यह अस्थिर क्षेत्र में भारत की ऊर्जा एवं आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करता है। ओमान लंबे समय से खाड़ी में भारत के सबसे भरोसेमंद साझेदारों में से एक रहा है।''

उन्होंने कहा कि भारत तेल, गैस एवं पेट्रोरसायन के आयात पर काफी निर्भर है। ऐसे में ओमान के साथ गहरे आर्थिक एकीकरण से इस महत्वपूर्ण संबंध के लिए अधिक स्थिर और मजबूत ढांचा तैयार होता है। अमेरिका-ईरान युद्ध और इसके बाद होर्मुज जलडमरूमध्य के बाधित होने से कृषि तथा ऊर्जा उत्पादों सहित विभिन्न क्षेत्रों की आपूर्ति श्रृंखलाओं में बाधा आई है। ओमान भारतीय व्यवसायों के लिए पश्चिम एशिया में विनिर्माण, लॉजिस्टिक और पुनःनिर्यात केंद्र के रूप में भी काम कर सकता है।

प्रियदर्शी ने कहा, '' इसलिए इस मुक्त व्यापार समझौते का महत्व केवल द्विपक्षीय व्यापार आंकड़ों से कहीं अधिक है। यह महत्वपूर्ण आर्थिक संबंधों को सुरक्षित करने, भारतीय उद्योग के लिए नए अवसर उत्पन्न करने और यह संकेत देने के बारे में है कि भारत वैश्विक व्यापार एवं संपर्क के अगले चरण को आकार देने में अग्रणी भूमिका निभाना चाहता है।''

अंतरराष्ट्रीय व्यापार विशेषज्ञ एवं हाई-टेक गियर्स के चेयरमैन दीप कपूरिया ने भी इसी तरह के विचार व्यक्त करते हुए कहा कि इस व्यापार समझौते के लागू होने से भारत को न केवल ओमान बल्कि पूरे पश्चिम एशिया क्षेत्र में अपनी बाजार हिस्सेदारी बढ़ाने में मदद मिलेगी।

उन्होंने कहा, '' इस समझौते के लागू होने की तारीख से ओमान को सभी निर्यात पर शून्य-शुल्क बाजार पहुंच, सरल नियामकीय प्रक्रियाएं और कम अनुपालन आवश्यकताओं के साथ भारतीय निर्यातक विभिन्न उत्पाद श्रेणियों में अपनी उपस्थिति बढ़ाने के लिए अच्छी स्थिति में हैं।'' कपूरिया ने कहा कि हालांकि ओमान अपेक्षाकृत छोटा बाजार है लेकिन यह इंजीनियरिंग, दवा, कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, समुद्री उत्पाद, वस्त्र, रसायन, इलेक्ट्रॉनिक, रत्न एवं आभूषण जैसे प्रमुख क्षेत्रों में निर्यात के अवसर प्रदान करता है।

आर्थिक शोध संस्थान 'ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव' (जीटीआरआई) के अनुसार, भारत के लिए ओमान के साथ व्यापार समझौता रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि मस्कट का अधिकतर तट होर्मुज जलडमरूमध्य के बाहर स्थित है। इससे क्षेत्रीय संघर्ष, व्यवधान या भू-राजनीतिक अस्थिरता के दौरान भी ओमान, भारत के लिए एक भरोसेमंद व्यापार और ऊर्जा मार्ग बना रह सकता है। वित्त वर्ष 2025-26 में ओमान को भारत का निर्यात लगभग चार अरब अमेरिकी डॉलर रहा। इसमें पेट्रोल (78.1 करोड़ डॉलर) और नेफ्था (74.6 करोड़ डॉलर) जैसे परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पाद प्रमुख रहे।

इसके बाद कैल्साइंड एल्युमिना (27.7 करोड़ डॉलर), लौह एवं इस्पात उत्पाद (23 करोड़ डॉलर), मशीनरी (17.8 करोड़ डॉलर) और चावल (16.7 करोड़ डॉलर) का स्थान रहा। दूसरी ओर, 2025-26 में भारत ने ओमान से 7.2 अरब अमेरिकी डॉलर का आयात किया।

पेज 1 का शेष

मोदी सरकार का बड़ा...

पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान अपलोड की गई उत्तर पुस्तिकाओं में कई छात्रों द्वारा अनियमितताओं को उजागर करने के बाद ओएसएम प्रणाली पर बढ़ती जांच के बीच यह घटनाक्रम सामने आया है। सूत्रों ने बताया कि मंत्रालय ने निविदा प्रक्रिया से संबंधित प्रारंभिक जानकारी पहले ही एकत्र कर ली है और अनुबंध दिए जाने के विभिन्न पहलुओं की जांच कर रहा है।

चुनाव में धांधली का...

पूरा माहौल ही बदल गया है। कोलकाता और बंगाल को गुंडों के हवाले कर दिया गया है। टीएमसी टिकट पर विधानसभा सीटें जीतने वाले अधिकांश नए चेहरे अनुपस्थित थे, वहीं बनर्जी के साथ पार्टी के पुराने नेता फिरहाद हकीम, मदन मित्रा, डेरेक ओ'ब्रायन, कल्याण बनर्जी और डोला सेन नजर आए।

हालांकि, पार्टी प्रमुख ने जोर देकर कहा कि उनके भतीजे और टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी पर शनिवार को हुए हमले, चुनाव के बाद कथित हिंसा और फेरीवालों को बेदखल करने के विरोध में धरना निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार शाम तक जारी रहेगा।

एयरपोर्ट पर रील बनाना...

और एयरपोर्ट के कामकाज को रिकॉर्ड होने और ऑनलाइन शेयर होने से रोकना है। दिशा-निर्देशों के अनुसार, जो यात्री बार-बार नियमों का उल्लंघन करते हैं या सुरक्षा से जुड़ा संवेदनशील कंटेट रिकॉर्ड करते हैं, उन्हें गंभीर नतीजों का सामना करना पड़ सकता है। गंभीर मामलों में, उल्लंघन की गंभीरता के आधार पर, एयरपोर्ट अधिकारी यह सिफारिश कर सकते हैं कि यात्री का नाम DGCA की नो-फ्लाई लिस्ट में डाल दिया जाए। यात्री पर कुछ समय के लिए या हमेशा के लिए हवाई यात्रा पर रोक लग सकती है।

एयरपोर्ट अधिकारियों का कहना है कि यह फैसला एयरपोर्ट परिसर के अंदर सोशल मीडिया कंटेंट बनाने के मामलों में अचानक आई तेजी को देखते हुए लिया गया है। ट्रैवल रील्स, व्लॉग और बिहाइंड-द-सीन वीडियो काफी लोकप्रिय हो गए हैं। हालांकि, इनमें से कुछ अपलोड्स की वजह से अनजाने में सुरक्षा ढांचा, कर्मचारियों के काम करने का तरीका और निगरानी के इंतजान उजागर हो गए हैं। भले ही कंटेट देखने में बेनुकसान लगे, लेकिन अधिकारियों का मानना है कि अगर संवेदनशील जानकारी आम लोगों तक पहुंच जाती है, तो इससे सुरक्षा को खतरा पैदा हो सकता है।

सुरक्षा कर्मियों को यह अधिकार दिया गया है कि वे नियमों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के ख़िलाफ़ तुरंत कार्रवाई करें। हालात के हिसाब से, कार्रवाई में ये चीजें शामिल हो सकती हैं। सुरक्षा कर्मी यात्रियों से तुरंत कंटेंट डिलीट करने के लिए कह सकते हैं। इसके अलावा जुर्माना लगाना, जांच के लिए मोबाइल फ़ोन, कैमरे या रिकॉर्डिंग डिवाइस जब्त करना, गंभीर मामलों में आगे की कार्रवाई की सिफारिश करना भी शामिल है। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि बार-बार नियम तोड़ने वालों को ज्यादा सख्त नतीजों का सामना करना पड़ सकता है। अधिकारियों का कहना है कि एयरपोर्ट के कुछ सार्वजनिक इलाकों में फोटोग्राफी की अब भी इजाजत है। लेकिन, यात्रियों से यह उम्मीद की जाती है कि वे हर समय एयरपोर्ट स्टाफ, एयरलाइन कर्मचारियों और सुरक्षा एजेंसियों के दिए गए निर्देशों का पालन करें।

इबोला पर स्वास्थ्य मंत्रालय ...

मंत्रालय ने जनता से अपील की है कि इबोला से संबंधित किसी भी जानकारी या सहायता के लिए 24x7 हेल्थ हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें।

मंत्रालय ने बताया कि देश में अभी तक इबोला के एक भी केस नहीं हैं, लेकिन स्वास्थ्य कर्मियों को लक्षणों पर विशेष नजर रखने और तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि समय पर सतर्कता और आइसोलेशन से संक्रमण को रोका जा सकता है।

'काला हिरण' फिल्म पर सलमान खान के लीगल नोटिस का निर्माता अमित जानी ने दिया जवाब, कहा- 'यह कोई बायोपिक नहीं है'

• मुंबई, एजेंसी

बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान और विवादों में घिरी फिल्म 'काला हिरणः द बैटल फॉर लेगेसी' के निर्माताओं के बीच कानूनी जंग छिड़ गई है। सलमान खान की लीगल टीम द्वारा फिल्म के खिलाफ भेजे गए नोटिस पर अब निर्माता अमित जानी ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। मंगलवार को दिए एक बयान में उन्होंने साफ किया कि यह फिल्म सलमान खान की बायोपिक नहीं है, बल्कि इसका मुख्य फोकस बिश्नोई समुदाय और पर्यावरण के प्रति उनके संघर्ष पर आधारित है।

फिल्म का पहला लुक पोस्टर रिलीज होने के बाद से ही कयास लगाए जा रहे थे कि यह कहानी सलमान खान के चर्चित काले हिरण शिकार मामले से प्रेरित है। सलमान खान की टीम ने इस पर तुरंत आपत्ति जताते हुए फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने और सभी प्रचार सामग्री हटाने की मांग का नोटिस भेजा है।

इंडिया टुडे से खास बातचीत में जानी ने कहा कि यह नोटिस जल्दबाजी में भेजा गया था और उन्होंने साफ किया कि यह फिल्म 'सलमान खान की बायोपिक नहीं है।' इस कानूनी कार्रवाई को 'गैर-जरूरी' बताते हुए प्रोड्यूसर ने कहा कि फिल्म का पोस्टर जारी होने के अलावा, अब तक फिल्म के बारे में और कुछ भी सामने नहीं आया है।

उन्हें इस लीगल नोटिस पर हैरानी हुई, खासकर इसलिए क्योंकि अब तक फिल्म का सिर्फ पहला पोस्टर ही जारी हुआ है। फिल्म का टीजर 20 जून को आने वाला है। जानी ने तर्क दिया कि यह मामला और उससे जुड़ी घटनाएं पब्लिक रिकॉर्ड का हिस्सा हैं और उन्हें स्क्रीन पर दिखाया जा सकता है। उन्होंने कहा, 'यह सलमान खान की बायोपिक नहीं है। यह फिल्म एक बड़ी कहानी पर आधारित है, जिसमें बिश्नोई समुदाय, उनका संघर्ष और वन्यजीवों के साथ उनका गहरा जुड़ाव शामिल है। हमने उसी कहानी को स्क्रीन पर उतारने की कोशिश की है।'

प्रोड्यूसर ने कहा कि फिल्म का फोकस आरोपी के बजाय, इस मामले से जुड़े लोगों के नज़रिए पर है। उन्होंने दावा किया कि असल जिंदगी की घटनाओं पर बनी फिल्में अक्सर पीड़ितों, शिकायतकर्ताओं, गवाहों और प्रभावित समुदायों के अनुभवों के ज़रिए ही दिखाई जाती हैं।

जानी ने यह भी कहा कि उन्हें लगता है कि यह लीगल नोटिस जल्दबाजी में भेजा गया था। उन्होंने कहा, 'अभी सिर्फ पोस्टर जारी हुआ है। टीज़र आना बाकी है। इस स्टेज पर, बिना किसी बातचीत के लीगल नोटिस भेजना गैर-जरूरी था।'

इस चिंता पर कि फिल्म सीधे तौर पर सलमान खान को निशाना बना रही है, जानी ने ऐसे किसी भी इरादे से इनकार किया। उन्होंने कहा कि फिल्म में न तो सलमान खान को महिमामंडित किया गया है और न ही गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को बुरा दिखाया गया है। उन्होंने कहा, 'मैंने सलमान खान को किसी भी तरह से नकारात्मक रूप में नहीं दिखाया है, और न ही मैंने लॉरेंस बिश्नोई को महिमामंडित किया है। यह फिल्म वही दिखाती है जो पहले से ही पब्लिक डोमेन में मौजूद है, और यह बिश्नोई समुदाय की मान्यताओं और इतिहास को उजागर करती है।' जानी ने आगे दावा किया कि यह फ़िल्म बिश्नोई समुदाय के लोगों द्वारा वन्यजीवों और प्रकृति की रक्षा के लिए दिए गए बलिदानों को दिखाती है। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण के प्रति समुदाय की ऐतिहासिक प्रतिबद्धता का ज़िक्र किया और कहा कि यह पहलू कहानी का एक अहम हिस्सा है।

70 के हुए मणि रत्नम, 'दिल से' से 'गुरु' तक बनाई शानदार फिल्में

• मुंबई, एजेंसी

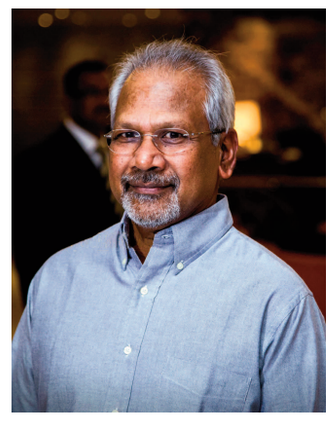

हिंदी सिनेमा और दक्षिण भारतीय सिनेमा के निर्देशक मणिरत्नम आज यानी की 02 जून को अपना 70वां जन्मदिन मना रहे हैं। मणिरत्नम ने कई बेहतरीन और शानदार फिल्मों का निर्देशन करके पूरी दुनिया में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। मणिरत्नम ने हिंदी, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ भाषा की फिल्में बनाई हैं। दर्शक भी उनकी फिल्मों का बड़ी बेसब्री से इंतजार करते हैं। तो आइए जानते हैं उनके जन्मदिन के मौके पर मणिरत्नम के जीवन से जुड़ी कुछ रोचक बातों के बारे में...

तमिलनाडु के मदुरै में 02 जून 1956 को मणिरत्नम का जन्म हुआ था। वह मद्रास में पले बढ़े हैं। उनके पिता वीनस पिक्चर्स में बतौर फिल्म वितरक काम करते थे। फिल्मी बैकग्राउंड से होने के बाद भी मणिरत्नम इस क्षेत्र में नहीं आना चाहते थे। इसलिए उन्होंने मैनेजमेंट का रुख किया और एक कंपनी में कंसल्टेंट के रूप में काम करने लगे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था और मणिरत्नम को फिल्मी दुनिया में आना ही पड़ा।

मणिरत्नम के दोस्त रवि शंकर फिल्म 'अनु पल्लवी अनु' बना रहे थे। इसके लिए उन्होंने मणिरत्नम ने सहायता मांगी और स्क्रीनप्ले लिखने के लिए कहा। मणिरत्नम ने शानदार स्क्रीनप्ले लिखा और यहीं से उनके फिल्मी सफर की शुरूआत हो गई। इस फिल्म में अभिनेता अनिल कपूर नजर आए थे। इस फिल्म को कर्नाटक के स्टेट अवॉर्ड से नवाजा गया था।

मणिरत्नम को असली पॉपुलैरिटी तमिल फिल्म 'माउंगा रंगम' से मिली थी। साल 1987 में उन्होंने फिल्म 'लायकन' बनाई थी। इस फिल्म में अभिनेता कमल हसन थे और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बड़ी हिट हुई थी, जिसके बाद इंडस्ट्री में मणिरत्नम की मांग बढ़ने लगी। मणिरत्नम को लीक से हटकर फिल्में बनाने के लिए जाना जाता है। उन्होंने आतंकवाद, पॉलिटिकल ड्रामा से लेकर क्लासिक लव स्टोरी जैसी फिल्में बनाई हैं।

वहीं मणिरत्नम की हिंदी फिल्मों की बात करें, तो उन्होंने फिल्म 'दिल से' बनाई थी। इसके अलावा उन्होंने 'बॉम्बे' और 'गुरु' जैसी बेहतरीन फिल्में दी हैं। बता दें कि मणिरत्नम ने अब तक 26 फिल्मों का निर्देशन किया है। वहीं उनको पद्मश्री के अलावा 6 बार नेशनल अवॉर्ड से सम्मानित किया जा चुका है।

वेलकम टू द जंगल का नया गाना 'ऊंचा लंबा कद फॉरएवर' रिलीज

• मुंबई, एजेंसी

बॉलीवुड की सबसे पसंदीदा कॉमेडी फ्रेंचाइजी 'वेलकम' एक बार फिर दर्शकों को हंसाने और थिरकने पर मजबूर करने के लिए तैयार है। इस महीने रिलीज होने जा रही फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' को लेकर फैंस का उत्साह चरम पर है। इसी बीच, मेकर्स ने सोमवार को फिल्म का एक नया गाना रिलीज कर दिया है, जिसने रिलीज होते ही इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है। इस गाने का टाइटल है 'ऊंचा लंबा कद फॉरएवर'। जी हां, आपने बिल्कुल सही पढ़ा! यह नया गाना साल 2007 में आई मूल फिल्म 'वेलकम' के सुपरहिट और एवरग्रीन गाने 'ऊंचा लंबा कद' का रीमिक्स वर्शन है, जिसमें अक्षय कुमार और कैटरीना कैफ की केमिस्ट्री ने दर्शकों का दिल जीत लिया था।

'ऊंचा लंबा कद फॉरएवर' अब रिलीज हो गया है

ओरिजिनल गाना आनंद राज आनंद ने कंपोज़ किया था, जबकि रीमिक्स वर्शन का म्यूज़िक विक्रम मोंट्रोज़ ने दिया है। 2007 का गाना आनंद राज आनंद और कल्पना पटवारी ने गाया था। वहीं, इस नए गाने को आनंद राज आनंद और रुबाई ने अपनी आवाज़ दी है। इस नए वर्शन के बोल मेघा बाली ने लिखे हैं।

'वेलकम टू द जंगल' के मेकर्स और कास्ट

इस फ़िल्म में अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, दिशा पटानी, जैकलीन फ़र्नांडिस, अरशद वारसी, जैकी श्रॉफ़, परेश रावल, रवीना टंडन, लारा दत्ता, फ़रीदा जलाल, जॉनी लीवर, श्रेयस तलपड़े, तुषार कपूर, राजपाल यादव, कृष्णा अभिषेक, कीकू शारदा, दलेर मेहंदी, आफ़ताब शिवदासानी, मुकेश तिवारी, यशपाल शर्मा, किरण कुमार, ज़ाकिर हुसैन, विंदू दारा सिंह, उर्वशी रौतेला, हेमंत पांडे, बृजेंद्र काला, फ़िरोज़ ख़ान (अर्जुन), स्वर्गीय पंकज धीर जी, पुनीत इस्सर, सुदेश बेरी, जीतू वर्मा, वृही कोडवारा, आदित्य सिंह और भाग्य भानुशाली एक साथ नज़र आएंगे।

'वेलकम टू द जंगल' को AA नाडियाडवाला, केप ऑफ़ गुड फ़िल्म्स और स्टार स्टूडियो18 ने सीता फ़िल्म्स और राकेश डांग के साथ मिलकर पेश किया है। यह फ़िल्म बेस इंडस्ट्रीज़ ग्रुप का प्रोडक्शन है, जिसे राकेश डांग और वेदांत विकास बाली ने प्रोड्यूस किया है। फ़िरोज़ ए. नाडियाडवाला द्वारा निर्मित, 'वेलकम टू द जंगल' 26 जून, 2026 को सिनेमाघरों में धूम मचाने के लिए तैयार है।

सुष्मिता सेन संग अपने रिश्ते पर बोले ललित मोदी, मैं तो बस एक पाला-पोसा बॉयफ्रेंड था

• मुंबई, एजेंसी

बिजनेसमैन और आईपीएल (IPL) के पूर्व चेयरमैन ललित मोदी और पूर्व मिस यूनिवर्स व बॉलीवुड अभिनेत्री सुष्मिता सेन का रिश्ता एक बार फिर सुर्खियों में है। साल 2022 में सोशल मीडिया पर अपने रिश्ते की अचानक घोषणा कर इंटरनेट पर तहलका मचाने वाले ललित मोदी ने अब इस रिश्ते की अंदरूनी हकीकत बयां की है। 'ह्यूमन्स ऑफ बॉम्बे' (Humans of Bombay) को दिए एक हालिया इंटरव्यू में ललित मोदी ने सुष्मिता सेन पर लगे 'गोल्ड डिगर' (पैसे के पीछे भागने वाली) के टैग को सिरे से खारिज करते हुए खुद को ही 'डायमंड डिगर' बता दिया है।

इंटरव्यू के दौरान ललित मोदी ने सुष्मिता सेन की आत्मनिर्भरता और उनकी सफलता की जमकर तारीफ की। उन्होंने साफ किया कि उनके रिश्ते के बीच कभी भी पैसा कोई मुद्दा नहीं था। सुष्मिता को 'गोल्ड डिगर' कहने वालों को जवाब देते हुए मोदी ने कहाः 'सुष्मिता बहुत खूबसूरत और एक बेहद संपन्न महिला हैं। इस दुनिया में मैं जितने भी लोगों को जानता हूँ, उनमें सबसे ज्यादा हीरे सुष्मिता के पास हैं। वह एक बहुत अमीर महिला हैं और उन्होंने यह सब अपनी मेहनत से हासिल किया है। एक समय ऐसा भी था, जब मैं उनके साथ बाहर जाता था तो मुझे किसी भी चीज़ के लिए पैसे नहीं देने पड़ते थे। हर चीज़ का खर्च सुष्मिता ही उठाती थीं। मैं तो बस एक पाला-पोसा बॉयफ्रेंड जैसा था।' ललित मोदी ने आगे मजाकिया और दार्शनिक अंदाज में कहा, 'अगर हम यह कहें कि सुष्मिता 'गोल्ड डिगर' नहीं थीं, बल्कि ललित 'डायमंड डिगर' थे, तो यह गलत नहीं होगा। और वह (सुष्मिता) ही वह हीरा थीं।'

उन्होंने आगे कहा, 'वह किसी से भी कभी कुछ नहीं लेती थीं। इसलिए, जब लोगों ने उन्हें 'गोल्ड डिगर' कहा, तो वह बात पूरी तरह से गलत थी।'

ललित मोदी ने खुलासा किया कि 2022 में जब उन्होंने अपने रिश्ते की घोषणा की थी, तब सुष्मिता सेन उनके साथ ही थीं

ललित मोदी ने उस सोशल मीडिया पोस्ट के बारे में भी खुलकर बात की, जिसके ज़रिए दुनिया को उनके रिश्ते के बारे में पता चला था। उनके मुताबिक, सुष्मिता को इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वह सच में उस पोस्ट को शेयर कर देंगे। उन्होंने बताया, 'मैंने यह सब उनके सामने ही किया था। उन्हें लगा ही नहीं था कि मैं सच में उसे पोस्ट कर दूँगा। हम हवाई जहाज में किसी बात पर बहस कर रहे थे, तभी सुष्मिता ने मुझसे कहा, 'तुम इसे पोस्ट नहीं करोगे।' मैंने हँसते हुए पोस्ट करने वाला बटन दबा दिया।'

बिजनेसमैन ने याद करते हुए बताया कि उस समय वे लंदन वापस लौट रहे थे। उन्होंने कहा, 'जब तक हम लंदन पहुँचे, तब तक तो पूरी दुनिया में हंगामा मच चुका था। लेकिन, इसमें कुछ भी गलत नहीं था। सुष्मिता ने मुझसे कभी भी उस पोस्ट को हटाने के लिए नहीं कहा, और मैंने भी कभी उसे हटाने के बारे में सोचा तक नहीं।' इसके बाद जो हंगामा मचा, उसके बावजूद मोदी ने कहा कि उन्हें इस रिश्ते को पब्लिक करने का कोई पछतावा नहीं है। उन्होंने कहा, 'इससे सच में इंटरनेट पर तहलका मच गया था। कुछ दिनों तक तो ऐसा लगा जैसे हर कोई बस इसी के बारे में बात कर रहा हो। लेकिन हमारी कहानी बहुत खूबसूरत थी और मुझे उसके एक भी पल का कोई पछतावा नहीं है।'

सुष्मिता के बारे में प्यार से बात करते हुए, मोदी ने उन्हें कई तरह से खुद पर असर डालने का श्रेय दिया और कहा कि वह उनकी ज़िंदगी की यादों का एक अहम हिस्सा बनी हुई हैं। मोदी ने कहा, 'सुष्मिता मेरे लिए बहुत खास थीं। आज मैं जो कुछ भी हूँ, उसमें उनका बहुत बड़ा हाथ है।'

अकेले बलूचिस्तान में मई में 71 आतंकी हमले, रिपोर्ट ने खोली पाक की पोल

• इस्लामाबाद, एजेंसी

पाकिस्तान में पिछले महीने आतंकवाद से प्रेरित हिंसा में अप्रैल की तुलना में 27 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है, जिससे देश में आतंकवाद से जुड़े खतरों की व्यापकता का पता चलता है। यह जानकारी एक 'थिंक टैंक' की रिपोर्ट में दी गई है। 'पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी स्टडीज' (पीआईसीएसएस) द्वारा सोमवार को जारी मासिक सुरक्षा आकलन रिपोर्ट के अनुसार, सापेक्ष गिरावट की संक्षिप्त अवधि के बाद मई में उग्रवादी और आतंकी समूहों की सक्रियता फिर से बढ़ गई है।

रिपोर्ट के मुताबिक, मई में पाकिस्तान में 128 आतंकवादी हमले दर्ज किए गए, जबकि अप्रैल में यह संख्या 101 थी, जो 27 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है। इसके अनुसार, मई में 71 नागरिक, 68 सुरक्षाकर्मी और शांति समितियों के छह सदस्य मारे गए, जबकि 147 नागरिक, 35 सुरक्षाकर्मी और शांति समितियों के तीन सदस्य घायल हुए। अप्रैल की तुलना में नागरिकों की मौतों की संख्या 37 से बढ़कर 71 हो गई, जबकि सुरक्षाकर्मियों की मौतों की संख्या 28 से बढ़कर 68 हो गईं।

रिपोर्ट में आत्मघाती हमलों में भी वृद्धि दर्ज की गई है। मई में देश में छह आत्मघाती हमले हुए, जिनमें चार वाहन-आधारित आत्मघाती विस्फोट शामिल थे।इन हमलों में अकेले 34 सुरक्षाकर्मी और नौ नागरिक मारे गए। इसके विपरीत, मार्च और अप्रैल में केवल एक-एक आत्मघाती हमला दर्ज किया गया था, जो आत्मघाती हमलों के उपयोग में बढ़ोतरी का संकेत देता है। रिपोर्ट के अनुसार, मई में सबसे अधिक प्रभावित प्रांत बलूचिस्तान रहा, जहां 71 आतंकवादी हमले दर्ज किए गए, जबकि अप्रैल में यह संख्या 34 थी।

भारत-ऑस्ट्रेलिया रक्षा संबंध होंगे मजबूत! पीएम मोदी के दौरे में रक्षा और समुद्री सुरक्षा पर रहेगा मुख्य फोकस

• सिडनी, एजेंसी

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रणनीतिक और सैन्य साझेदारी आने वाले दिनों में एक नई ऊंचाई छूने जा रही है। ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री एवं रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्लेस ने सोमवार को कहा कि दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग लगातार मजबूत हो रहा है।

उन्होंने साफ किया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की आगामी ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच रक्षा और सुरक्षा संबंध सबसे प्रमुख मुद्दों में शामिल रहेंगे। यह बात रिचर्ड मार्लेस ने नई दिल्ली में आयोजित 'भारत-ऑस्ट्रेलिया रक्षा मंत्रियों के संवाद' के दूसरे संस्करण की सह-अध्यक्षता करने के बाद संवाददाताओं से बातचीत के दौरान कही। इस उच्च स्तरीय बैठक की सह-अध्यक्षता भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उनके ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष रिचर्ड मार्लेस ने की।

पीएम मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा और शिखर वार्ता पर नजर

ऑस्ट्रेलियाई रक्षा मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज की आगामी शिखर वार्ता में रक्षा एवं समुद्री सुरक्षा सहयोग पर विशेष जोर रहेगा।

हिंद-प्रशांत क्षेत्र में बदलते भू-राजनीतिक समीकरणों के बीच दोनों देशों का यह कदम बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। रिचर्ड मार्लेस, उप प्रधानमंत्री एवं रक्षा मंत्री, ऑस्ट्रेलिया के बयान के अनुसार 'भारत और ऑस्ट्रेलिया के रक्षा संबंध लगातार गहरे हो रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की आगामी ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान रक्षा सहयोग हमारी चर्चाओं का एक मुख्य स्तंभ होगा।'

'पिच ब्लैक' अभ्यास में दहाड़ेंगे भारतीय 'राफेल'

इस संवाद के दौरान रक्षा क्षेत्र में एक और बड़ी घोषणा की गई। रिचर्ड मार्लेस ने जानकारी दी कि भारतीय वायुसेना (IAF) अगले महीने ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होने वाले बहुराष्ट्रीय हवाई युद्ध अभ्यास 'पिच ब्लैक' में हिस्सा लेगी।

इस बार भारतीय वायुसेना अपने अत्याधुनिक राफेल लड़ाकू विमानों के साथ इस युद्धाभ्यास में शामिल होगी, जो दोनों देशों की वायुसेनाओं के बीच बढ़ते अंतर-संचालनीयता (Interoperability) और तालमेल को दर्शाता है।

बैठक की मुख्य बातें

द्विपक्षीय संवादः रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रिचर्ड मार्लेस ने नई दिल्ली में रक्षा मंत्रियों के संवाद के दूसरे संस्करण की सह-अध्यक्षता की।

समुद्री सुरक्षा पर जोरः आगामी द्विपक्षीय शिखर वार्ता में समुद्री सुरक्षा और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता पर विशेष फोकस रहेगा।

सैन्य अभ्यासः भारतीय राफेल विमान ऑस्ट्रेलिया में होने वाले प्रतिष्ठित 'पिच ब्लैक' अभ्यास में अपनी ताकत दिखाएंगे।

संक्षिप्त खबरें

मेरे कहने पर नेतन्याहू ने लेबनान पर हमले से सेना वापस बुलाईः ट्रंप

वाशिंगटन। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्होंने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को लेबनान के खिलाफ हमले को रोकने के लिए राजी कर लिया है, जिसके बाद उन्होंने अपने सैनिकों को वापस बुला लिया। ट्रंप ने सोमवार शाम को 'ट्रुथ सोशल' पर यह घोषणा की। ट्रंप का यह बयान ऐसे समय में आया है जब दोनों नेताओं के बीच ''तीखी'' बातचीत की खबरें सामने आ रही थीं। खबरों के अनुसार ट्रंप ने नेतन्याहू से यह भी कहा कि अगर उन्होंने हस्तक्षेप नहीं किया होता तो इजराइल के प्रधानमंत्री आज जेल में होते।

उन्होंने इजराइल के प्रधानमंत्री को उनके लोकप्रिय उपनाम से संबोधित करते हुए कहा, ''आज (सोमवार) मेरी बीबी नेतन्याहू से बातचीत हुई। मैंने उनसे लेबनान के बेरूत में कोई बड़ा हमला न करने का अनुरोध किया। उन्होंने अपनी सेना को वापस बुला लिया। धन्यवाद बीबी।'' ईरान द्वारा लेबनान पर इजराइल के हमलों को लेकर अमेरिका के साथ जारी बातचीत को खत्म करने की धमकी के बाद ट्रंप और नेतन्याहू के बीच फोन पर बातचीत हुई। नेतन्याहू ने कहा था कि अगर हिजबुल्ला इजराइल पर हमले बंद नहीं करता है तो इजराइल बेरूत में ''आतंकी ठिकानों'' पर हमला करेगा।

ट्रंप ने कहा कि उनकी हिजबुल्ला के नेताओं के प्रतिनिधियों से भी बातचीत हुई, जो ''इजराइल और उसके सैनिकों पर गोलीबारी बंद करने'' पर सहमत हुए। उन्होंने कहा, ''मेरी हिजबुल्ला के नेताओं के प्रतिनिधियों से भी बातचीत हुई और वे इजराइल तथा उसके सैनिकों पर गोलीबारी बंद करने पर सहमत हुए। इसी तरह, इजराइल भी उन पर गोलीबारी बंद करने पर सहमत हो गया। देखते हैं यह कब तक चलता है - उम्मीद है कि यह हमेशा के लिए चलेगा।

'ऑपरेशन चेकमेट' के तहत 30 अवैध भारतीय ट्रक चालक गिरफ्तार

वाशिंगटन। अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे और वाणिज्यिक ट्रक चालक के तौर पर काम कर रहे करीब 30 भारतीय नागरिकों को एक बड़े संघीय अभियान के तहत गिरफ्तार किया गया है। इन सभी को जल्द ही अमेरिका से निर्वासित किया जाएगा। यह कार्रवाई अमेरिकी सीमा शुल्क और सीमा सुरक्षा द्वारा चलाए गए 'ऑपरेशन चेकमेट' के तहत की गई है। CBP द्वारा सोमवार को जारी आधिकारिक बयान के अनुसार, एरिजोना में युमा सेक्टर के सीमा गश्त एजेंटों ने 11 से 15 मई के दौरान इस विशेष अभियान को अंजाम दिया। अमेरिकी सीमा शुल्क और सीमा सुरक्षा (सीबीपी) ने सोमवार को एक बयान में बताया कि एरिजोना में युमा सेक्टर के सीमा गश्त एजेंटों ने 11 से 15 मई के दौरान अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे 52 लोगों को 'ऑपरेशन चेकमेट' के तहत गिरफ्तार किया जिनमें से 36 ट्रक चलाते पाए गए। गिरफ्तार किए गए इन अवैध ट्रक चालकों में 30 भारत से हैं जबकि बाकी छह मेक्सिको, अल सल्वाडोर और रूस से हैं। उनके पास कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन और वर्जीनिया जैसे राज्यों के वाणिज्यिक चालक लाइसेंस थे जबकि कुछ के पास किसी भी तरह का चालक लाइसेंस नहीं था।

इनमें से अधिकतर लोगों के पास ऐसे रोजगार प्राधिकरण दस्तावेज थे जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडन के नेतृत्व वाले प्रशासन के दौरान हासिल किए गए थे और अब वैध नहीं हैं। सभी लोगों के खिलाफ संघीय कानून के तहत कार्रवाई की गई है और उन्हें निर्वासित किया जाएगा। 'ऑपरेशन चेकमेट' का उद्देश्य देश में अवैध रूप से रह रहे और वाणिज्यिक मोटर वाहन चला रहे लोगों का पता लगाकर उन्हें गिरफ्तार करना और आव्रजन कानूनों को लागू कर सार्वजनिक सुरक्षा को मजबूत करना है। अमेरिकी सीमा गश्त के युमा सेक्टर के कार्यवाहक मुख्य गश्त एजेंट डस्टिन कॉडल ने कहा, ऑपरेशन चेकमेट समुदायों और सड़कों को ऐसे चालकों से सुरक्षित रखने की हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है जो गैरकानूनी रूप से रहकर वाहन चलाते हैं और सार्वजनिक सुरक्षा के लिए गंभीर जोखिम पैदा करते हैं।''

ट्रंप की सनक

ट्रंप ने फोन पर नेतन्याहू को गलियाया, धमकी देकर कहा-मैं ना होता तो तुम जेल में होते

• वाशिंगटन, एजेंसी

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच फोन पर हुई एक बेहद असाधारण और तीखी बातचीत का खुलासा हुआ है। Axios की एक सनसनीखेज रिपोर्ट के अनुसार, लेबनान में इजरायल के बढ़ते सैन्य अभियान से नाराज राष्ट्रपति ट्रंप ने नेतन्याहू पर जमकर गुस्सा निकाला और बातचीत के दौरान अपशब्दों (गालियों) का भी इस्तेमाल किया। यह टकराव तब हुआ जब वाशिंगटन, ईरान के साथ चल रही अपनी बेहद संवेदनशील कूटनीतिक बातचीत को बचाने की कोशिश कर रहा था, जिसमें इजरायली हमले लगातार बाधा बन रहे थे।

दो अमेरिकी अधिकारियों और इस बातचीत से जुड़े सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ट्रंप, नेतन्याहू की कार्यप्रणाली से इस कदर नाराज थे कि एक समय वह चिल्ला पड़े— 'तुम आखिर कर क्या रहे हो?' एक अमेरिकी अधिकारी ने ट्रंप के कड़े शब्दों का हवाला देते हुए बताया कि उन्होंने नेतन्याहू से कहाः 'तुम साले पागल हो। अगर मैं न होता तो तुम जेल में होते। मैं तुम्हारी जान बचा रहा हूँ। अब हर कोई तुमसे नफरत करता है। इसी वजह से हर कोई इजरायल से नफरत करता है।'

यह टकराव सोमवार को तब और बढ़ गया जब नेतन्याहू और रक्षा मंत्री इजरायल काट्ज ने बेरूत के दाहिये जिले में हिजबुल्लाह के नियंत्रण वाले इलाकों पर हमले का आदेश दिया। उन्होंने इसके पीछे हिजबुल्लाह द्वारा संघर्ष विराम के बार-बार उल्लंघन और इजरायली क्षेत्र पर हमलों का हवाला दिया। इस घोषणा के बाद लेबनान की राजधानी के दक्षिणी इलाकों में रहने वाले लोग बड़े हवाई हमलों के डर से वहां से भागने लगे।

ईरान, जो हिजबुल्लाह का समर्थन करता है, ने चेतावनी दी कि लेबनान में इजरायल के लगातार हमले वॉशिंगटन के साथ चल रही उन बातचीत को पटरी से उतार सकते हैं, जिनका मकसद महीनों के संघर्ष के बाद तनाव कम करना है। ईरानी अधिकारियों ने बार-बार जोर देकर कहा है कि लेबनान में संघर्ष विराम अमेरिका के साथ किसी भी व्यापक समझौते का एक अहम हिस्सा है।

अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि ट्रंप इजरायल की इस दलील को समझते थे कि वह हिजबुल्लाह के रॉकेट और ड्रोन हमलों का जवाब दे रहा है, लेकिन उनका मानना था कि नेतन्याहू इस संघर्ष को जरूरत से ज्यादा बढ़ा रहे हैं। एक अधिकारी ने बताया कि ट्रंप लेबनान में आम नागरिकों की मौत की संख्या से खास तौर पर परेशान थे और उन्होंने हिजबुल्लाह के किसी एक कमांडर को निशाना बनाने के लिए बड़े पैमाने पर किए जा रहे हमलों पर आपत्ति जताई।

इस बातचीत का तुरंत असर होता दिखा। एक इजरायली अधिकारी ने Axios को बताया कि इजरायल का अब बेरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला करने का कोई इरादा नहीं है। बाद में, ट्रंप ने कहा कि उन्होंने नेतन्याहू से बात की है और बेरूत की ओर बढ़ रहे इजरायली सैनिकों को वापस बुला लिया गया है। उन्होंने यह भी दावा किया कि हिज़्बुल्लाह ने बिचौलियों के ज़रिए, इज़रायल पर हमले रोकने पर सहमति जताई है। ट्रंप ने Truth Social पर लिखा, 'मेरी प्रधानमंत्री बीबी नेतन्याहू के साथ बहुत ही सार्थक बातचीत हुई,' और साथ ही यह भी जोड़ा कि 'बेरूत में कोई भी सैनिक नहीं भेजा जाएगा।'

हालाँकि, नेतन्याहू ने इज़रायल की व्यापक सैन्य स्थिति में किसी भी बदलाव का कोई संकेत नहीं दिया। बातचीत के बाद जारी